



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07082020-220959  
CG-DL-E-07082020-220959

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 192]	नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 7, 2020/श्रावण 16, 1942
No. 192]	NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 7, 2020/SRAVANA 16, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय  
(वाणिज्य विभाग)  
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2020

प्राथमिक जांच परिणाम

मामला संख्या सीवीडी-ओआई - 05/2019

**विषय:** इंडोनेशिया से "स्टेनलेस स्टील के फ्लैट उत्पादों" के आयातों के संबंध में सब्सिडीरोधी जांच में प्राथमिक जांच परिणाम।

**फा. सं. 6/16/2019-डीजीटीआर .— क. मामले की पृष्ठभूमि**

समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे बाद में "अधिनियम" कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (सब्सिडीयुक्त वस्तुओं पर प्रतिकारी शुल्क पहचान, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे यहां "नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए:

1. इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलेपमेंट एसोसिएशन (आईएसएसडीए), जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड (जेएसएल), जिंदल स्टेनलेस (हिसार) लिमिटेड और जिंदल स्टेनलेस स्टीलवे लिमिटेड (जेएसएसएल) (जिन्हें यहां आगे "आवेदक" अथवा "घरेलू उद्योग" भी कहा गया है) ने इंडोनेशिया (जिसे यहां आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) से "स्टेनलेस स्टील के फ्लैट उत्पादों" (जिसे यहां आगे "संबद्ध सामान" भी कहा गया है) के आयातों पर प्रतिकारी शुल्क लगाए जाने के लिए अधिनियम और नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन पत्र दायर किया है।

2. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर तथाकथित सब्सिडी की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने तथा सब्सिडीरोधी प्रतिकारी शुल्क की राशि, जो यदि लगायी जाती है और जो घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए नियम 6 के अनुसार संबद्ध जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 18 अक्तूबर, 2019 की अधिसूचना संख्या 6/16/2019-डीजीटीआर द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

### प्रक्रिया

3. प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:
- क. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 6 के उप नियम (5) के अनुसार जांच की शुरुआत की कार्रवाई करने से पूर्व वर्तमान सब्सिडीरोधी आवेदन पत्र की प्राप्ति के संबंध में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।
  - ख. प्राधिकारी ने स्थिति स्पष्ट करने के उद्देश्य से और सब्सिडी तथा प्रतिकारी उपायों से संबंधित करार के अनुच्छेद 13 के अनुसार पारस्परिक रूप से सहमत समाधान निकालने के उद्देश्य से परामर्श हेतु इंडोनेशिया सरकार को आमंत्रित किया। यह परामर्श नई दिल्ली में 23 सितंबर, 2019 को आयोजित किया गया था जिसमें इंडोनेशिया सरकार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
  - ग. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में सब्सिडीरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 18 अक्तूबर, 2020 की सार्वजनिक सूचना जारी की।
  - घ. प्राधिकारी ने संबद्ध देश की सरकार को भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग और आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार अन्य घरेलू उत्पादकों को जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने ज्ञात विचार दें।
  - ङ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 7(3) के अनुसार, ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा संबद्ध देश के दूतावास को आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति उपलब्ध कराई।
  - च. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की प्रति संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नामों और पतों के साथ उन्हें भेजी गई थी।
  - छ. प्राधिकारी ने उन विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के संबंध में संगत तथ्य/सूचना मांगने के लिए इंडोनेशिया सरकार को प्रश्नावली भेजी जहां सरकार द्वारा प्रतिकार योग्य लाभ प्रदान किए जा सकते हैं।
  - ज. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 7(4) के अनुसार संबद्ध देश में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजीं:
    - i. पीटी आईएमआर एआरसी स्टील
    - ii. पीटी बिंटांग एशिया उशाहा
    - iii. पीटी शिंगशान स्टील
  - झ. उत्तर में, संबद्ध देश के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किये:
    - (i) पीटी इंडोनेशिया गुआंग चिंग निकिल एंड स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री
    - (ii) पीटी इंडोनेशिया शिंगशान स्टेनलेस स्टील
    - (iii) पीटी इंडोनेशिया रुइपू निकिल एंड क्रोम अलॉय
    - (iv) पीटी शिंगशान स्टील इंडोनेशिया
    - (v) पीटी सुलावेसी माइनिंग इन्वेस्टमेंट, इंडोनेशिया
    - (vi) पीटी एकासा याड रिसोर्सेस, इंडोनेशिया
    - (vii) पीटी बिंटांगडेलापन मिनरल, इंडोनेशिया
    - (viii) एटरनल शिंगशान ग्रुप लिमिटेड

- (ix) सेलेरिटी एशिया ट्रेड लिमिटेड
- (x) गोल्डन हार्बर इंटरनेशनल पीटीई. लि.
- (xi) हनवा कं. लि.
- (xii) चुआंग इंटरनेशनल डेवलपमेंट लिमिटेड
- (xiii) स्ट्रेटस स्टील्स डीएमसीसी
- (xiv) रेचीर रिसोर्सेस (सिंगापुर) पीटीई. लि.
- (xv) पीटी हनवा इंडोनेशिया
- (xvi) पीटी आईएमआर एआरसी स्टील, इंडोनेशिया
- (xvii) आईएमआर मेटाल्लर्जिकल रिसोर्सेस एजी

ज. जांच की शुरुआत की अधिसूचना के अनुसरण में, संबद्ध देश से उपर्युक्त उत्पादकों/निर्यातकों के अलावा, इंडोनेशिया सरकार ने भी प्रश्नावली के उत्तर दायर किए।

ट. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 7(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाते हुए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक प्रश्नावली भेजी:

- i. एक्युरेट स्टील
- ii. मूनलाइट ट्यूब इंडस्ट्रीज
- iii. अमानत स्टील प्रा. लि.
- iv. नमन स्टील
- v. एमिनोक्स इंटरनेशनल
- vi. नेशनल पेट्रोक्साइड लिमिटेड
- vii. अंकुर एक्सपोर्ट्स
- viii. नवग्रह फास्टनर्स प्रा. लि.
- ix. अनुपम इम्पैक्स
- x. नवग्रह फास्टनर्स प्रा. लि.
- xi. मोनटेक्स स्टेनलेस एंड अलॉयज
- xii. नवपाड स्टील सेंटर
- xiii. अशोक मेटल कारपोरेशन
- xiv. नवयुग मेटल कारपोरेशन
- xv. आश्विन इम्पैक्स
- xvi. नेनावा मेटल कारपोरेशन
- xvii. बी. वी. एस. ओवरसीज
- xviii. नेपट्यून स्टील इम्पैक्स
- xix. बालाजी इम्पैक्स
- xx. एनजी इंडस्ट्रीज
- xxi. बालाजी निर्यात प्राइवेट
- xxii. निकिल इम्पैक्स एलएलपी
- xxiii. भलारिया मेटल क्राफ्ट प्रा. लि.
- xxiv. न्यूमेक्स स्टील्स
- xxv. भारत एक्सपोर्ट्स

- xxvi. ओहसंग इलैक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- xxvii. भव्यदीप इम्पैक्स
- xxviii. ओम गुरुदेव मेटल्स
- xxix. चंचल मेटल एंड ट्यूब
- xxx. पी. पी. इम्पैक्स (इंडिया)
- xxxi. चिराग उद्योग
- xxxii. पैसिफिमेटल ट्रेडिंग कं.
- xxxiii. देवदीप स्टील अलॉयज
- xxxiv. परम इंडस्ट्रीज
- xxxv. धनेरा इम्पैक्स
- xxxvi. पारस इम्पोएक्सपो प्रा. लि.
- xxxvii. धनेरा मेटल सप्लाय कारपोरेशन
- xxxviii. फोनिक्स फाईल्स प्रा. लि.
- xxxix. मिनोक्स मेटल प्राइवेट लिमिटेड
- xl. पोस्को-इंडिया पुणे प्रोसेसिंग सेंटर प्रा. लि.
- xli. डिविन ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड
- xlii. राजेश स्टील
- xliii. फ्लैज फोर्ज इंडिया
- xliv. राजगुरु इंटरप्राइजेज प्रा. लि.
- xliv. फोर्ट इम्पैक्स प्रा. लि.
- xlvi. रमानी स्टील हाउस
- xlvi. गोदरेज एंड बायसी मैनु. कं. लि.
- xlvi. रंदेन इंजीनियरिंग प्रा. लि.
- xlvi. गुडलक मेटल कारपोरेशन
- I. ऋद्धि सिद्धि इम्पैक्स
- li. गुडलक स्टील्स
- lii. वेल्किन इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड
- liii. एच. के. इम्पैक्स प्रा. लि.
- liv. एस एस इम्पैक्स
- lv. हिम इंटरप्राइजेज
- lvi. सनीत स्टीलसा
- lvii. हिंदुस्तान इनोक्स लिमिटेड
- lviii. सरस्वती स्टील इंडिया
- lix. हिंदुस्तान साइरिंग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस लि.
- lx. सेठ आयरन एंड स्टील प्रा. लि.
- lxi. होम जोन मेटल्स प्राइवेट
- lxii. शाह फाईल्स लिमिटेड

- lxiii. होम जोम स्टेनलेस प्राइवेट लिमिटेड
- lxiv. शक्ति पम्प्स इंडिया लिमिटेड
- lxv. हॉरिजोन चट्स प्रा.
- lxvi. श्री आशापुरा स्टील सेंटर
- lxvii. हाइप्रो इंजीनियर्स प्रा. लि.
- lxviii. श्री महावीर स्टील
- lxix. आईजीपी इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
- lxx. श्री रामदेव मेटल मार्ट
- lxxi. इनको स्टील
- lxxii. श्री रामदेव स्टील्स प्रा. लि.
- lxxiii. इनोक्स स्टेनलेस
- lxxiv. श्री स्वंगीया मेटल इंडस्ट्रीज
- lxxv. जे. वाई. इंटरनेशनल
- lxxvi. श्री ट्यूब मैन्यु. कं. प्रा. लि.
- lxxvii. जगदंबा कटलरी प्राइवेट लिमिटेड
- lxxviii. श्री वल्लभ मेटल्स
- lxxix. जैमन मेटालॉयज एलएलपी
- lxxx. श्रीराम हैंडल्स
- lxxxi. जैनेक्स स्टील एंड मेटल
- lxxxii. सिद्धांत स्टील
- lxxxiii. जय लक्ष्मी मेटल कारपोरेशन
- lxxxiv. सिद्धिविनायक स्टील
- lxxxv. जयना स्टील इंडिया
- lxxxvi. सिल्वर स्टील्स
- lxxxvii. जेवेल इम्पैक्स प्रा. लि.
- lxxxviii. स्टेनोक्स अलॉयज प्रा. लि.
- lxxxix. जेएफई शोजी ट्रेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- xc. स्टील इंटरनेशनल महावीर दर्शन
- xc. कमल मेटल कारपोरेशन
- xcii. स्टील लाइन (इंडिया)
- xciii. केशोराम इंडस्ट्रीज
- xciv. स्टील यार्ड ओवरसीज
- xcv. केयूर किचनवेयर
- xcvi. स्ट्राइड इंडस्ट्रीज एलएलपी
- xcvii. किचन एसेंसियल्स
- xcviii. सुची फास्टनर्स प्रा. लि.
- xcix. क्राफ्टवेयर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

- c. सुमन मेटलशॉप  
 ci. कुनाल हाउसवेयर्स प्रा. लि.  
 cii. सनसिटी शीट्स प्रा. लि.  
 ciii. लारसेन एंड टुब्रो लिमिटेड  
 civ. सनसिटी स्ट्रिप्स एंड ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड  
 cv. लुबी इंडस्ट्रीज एलएलपी  
 cvi. सुंदर इम्पैक्स प्रा. लि.  
 cvii. एम. पी. स्टील सेंटर  
 cviii. सुपर इम्पैक्स  
 cix. मैगपी इंटरनेशनल लि.  
 cx. स्वास्तिक इंडस्ट्रीज  
 cxi. महावीर स्टेनलेस स्टील  
 cxii. ट्राइडेंट स्टील  
 cxiii. मार्स हाउसवेयर्स  
 cxiv. उत्तम स्टील अलॉयज प्रा. लि.  
 cxv. मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड  
 cxvi. विशाल स्टील्स  
 cxvii. मैक्सिम ट्यूब्स कंपनी प्रा. लि.  
 cxviii. वीना स्टील इंडस्ट्रीज  
 cxix. मेफेयर इंटरनेशनल  
 cxx. विक्टोरा ऑटो प्रा. लि.  
 cxxi. मेटल वन कारपोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड  
 cxxii. विक्रम मेटल [इंडिया]  
 cxxiii. मिलन स्टील
- ठ. उत्तर में, निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने उत्तर दिया और आयातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए:
- (i) इंडियन कोक एंड पावर प्रा. लि.
- ड. ऊपर उल्लिखित उत्तरदाता निर्यातकों/आयातकों के अलावा, इस जांच प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित पक्षकारों की ओर से कुछ कानूनी अनुरोध प्राप्त हुए हैं:
- (i) पीटी बिटांग एशिया उशाहा (बीएयू), इंडोनेशिया
- ढ. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले में रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों/किए गए अनुरोधों का अगोपनीय रुपांतर उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को इस प्राथमिक जांच परिणाम अधिसूचना में ध्यान में रखा गया है।
- ण. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया था कि वे पिछले तीन वर्षों तथा जांच की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयातों के लेन-देन वार ब्यौरे उपलब्ध कराएं जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गए थे। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा एवं मूल्य का परिकलन करने और लेन-देनों की उचित जांच करने के बाद अपने विश्लेषण के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर विश्वास किया है।
- त. सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत और निर्माण एवं बिक्री लागत के आधार पर क्षति

रहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या सब्सिडी मार्जिन से कम प्रतिकारी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

- थ. इस तथ्यो को ध्यान में रखते हुए कि संबद्ध सामान विभिन्न ग्रेडों/आकारों/रूपों में आयात किए जा रहे हैं, आवेदकों ने क्षति मार्जिन का परिकलन करने के लिए पीसीएन से पीसीएन तुलना करने के उद्देश्य से उत्पाद नियंत्रण संख्याओं (पीसीएन) का प्रस्ताव किया है। प्राधिकारी का दिनांक 03 जुलाई, 2019 की अधिसूचना संख्या 6/12/2019-डीजीटीआर द्वारा शुरू की गई स्टेनलेस स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पादों के आयातों के संबंध में समांतर पाटनरोधी जांच में 14 अगस्त, 2019 की अधिसूचना संख्या 6/12/2019-डीजीटीआर द्वारा प्रकाशित उसी पीसीएन सिद्धांत को अपनाने का प्रस्ताव है।
- द. वर्तमान सब्सिडीरोधी जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 (12 माह) है। क्षति जांच अवधि में अप्रैल, 2015 – मार्च, 2016, अप्रैल, 2016 – मार्च, 2017, अप्रैल, 2017 – मार्च, 2018 की अवधि तथा जांच की अवधि शामिल है।
- ध. वर्तमान जांच में संगत मानी गई सीमा तक, इस जांच प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर प्राधिकारी द्वारा इस प्राथमिक जांच परिणाम में उपयुक्त रूप से विचार किया गया है।
- न. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और उस सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं।
- प. जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने सूचना देने से इंकार किया है अथवा वर्तमान जांच प्रक्रिया के दौरान अन्यथा आवश्यक सूचना नहीं दी है अथवा जांच में काफी बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने उन पक्षकारों को असहयोगी माना है तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्राथमिक जांच परिणाम रिकार्ड किए हैं।
- फ. इस प्राथमिक जांच परिणाम में \*\*\* किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई तथा प्राधिकारी द्वारा नियमावली के तहत मानी गई सूचना दर्शाते हैं।
- ब. संबद्ध के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 70.82 रुपए है।

#### ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. जांच की शुरुआत के स्तर पर, विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया था:

"वर्तमान आवेदन पत्र में विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित को छोड़कर "स्टेनलेस स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पाद" है:

क. ब्लेड स्टील, अथवा वाणिज्यिक रूप से रेजर के उत्पादन में प्रयुक्त रेजर ब्लेड ग्रेड स्टील के रूप में ज्ञात

ख. मौद्रिक सिक्कों के उत्पादन में प्रयुक्त 73269099 के तहत आने वाले कॉइन ब्लैंक।

विचाराधीन उत्पाद का लेन-देन विभिन्न रूपों में किया जा सकता है, यथा कॉइल्स, शीट्स, प्लेट्स, सर्किल्स, स्ट्रिप्स अथवा अन्यथा। इस उत्पाद के सभी रूप विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत हैं। संबद्ध सामान अधिनियम के अध्याय 72 के सीमा शुल्क उप शीर्ष "7219" और "7220" के अंतर्गत आते हैं। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह वर्तमान जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।"

#### ग.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

5. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

- क) वर्तमान आवेदन पत्र में विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित को छोड़कर "स्टेनलेस स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पाद" है:
  - (i) ब्लेड स्टील, अथवा वाणिज्यिक रूप से रेजर के उत्पादन में प्रयुक्त रेजर ब्लेड ग्रेड स्टील के रूप में ज्ञात
  - (ii) मौद्रिक सिक्कों के उत्पादन में प्रयुक्त 73269099 के तहत आने वाले कॉइन ब्लैंक।
- ख) विचाराधीन उत्पाद का लेन-देन विभिन्न रूपों में किया जा सकता है, यथा कॉइल्स, शीट्स, प्लेट्स, सर्किल्स, स्ट्रिप्स अथवा अन्यथा। इस उत्पाद के सभी रूप विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत हैं।

- ग) विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न रूप/प्रकार उत्पाद विशिष्टियों के संदर्भ में अलग-अलग हैं जो उत्पादकों द्वारा विशिष्ट अंतिम अनुप्रयोग को पूरा करने के लिए प्राप्त किए जाते हैं। विचाराधीन उत्पाद व्यापक रूप से निम्नलिखित श्रृंखलाओं में वर्गीकृत किया जाता है:
- 200 सीरीज
  - 300 सीरीज
  - 400 सीरीज
  - डुप्लेक्स
- घ) इन प्रत्येक श्रृंखला के अंतर्गत उत्पाद की कई भिन्न विशिष्टियां और विभिन्न ग्रेडों से नाम दिया जाता है।
- ङ) सामान्यतः यह उत्पाद पहले गरम स्थितियों (हॉट रोलड नामक) में उत्पादित किया जाता है और उसके बाद ठंडी स्थितियों (कोल्ड रोलड नामक) में रोलड किया जाता है। इस उत्पाद में विभिन्न गुणधर्म में सही रासायनिक सम्मिश्रण का लक्ष्य बनाकर और संयंत्र में बाद में प्रसंस्करण कर प्राप्त किया जाता है। संबद्ध देश में उत्पादक और भारत में घरेलू उद्योग के पास उपभोक्ताओं द्वारा वांछित विभिन्न उत्पाद विशिष्टियों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त उत्पादन सुविधाएं हैं।
- च) विचाराधीन उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 72 के सीमा शुल्क उप शीर्ष संख्या 7219 और 7220 के अंतर्गत आता है। तथापि, यह केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच के क्षेत्र पर किसी तरह बाध्यकारी नहीं है। सीमा प्रशुल्क के तहत उत्पाद को निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अलग-अलग वर्णित किया जाता है:
- चौड़ाई – 600 एमएम से कम और अधिक
  - हॉट रोलड से अधिक किया गया हो अथवा न किया गया हो (अर्थात् हॉट रोलड, कोल्ड रोलड आदि)
  - कोल्ड रोलड से अधिक किया गया हो अथवा न किया गया हो
  - रूप – यथा कॉइल्स, शीट्स, प्लेट और सर्किल
  - मोटाई – यथा 14 एमएम से अधिक, 10-14 एमएम, 4.75-10 एमएम, 3-4.75 एमएम, 3 एमएम से कम आदि।
  - क्रोमियम तथा निकिल क्रोमियम एसटेनिटिक प्रकार।
- छ) विचाराधीन उत्पाद सामान्यतः कि.ग्रा. अथवा मी. टन के संदर्भ में व्यक्त निवल भार के अनुसार उत्पादित किया जाता है तथा बेचा जाता है।
- ज) संबद्ध सामानों का प्रयोग विभिन्न प्रकार के उत्पादों, यथा वास्तुकला तथा निर्माण, उपभोक्ता के टिकाऊ सामानों, प्रसंस्करण एवं इंजीनियरी तथा ऑटोमोबाइल रेलवे ट्रांसपोर्ट के विनिर्माण के लिए किया जाता है।
- झ) याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित पीसीएन सिद्धांत अपनाए जाने का प्रस्ताव किया:

1	स्थिति	एचआर, सीआर, एचआरएपी, सीआरएपी
2	ग्रेड	201, 202, 216, 204सीयू, 212-वाईकेके, 253 एमए, जे4, जे5, जे6, जे7, जे8, जेएसएलएयेस, जेएसएलयू, जेटी, 301, 304/एल, 309, 310/एस, 316/एल, 317, 321, 347, 405, 409, 410/एस, 415, 420, 430, 432, 436, 439, 441, 444, 446, डुपलैक्स, 904 एल, सुपर ऑस तथा विभिन्न मानकों के तहत उनके प्रकार
3	रूप	कॉइल, प्लेट, शीट
4	चौड़ाई	600 एमएम से कम चौड़ाई, 600 अथवा उससे अधिक चौड़ाई
5	मोटाई	<0.5 एमएम, =>0.5 एमएम (केवल सीआर/सीआरएपी के लिए)
6	परिष्कृत	ब्लैक, सं. 1 एचआरएपी, सं. 2वी और 2 डी सीआरएपी विशेष (स्कॉच ब्राइट, एचएल, एनएन, सं. 3, सं. 4 आदि), टैम्पर्ड



## ग.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

6. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए तथा प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:  
क) पीटी बिंटॉंग एशिय उशाहा (बीएयू) द्वारा निर्यातित उत्पाद जांच की शुरुआत की सूचना में निर्धारित विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के बाहर पड़ता है।

## ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

7. विचाराधीन उत्पाद से संबंधित मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की निम्नलिखित रूप में जांच की गई और उन्हें हल किया गया।
8. किसी जांच में सबसे पहला कदम विचाराधीन उत्पाद की पहचान करना होता है। विचाराधीन उत्पाद आयातित उत्पाद है जो तथाकथित रूप से घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहा है। वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी), जैसा कि जांच की शुरुआत की अधिसूचना में परिभाषित किया गया है, "स्टेनलेस स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पाद" है। उत्पाद क्षेत्र विशेष रूप से ब्लेड स्टील, अथवा मौद्रिक सिक्के के उत्पादन में प्रयुक्त 73269099 के तहत आने वाले रेजर तथा कॉइन ब्लैंक के उत्पादन में प्रयुक्त वाणिज्यिक रूप से रेजर ब्लेड स्टील के रूप में ज्ञात को अलग करता है। विचाराधीन उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के सीमा शुल्क शीर्ष संख्या 7219 और 7220 के अंतर्गत अध्याय 72 में वर्गीकृत है।
9. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध सामानों का आयात विभिन्न ग्रेडों/आकारों/रूपों में किया जा रहा है। आवेदकों ने क्षति मार्जिन का परिकलन करने के लिए पीसीएन से पीसीएन तुलना करने के उद्देश्य से उत्पाद नियंत्रण संख्याओं (पीसीएन) का प्रस्ताव किया है। प्राधिकारी का दिनांक 03 जुलाई, 2019 की अधिसूचना संख्या 6/12/2019-डीजीटीआर द्वारा शुरू की गई स्टेनलेस स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पादों के आयातों के संबंध में समांतर पाटनरोधी जांच में 14 अगस्त, 2019 की अधिसूचना संख्या 6/12/2019-डीजीटीआर द्वारा प्रकाशित उसी पीसीएन सिद्धांत को अपनाने का प्रस्ताव है।
10. विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में शामिल आधारभूत उत्पादन प्रक्रिया में कच्ची सामग्री, स्क्रैप (अलॉय तथा गैर-अलॉय) और फैरो अलॉय को एक इलैक्ट्रिक आर्क फर्नेस में पिघलाना शामिल होता है जहां शक्तिशाली इलैक्ट्रिक आर्क स्क्रैप तथा अलॉय को पिघलाने के लिए शुरू होते हैं। गर्म वाली प्रक्रिया पुनः तापन भट्टी पर शुरू होती है जहां स्लैबों को स्टेनलेस स्टील ग्रेड के आधार पर 1100 और 1300 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म किया जाता है। हॉट रोल्ड उत्पादों को नरम (अमील्ड) किया जाता है और डिस्केल्ड (एसिड के साथ पिकिल) किया जाता है। हॉट रोल्ड स्टेनलेस स्टील की सेंडजिमर मिलों (जेड मिलों) में कोल्ड रोलिंग होती है जो एचआर स्टील की रोलिंग करके मुलायम, चमकदार परिष्कृत, कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील का उत्पादन करती है। इस उत्पाद का उत्पादन पहले तम स्थिति/रूप में रोलिंग स्लैब द्वारा किया जाता है। इसके बाद इसे बाजार में बेचा जा सकता है अथवा आगे कोल्ड रोल्ड किया जा सकता है। कोल्ड रोल्ड उत्पादों स्क्रैप तथा स्लैब से सीधे ही बनाए जा सकते हैं तथा कोल्ड रोल्ड स्टील विशिष्ट तापमान पर हॉट रोल्ड कॉइलों की रोलिंग करके बनाए जाते हैं।
11. विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग सफेद सामानों, प्रसंस्कृत उपस्करों, डेयरी उपस्करों, रि-रोलिंग, रिएक्टर वेसेल्स, सामग्री सार संभाल उपस्करों, रेलवे, पाइपों और ट्यूबों ऑटोमोटिव संघटकों, रेल गाड़ियों, मेट्रो कोचों, वास्तुशिल्प, भवन और निर्माण, रोल्ड आकार के सेक्शन, औद्योगिक निर्माण आदि के विनिर्माण के लिए किया जाता है।
12. उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दायर किए गए प्रश्नावली के उत्तर और घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना यह दर्शाती है कि उत्पादकों की हॉट रोल्ड तथा कोल्ड रोल्ड, दोनों उत्पादों को उत्पादन करने की प्रवृत्ति है और विशिष्ट अंतिम प्रयोक्ता आवश्यकताओं के अनुकूल होने के लिए व्यापक आकार की रेंज, साइज तथा धात्विक सम्मिश्रणों में इन्हें पेश करते हैं। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग 1650 एमएम से अधिक की चौड़ाई के स्टेनलेस स्टील फ्लैट रोल्ड उत्पादों और 80 एमएम से अधिक मोटाई के स्टेनलेस स्टील के फ्लैट

उत्पादों का उत्पादन नहीं कर रहा है। तदनुसार, "1650 एमएम से अधिक की चौड़ाई के स्टेनलेस स्टील फ्लैट रोल्ड उत्पादों" और "80 एमएम से अधिक मोटाई के स्टेनलेस स्टील के फ्लैट उत्पादों" को अनंतिम रूप से विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किया गया है।

13. समान वस्तु के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि नियमावली के नियम 2(गक) में यह प्रावधान है कि समान वस्तु का अर्थ उस वस्तु से है जो जांच के अधीन वस्तु के समान अथवा एक जैसी है अथवा ऐसी वस्तु न होने पर, कोई अन्य वस्तु, जो यद्यपि पूरी तरह से समान तो नहीं है लेकिन जांच की जा रही वस्तु से काफी मिलती-जुलती विशेषताओं वाली है। रिकार्ड में सूचना के आधार पर प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह मानते हैं कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों और संबद्ध देश से आयातित सामानों में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। ये दोनों भौतिक विशेषताओं, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियों और सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। इस प्रकार, प्राधिकारी अनंतिम रूप से मानते हैं कि आवेदकों द्वारा विनिर्मित उत्पाद संबद्ध देश से भारत में आयात किए जा रहे संबद्ध सामानों की समान वस्तु हैं।

14. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए अनुरोधों और रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी अनंतिम रूप से मानते हैं कि विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित है:

"वर्तमान आवेदन पत्र में विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित को छोड़कर "स्टेनलेस स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पाद" है:

क. ब्लेड स्टील, अथवा वाणिज्यिक रूप से रेजर के उत्पादन में प्रयुक्त रेजर ब्लेड ग्रेड स्टील के रूप में ज्ञात

ख. मौद्रिक सिक्कों के उत्पादन में प्रयुक्त 73269099 के तहत आने वाले कॉइन ब्लैंक।

ग. 1650 एमएम से अधिक चौड़ाई के स्टेनलेस स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पाद।

घ. 80 एमएम से अधिक मोटाई के स्टेनलेस स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पाद।

विचाराधीन उत्पाद का लेन-देन विभिन्न रूपों में किया जा सकता है, यथा कॉइल्स, शीट्स, प्लेट्स, सर्किल्स, स्ट्रिप्स अथवा अन्यथा। इस उत्पाद के सभी रूप विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत हैं। संबद्ध सामान अधिनियम के अध्याय 72 के सीमा शुल्क उप शीर्ष "7219" और "7220" के अंतर्गत आते हैं। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह वर्तमान जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।"

15. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि 1650 एमएम से अधिक चौड़ाई के स्टेनलेस स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पाद को हटाना उसी रूप में अंतिम प्रयोग के लिए आयातकों/ प्रयोक्ताओं द्वारा अधिकृत प्रयोग के मामले में ही लागू होगा। उन्हें हटाना उन मामलों में लागू नहीं होगा जिनमें 1650 एमएम से अधिक चौड़ाई के स्टेनलेस स्टील के आयातित फ्लैट रोल्ड उत्पाद 1650 एमएम से कम की चौड़ाई वाले उत्पादों में बंटे होंगे।

## घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र एवं आधार

### घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

16. घरेलू उद्योग को छोड़कर अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- मैसर्स जिंदल स्टेनलेस (हिसार) लिमिटेड, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड और जिंदल स्टेनलेस स्टीलवे लिमिटेड (जिन्हें यहां आगे सामूहिक रूप से उपर्युक्त जांच में आवेदक उद्योग कहा गया है) सीवीडी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग माने जाने के लिए अपात्र हैं क्योंकि नियम 2(ख) के अंतर्गत प्राधिकारी को आवेदक उद्योग को पात्र घरेलू उद्योग मानने का कोई विवेकाधिकार नहीं है।
- पाटनरोधी नियमावली के विपरीत, सीवीडी नियमावली आवेदक को अपात्र मानती है, यदि उन्होंने खुद अथवा उनके संबद्ध पक्षकारों ने यहां तक कि "अन्य देशों" के संबद्ध सामानों का आयात किया हो।
- आवेदक जिंदल सॉ लिमिटेड और जिंदल क्वालिटी ट्यूबलर लि. से संबद्ध हैं, जैसा कि जिंदल सॉ लिमिटेड और जिंदल क्वालिटी ट्यूबलर लि. की वार्षिक रिपोर्टों से सिद्ध है।

- iv. जिंदल साँ लिमिटेड और जिंदल क्वालिटी ट्यूबलर लि. जांचाधीन अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के आयातक हैं। इस प्रकार, आवेदक संबद्ध सामानों के आयातक से संबद्ध हैं।
- v. पीटी. जिंदल स्टेनलेस इंडोनेशिया ने जांच की अवधि के दौरान हांगकांग में स्थित एक व्यापारी के माध्यम से भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात किया है।
- vi. पीटी. जिंदल स्टेनलेस इंडोनेशिया ने क्षति की अवधि में भी भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात किया है और कानून यह नहीं कहता कि संबद्ध पक्षकार के लेन-देनों की केवल जांच की अवधि के संबंध में जांच की जानी चाहिए। इस प्रकार का निर्वचन कानून के आशय का अवसाद करेगा जो कि आवेदक उद्योग द्वारा किसी हेर-फेर की संभावना को रोकने के लिए जांच की अवधि में आयात प्रतिबंधित नहीं करता।
- vii. जहां तक कि प्राधिकारी मशीनरी के वास्तविक उपयोगी जीवनकाल (एयूएल) तक विगत अवधि पर विचार करते हुए आवर्ती सब्सिडी का परिकलन करते हैं, जो कि जांच की अवधि के बाद है। इस प्रकार, प्राधिकारी के लिए संबंध के बारे में भिन्न निर्वचन अपनाना और केवल जांच की अवधि तक ही परीक्षण प्रतिबंधित करना अनुपयुक्त होगा।

## घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

17. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में जांच प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:
  - i. याचिकाकर्ता कंपनियों का उत्पादन भारतीय उत्पादन के 50 प्रतिशत से अधिक है। तदनुसार, याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा उत्पादन भारतीय उत्पादन में प्रमुख अनुपात रखता है और इसीलिए याचिकाकर्ता सीवीडी नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से "घरेलू उद्योग" हैं।
  - ii. याचिकाकर्ता कंपनियों ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है। याचिकाकर्ता कंपनियां इंडोनेशिया में संबद्ध सामानों के उत्पादक से संबद्ध हैं। तथापि, वह नियम 2(ख) के तहत याचिकाकर्ताओं की पात्रता को प्रभावित नहीं करता।
  - iii. यह आरोप कि जिंदल साँ लि. (जिंदल साँ) और जिंदल क्वालिटी ट्यूबलर लि. (जेक्यूटीएल) जेएसएल और जेएसएचएल से संबद्ध पक्षकार हैं और संबद्ध सामानों के आयातक हैं तथा यह कि पीटी. जिंदल स्टेनलेस, इंडोनेशिया ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों का निर्यात किया है, आधारहीन और वास्तविक रूप से गलत है।
  - iv. घरेलू उत्पादक निर्यातकों अथवा आयातकों से संबद्ध तभी माने जाएंगे, यदि उनमें से एक दूसरे का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण करता हो अथवा वे दोनों तीसरे व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से नियंत्रित किए जाते हों अथवा वे साथ-साथ प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से तीसरे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किए जाते हों।
  - v. किसी उत्पादक को दूसरे उत्पादक को नियंत्रित करना तब माना जाएगा जब पहले वाला कानूनी अथवा प्रचालनात्मक रूप से दूसरे के ऊपर प्रतिरोध अथवा निर्देश लगाने की स्थिति में हो। वर्तमान मामले में कोई भी उल्लिखित स्थिति नहीं है और इस प्रकार यह माना जाना चाहिए कि जेएसएल/जेएसएचएल, जिंदल साँ/जेक्यूटीएल से संबद्ध नहीं है।
  - vi. आवेदक घरेलू उद्योग कानूनी प्रावधानों के अनुसार इन दो कंपनियों को संबद्ध कंपनी नहीं मानता। आवेदक कंपनियों ने अपनी वार्षिक रिपोर्टों में इन दो कंपनियों को अपनी संबद्ध कंपनी के रूप में सूचित नहीं किया है।
  - vii. किसी भी शेयरधारक (निवेश कंपनियों/वित्तीय संस्थाओं को छोड़कर) का एक ओर जेएसएल/जेएसएचएल में और दूसरी ओर जेएसएडब्ल्यू/जेक्यूटीएल ने उसी समय 5 प्रतिशत हिस्सा अथवा बकाया वोटिंग स्टॉक अथवा शेयरों से अधिक का स्वामित्व नहीं है।
  - viii. एक स्वतंत्र निदेशक को छोड़कर, एक ओर जेएसएल के बोर्ड तथा दूसरी ओर जिंदल साँ के बोर्ड के बीच कोई सामान्य निदेशक नहीं है। कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार कि जिंदल साँ और जेएसएल के बीच तथा जेटीक्यूएल तथा जेएसएचएल/जेएसएल के बीच भी कोई सामान्य निदेशक नहीं है और एक ओर

- जेएसएल/जेएसएचएल तथा दूसरी ओर जिंदल साँ/जेक्यूटीएल के बीच कोई सामान्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक नहीं है।
- ix. मताधिकार पर विचार करते हुए, एक सामान्य निदेशक और वह भी एक स्वतंत्र निदेशक की मौजूदगी के तथ्य का अर्थ "नियंत्रण करने की स्थिति में कानूनी तथा प्रचालनात्मक रूप से" नहीं है। एक से अधिक कंपनी में निदेशक के रूप में नियुक्त किए जा रहे स्वतंत्र निदेशक के कई उदाहरण हैं।
  - x. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) के दिशा-निर्देशों में विशेष रूप से यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति सात कंपनियों तक में स्वतंत्र निदेशक हो सकता है। इस प्रकार, यह तर्क कि किसी व्यक्ति के सामान्य स्वतंत्र निदेशक होने के नाते ही वह "नियंत्रण करने की स्थिति में कानूनी तथा प्रचालनात्मक रूप से" हो जाता है और इसीलिए दो कंपनियां संबद्ध हो जाती हैं, त्रुटिपूर्ण है।
  - xi. कोई भी स्वतंत्र निदेशक सख्त कानूनों से शासित होता है और उससे उम्मीद की जाती है कि वह कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आचार संहिता का पालन करे। यह सुनिश्चित करता है कि स्वतंत्र निदेशक किसी ऐसी असंगत बात की अनुमति नहीं देगा जो उसके निर्णय करने में बोर्ड के सामूहिक निर्णय के सहमत होते हुए अथवा अलग होते हुए समग्र रूप में कंपनी के सर्वोच्च हित में उद्देश्यपूर्ण स्वतंत्र निर्णय करने में कमी लाए। अतः स्वतंत्र निदेशक किसी भी कंपनी में रुचि रखने वाला नहीं माना जा सकता।
  - xii. जिंदल साँ और जेएसएचएल/जेएसएल की दैनिक कार्यप्रणाली को उनके निदेशक बोर्ड द्वारा देखा जाता है। निदेशक बोर्ड बहुमत से निर्णय लेते हैं। एक सामान्य निदेशक किसी भी स्थिति में किसी निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकता। आवेदक कंपनियों ने इन कंपनियों को संबद्ध कंपनी के रूप में कभी भी सूचित नहीं किया है और आवेदक कंपनियों की रिपोर्टिंग पर किसी भी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कोई प्रश्न नहीं उठाया गया है।
  - xiii. इस आरोप के संबंध में कि पीटी जिंदल इंडोनेशिया ने क्षति की अवधि में भी भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात किया है, आवेदकों ने कंपनी द्वारा किए गए वैश्विक निर्यातों संबंधी संगत सूचना के साथ पीटी जिंदल स्टेनलेस इंडोनेशिया से एक पत्र प्रस्तुत किया है।
  - xiv. पीटी जिंदल भारत और अन्य देशों से हॉट रोलड स्टेनलेस स्टील उत्पादों का आयात करता है और कोल्ड रोलड स्टेनलेस फ्लैट उत्पादों का उत्पादन करता है जिनकी बिक्री घरेलू तौर पर की जाती है तथा जिनका वैश्विक रूप से निर्यात भी किया जाता है। तथापि, उन्होंने पूरी क्षति अवधि के दौरान भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात नहीं किया है। पीटी जिंदल ने जांच की अवधि के दौरान आवेदक कंपनियों के लिए भारत को केवल "स्क्रेप" का निर्यात किया है जो वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद नहीं है।
  - xv. पीटी जिंदल ने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जांच की अवधि सहित पूरी क्षति अवधि में भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया है। यहां तक कि व्यापारी के माध्यम से एक निर्यात के मामले में सामान विनिर्माता के परिसर से संबद्ध देश को सीधे ही भेजे गए हैं। इस प्रकार, व्यापारी के माध्यम से निर्यात में भी पीटी जिंदल संबंधित देश को सीधे ही सामान भेजता है और उस देश के संबंध में उसे जानकारी है जहां सामान भेजे गए थे। इसे उन बिक्री के ब्यौरों से भी सत्यापित किया जा सकता है जो कि कंपनी द्वारा दिए गए हैं। इस प्रकार यह देखा जाएगा कि आवेदकों की संबद्ध कंपनी, पीटी जिंदल स्टेनलेस, इंडोनेशिया द्वारा भारत को विचाराधीन उत्पाद के कोई निर्यात नहीं हैं।
  - xvi. इस आरोप के संबंध में कि पीटी जिंदल इंडोनेशिया ने क्षति की अवधि में भी भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात किया है क्योंकि प्राधिकारी मशीनों के वास्तविक उपयोगी जीवनकाल (एयूएल) तक की विगत अवधि में ली गई आयातित सब्सिडी का परिकलन करते हैं जो कि जांच की अवधि के बाद का है, पात्रता का निर्णय लेने के लिए केवल जांच की अवधि के दौरान आयातों/ निर्यातों पर विचार करना निर्दिष्ट प्राधिकारी की सतत परिपाटी है। पीटी जिंदल स्टेनलेस ने यद्यपि पूरी क्षति अवधि में संबद्ध सामानों का निर्यात नहीं किया है।

### घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

18. दिनांक 02.02.2020 की अधिसूचना 10/2020-सीमा शुल्क (एनटी) द्वारा संशोधन से पूर्व नियमावली के नियम 2(ख) में निम्नलिखित प्रावधान है:

“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित सब्सिडीयुक्त वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।”

19. दिनांक 02.02.2020 की अधिसूचना 10/2020-सीमा शुल्क (एनटी) द्वारा संशोधन के बाद घरेलू उद्योग की परिभाषा निम्नलिखित रूप में पठित है:

“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समग्र रूप से समान वस्तु के विनिर्माण में लगे हुए हैं अथवा जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित सब्सिडीयुक्त वस्तु अथवा अन्य देशों से समान वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं।”

"व्याख्या – इस खंड के प्रयोजन के लिए उत्पादक केवल तभी निर्यातकों अथवा आयातकों से संबद्ध माने जाएंगे यदि-

(क) उनमें से एक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे का नियंत्रण करता हो; अथवा

(ख) वो दोनों प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे व्यक्ति से नियंत्रित हों; अथवा

(ग) वे साथ-साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस शर्त पर तीसरे व्यक्ति को नियंत्रित करते हों कि यह विश्वास करने अथवा संदेह करने का आधार है कि संबंध का प्रभाव ऐसा है जिससे उत्पादकों को गैर संबद्ध उत्पादकों से भिन्न व्यवहार हो।”

**टिप्पणी:** इस स्पष्टीकरण के प्रयोजन के लिए किसी उत्पादक तब दूसरे उत्पादक को नियंत्रित करना माना जाएगा जब पहले वाला कानूनी अथवा प्रचालनात्मक रूप से दूसरे के ऊपर प्रतिरोध अथवा निर्देश करने की स्थिति में हो।

20. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि आवेदक कंपनियां अपात्र घरेलू उद्योग हैं क्योंकि उनके संबद्ध पक्षकार यथा जिंदल साँ लि. (जिंदल साँ) और जिंदल क्वालिटी ट्यूबलर लि. (जेक्यूटीएल) हैं जिन्होंने संबद्ध सामानों का आयात किया है। यह भी तर्क दिया गया है कि इंडोनेशिया में आवेदकों के दूसरे संबद्ध पक्षकार पीटी जिंदल, इंडोनेशिया ने व्यापारी के माध्यम से हांगकांग से भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात किया है।
21. जहां तक जिंदल साँ और जेक्यूटीएल की वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर आवेदक कंपनियों और जिंदल साँ तथा जेक्यूटीएल के बीच संबंध के बारे में तर्क का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि वार्षिक रिपोर्ट (रिपोर्टें) कंपनियों के बीच संबंध के मुद्दे का निर्णय लेने के लिए निष्कर्षात्मक कारक नहीं हो सकता। इस विशेष मामले में, जिंदल साँ और जेक्यूटीएल को संबद्ध कंपनियां होने का दावा किया गया है। जिंदल साँ ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कुल 54 कंपनियों की सूची दी है जिसमें उसके प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक तथा उनके संबंधियों का महत्वपूर्ण प्रभाग है और उनमें आवेदक कंपनियों के नाम दिए गए हैं। आवेदक कंपनियां अपनी वार्षिक रिपोर्टों में और जेक्यूटीएल को संबद्ध पक्षकार नहीं मानते।
22. प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमावली के अनुसार उत्पादकों को निर्यातकों अथवा आयातकों से संबद्ध केवल तभी माना जाएगा यदि (क) उनमें से एक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे का नियंत्रण करता हो, अथवा (ख) वो दोनों प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे व्यक्ति से नियंत्रित हों अथवा (ग) वे साथ-साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस शर्त पर तीसरे व्यक्ति को नियंत्रित करते हों कि यह विश्वास करने अथवा संदेह करने का आधार है कि संबंध का प्रभाव ऐसा है जिससे उत्पादकों को गैर संबद्ध उत्पादकों से भिन्न व्यवहार हो। इसके अतिरिक्त, किसी उत्पादक तब दूसरे उत्पादक को नियंत्रित करना माना जाएगा जब पहले वाला कानूनी अथवा प्रचालनात्मक रूप से दूसरे के ऊपर प्रतिरोध अथवा निर्देश करने की स्थिति में हो। अतः प्राधिकारी ने आवेदक कंपनियों (प्रथम पक्षकार) के जिंदल साँ लि. (जिंदल साँ) और जिंदल क्वालिटी ट्यूबलर लि. (द्वितीय पक्षकार) के साथ संबंध के मुद्दे की जांच की है।

23. हितबद्ध पक्षकार ने प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार के बीच संबंध का आरोप लगाते हुए यह सिद्ध नहीं किया है कि एक पक्षकार प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे पक्षकार पर नियंत्रण करता है अथवा वे दोनों प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे व्यक्ति/पक्षकार द्वारा नियंत्रित होते हैं अथवा एक साथ वे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से तीसरे व्यक्ति/पक्षकार पर नियंत्रण करते हैं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि यह नहीं दर्शाया गया है कि यह विश्वास करने का अथवा संदेह करने का कोई आधार है कि तथाकथित संबंध का प्रभाव ऐसा है कि प्रथम पक्षकार दूसरे संबद्ध उत्पादकों से भिन्न रूप में व्यवहार करें।
24. प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा यह दर्शाते हुए दी गई सूचना को ध्यान में रखा है कि (क) किसी भी शेयरधारक (निवेश कंपनियों/वित्तीय संस्थाओं को छोड़कर) का प्रथम तथा द्वितीय पक्षकार में एक ही समय 5 प्रतिशत का स्वामित्व अथवा उससे अधिक का वोटिंग स्टॉक अथवा शेयर हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक कंपनियों और जेएसडब्ल्यू तथा जेक्यूटीएल के संबंध के बारे में प्रमुख घटक कानूनी अथवा प्रचालनात्मक (नियंत्रण) है। प्राधिकारी यह चाहते हैं कि किसी भी शेयरधारक (निवेश कंपनियों/वित्तीय संस्थाओं को छोड़कर) का प्रथम तथा द्वितीय पक्षकार में एक ही समय 5 प्रतिशत का स्वामित्व अथवा उससे अधिक का वोटिंग स्टॉक अथवा शेयर नहीं हैं। केवल शेयरधारिता से कानूनी अथवा प्रचालनात्मक नियंत्रण करना नहीं बन जाता जब तक कि शेयरधारिता बड़ी मात्रा में सिद्ध न हो जाए और उससे दूसरे पक्षकार पर कानूनी अथवा प्रचालनात्मक नियंत्रण न बन जाए। (ख) प्रथम और द्वितीय पक्षकार के बीच कोई सामान्य प्रमुख संबंधीय कार्मिक नहीं हैं। (ग) प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार की दैनिक कार्यप्रणाली संबंधित कंपनियों के निदेशक बोर्ड के समग्र अधीक्षण तथा नियंत्रण के अध्येक्षित संचालित की जाती हों। (घ) आवेदक कंपनियों ने तथाकथित संबद्ध कंपनियों को अपनी वार्षिक रिपोर्टों में अपनी संबद्ध कंपनी सूचित नहीं किया है। यह भी देखा जाता है कि जेएसएचएल और जिंदल साँ के बोर्डों में केवल एक सामान्य स्वतंत्र निदेशक अर्थात् श्री गिरीश शर्मा हैं।
25. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) तथा सेबी (सूचियन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम का प्रावधान 16 कंपनी में स्वतंत्र निदेशक (निदेशकों) की नियुक्ति के मुद्दे से संबंधित है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जिस व्यक्ति का कंपनी अथवा किसी संबद्ध अथवा सहायक कंपनी के संबंधों अथवा शेयरधारकों के साथ कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध अथवा हित न हो, वही कंपनी में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति का प्रयोजन कंपनी में निर्णय करने में उद्देश्यपरकता तथा उचित भूमिका सुनिश्चित करना है और उसे ऐसी किसी असंगत बात की अनुमति नहीं देनी होती है जिससे बोर्ड के सामूहिक निर्णय के अपने निर्णय करने में सहमत अथवा असहमत होते समय समग्र रूप से कंपनी के शीर्ष हित में उद्देश्यपर स्वतंत्र निर्णय लेने में कोई कमी आए। अतः स्वतंत्र निदेशक किसी भी कंपनी में रुचि लेने वाला नहीं माना जा सकता। यहां तक कि अन्यथा निदेशक बोर्ड बहुमत से निर्णय लेता है और एक सामान्य स्वतंत्र निदेशक किसी भी स्थिति में दो कंपनियों में किसी निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकता और कानूनी अथवा प्रचालनात्मक रूप से दूसरी कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए कंपनी को ले जाने की स्थिति में नहीं माना जा सकता और न ही वह सामान्य स्वतंत्र निदेशक दूसरे को निर्देश देने की स्थिति में हो सकता है।
26. रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर, यह नोट किया जाता है कि न तो आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जिंदल साँ और जेक्यूटीएल का नियंत्रण करते हैं और न ही वे एक साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे पक्षकार अथवा कंपनी द्वारा नियंत्रित होते हैं और न ही वे एक साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से तीसरे पक्षकार/कंपनी का नियंत्रण करते हैं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि यह सिद्ध नहीं किया गया है कि इनमें से कोई भी पक्षकार कानूनी अथवा प्रचालनात्मक रूप से तीसरे पक्षकार पर प्रतिरोध जताने अथवा निर्देश देने की स्थिति में है। उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी नियमावली के अभिप्राय से जिंदल साँ लि. और जिंदल क्वालिटी ट्यूबलर लि. को आवेदक कंपनियों के संबद्ध पक्षकार नहीं मानते हैं।
27. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि पीटी जिंदल स्टेनलेस, इंडोनेशिया ने हांगकांग में स्थित एक व्यापारी के माध्यम से भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात किया है, यह नोट किया जाता है कि पीटी जिंदल स्टेनलेस, इंडोनेशिया ने कुल वैश्विक बिक्री के अपने बीजक दर बीजक ब्यौरे प्रस्तुत किए हैं जो यह दर्शाते हैं कि पूरी क्षति की अवधि के दौरान इंडोनेशिया से भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात नहीं किया गया है। यह देखा जाता है कि भारत को केवल "स्क्रेप" का निर्यात किया गया है जो विचाराधीन उत्पाद नहीं है। इस प्रकार, हितबद्ध पक्षकारों का दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक संबद्ध सामानों के किसी आयातक अथवा निर्यातक से संबद्ध नहीं हैं। यह भी नोट किया जाता है कि रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य

यह दर्शाते हैं कि आवेदकों ने संबद्ध सामानों का आयात भी नहीं किया है। यह भी नोट किया जाता है कि आवेदकों का उत्पादन भारतीय उत्पादन के 50 प्रतिशत से अधिक है।

28. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी तदनुसार नोट करते हैं कि आवेदकों का भारत में संबद्ध सामानों के उत्पादन का भारी अनुपात है और आधार की अपेक्षाएं पूरी करते हैं तथा सीवीडी नियमावली के नियम 2(ख) और 6(3) के अनुसार घरेलू उद्योग हैं।

### **ड. गोपनीयता से संबंधित मुद्दे**

#### **ड.1 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध**

29. गोपनीयता के मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. आवेदक ने सीवीडी नियमावली के नियम 8 के अनुसार आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर में पूरी अनिवार्य सूचना प्रकट की है।

#### **ड.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध**

30. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने सूचना की गोपनीयता के संबंध में कोई टिप्पणी दायर नहीं की है।

#### **ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच**

31. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, सीवीडी नियमावली के नियम 8 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

- (2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

- (3) उप नियम (2) में निहित किसी बात को होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि गोपनीयता के लिए अनुरोध न्यायसंगत नहीं अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा इसको सामान्य तौर पर अथवा संक्षिप्त रूप में उसे प्रकट करने के लिए अनिच्छुक हो, तो ऐसी सूचना की उपेक्षा की जा सकती है।

32. प्राधिकारी ने निरीक्षण के लिए विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रूपांतर से युक्त सार्वजनिक फाइल के माध्यम से सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया।

33. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और उस सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं। प्राधिकारी ने सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपनी व्यापार संबंधी संवेदनशील सूचना को गोपनीय होने का दावा किया है।

### **च. सन्सिडी तथा सन्सिडी मार्जिन का निर्धारण**

34. घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका में वर्तमान जांच शुरू करने के लिए संबद्ध देश में प्रतिकारी सन्सिडी की मौजूदगी का प्रथम दृष्टया साक्ष्य दिया गया। इंडोनेशिया सरकार को परामर्श के लिए आमंत्रित किया गया था जो नई दिल्ली में 23 सितंबर, 2019 को आयोजित किया गया था। इंडोनेशिया के उत्पादकों और निर्यातकों

को सलाह दी गई थी कि वे प्रश्नावली के उत्तर दायर करें और उन्हें उन सब्सिडियों, यदि कोई हैं, की मौजूदगी तथा मात्रा का उपयुक्त निर्धारण करने के लिए तथाकथित सब्सिडी कार्यक्रम की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव के संबंध में सत्यापनीय साक्ष्य प्रदान करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था।

35. इंडोनेशिया सरकार सहित इंडोनेशिया के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं:

- i. पीटी इंडोनेशिया गुआंग चिंग निकिल एंड स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री
  - ii. पीटी इंडोनेशिया शिंगशान स्टेनलेस स्टील
  - iii. पीटी इंडोनेशिया रुइपू निकिल एंड क्रोम अलॉय
  - iv. पीटी शिंगशान स्टील, इंडोनेशिया
  - v. पीटी सुलावेसी माइनिंग इन्वेस्टमेंट, इंडोनेशिया
  - vi. पीटी एकासा याड रिसोर्सेस, इंडोनेशिया
  - vii. पीटी बिटांगडेलापम मिनरल, इंडोनेशिया
  - viii. एटरनल शिंगशान ग्रुप लिमिटेड
  - ix. सेलेरिटी एशिया ट्रेड लिमिटेड
  - x. गोल्डन हार्बर इंटरनेशनल पीटीई. लि.
  - xi. हनवा कं. लि.
  - xii. स्कूचांग इंटरनेशनल डेवलपमेंट लिमिटेड
  - xiii. स्ट्रेटस स्टील्स डीएमसीसी
  - xiv. रेचीर रिसोर्सेस (सिंगापुर) पीटीई. लि.
  - xv. पीटी हनवा इंडोनेशिया
  - xvi. पीटी आईएमआर एआरसी स्टील, इंडोनेशिया
  - xvii. आईएमआर मेटालर्जिकल रिसोर्सेस एजी
- आरोपित सब्सिडी कार्यक्रमों का सामान्य अवलोकन

#### च.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

- (i) घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि इंडोनेशिया सरकार संबद्ध सामानों के अपने उत्पादकों/निर्यातकों को प्रतिकारी सब्सिडी प्रदान कर रहा है और कानून तथा नीतिगत दस्तावेजों के अनुसार उन सब्सिडी योजनाओं की मौजूदगी का प्रथम दृष्टया साक्ष्य दिया है। तदनुसार, घरेलू उद्योग ने एएससीएम और भारतीय नियमावली के अभिप्राय से इंडोनेशिया में कतिपय प्रतिकारी सब्सिडी योजनाओं की मौजूदगी अभिज्ञात की।
- (ii) याचिकाकर्ताओं ने यह अनुरोध किया है कि इंडोनेशिया में संबद्ध सामानों के उत्पादक/निर्यातक कार्रवाईगत सब्सिडी से लाभान्वित हुए हैं। इंडोनेशिया सरकार ने कई कार्यक्रम बना रखे हैं। याचिकाकर्ताओं ने परिपत्रों, अधिसूचनाओं, विनियमों, कानूनों, परिपाटी रिपोर्टों, निजी रिपोर्टों, अनुच्छेदों, डब्ल्यूटीओ अधिसूचनाओं, वार्षिक रिपोर्टों आदि के रूप में, कानूनी अधिसूचनाओं जैसे दस्तावेजों पर विचार किया है। याचिकाकर्ताओं ने विभिन्न सब्सिडी कार्यक्रमों के संबंध में विस्तृत सूचना दी है। याचिकाकर्ता ने यह भी अनुरोध किया है कि निम्नलिखित सब्सिडी कार्यक्रम संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत काफी कम करते हैं।
- (iii) इंडोनेशिया सरकार के कार्यक्रमों में निम्नलिखित कारणों से सब्सिडी है:
  - सरकार अथवा सार्वजनिक निकाय द्वारा वित्तीय अंशदान है जिसमें सरकारी परिपाटी में निधियों का सीधा अंतरण (उदाहरणार्थ अनुदान, ऋण तथा इक्विटी निवेश), सरकारी राजस्व जिसे छोड़ दिया जाता है अथवा एकत्रित नहीं किया जाता है (उदाहरणार्थ राजकोषीय प्रोत्साहन, यथा कर साख), सरकार द्वारा दिए जाने वाले सामान अथवा पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर सामान्य अवसंरचना को छोड़कर सेवाएं, अथवा पर्याप्त पारिश्रमिक से अधिक पर सामानों की खरीद शामिल है।



- इससे विचाराधीन उत्पाद के इंडोनेशियाई उत्पादकों/निर्यातकों को लाभ प्रदान किया जाता है; और
  - यह कार्यक्रम भारतीय सीवीडी नियमावली और एएससीएम के अभिप्राय से विशिष्ट है।
- (iv) संगत इंडोनेशियाई कानून एवं विनियम, परिपत्रों, अधिसूचनाओं, विनियमों, कानूनों, सरकारी रिपोर्टों, निजी रिपोर्टों, अनुच्छेदों, डब्ल्यूटीओ अधिसूचनाओं, वार्षिक रिपोर्टों के रूप में कानूनी अधिसूचनाएं इंडोनेशिया में प्रतिकारी सब्सिडी कार्यक्रमों की मौजूदगी का पर्याप्त साक्ष्य हैं। ये साक्ष्य इंडोनेशिया सरकार तथा इंडोनेशिया में ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों को याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए थे।
- (v) कर प्रोत्साहन, ऋण, ऋण पुनर्निर्माण, शुल्क वापसी और तदर्थ सब्सिडी जैसे विभिन्न शीर्षों के तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा अभिज्ञात विभिन्न प्रतिकार योग्य सब्सिडियों की सूची निम्नलिखित है जो इंडोनेशिया सरकार द्वारा उत्पादकों/ निर्यातकों को दी गई है:

क्र. सं.	कार्यक्रम सं.	योजनाएं
1.	कार्यक्रम सं. 1	विद्युत के लिए कोयला कीमत का निर्धारण
2.	कार्यक्रम सं. 2	निर्यात के लिए न्यूनतम मूल्य वर्धन
3.	कार्यक्रम सं. 3	खनिज, धातु तथा कोयला के लिए निर्धारण कीमत
4.	कार्यक्रम सं. 4	घरेलू बाजार दायित्व (डीएमओ) योजना
5.	कार्यक्रम सं. 5	निर्यात ऋण बीमा/हानियों की प्रतिपूर्ति
6.	कार्यक्रम सं. 6	निर्यात ऋण गारंटी
7.	कार्यक्रम सं. 7	आय कर की कमी
8.	कार्यक्रम सं. 8	कर अवकाश
9.	कार्यक्रम सं. 9	इंडोनेशिया एक्विजिशन से निर्यात वित्तपोषण
10.	कार्यक्रम सं. 10	आयात शुल्क पर छूट
11.	कार्यक्रम सं. 11	आयात शुल्क वापसी
12.	कार्यक्रम सं. 13	निवल कर योग्य आय की कटौती
13.	कार्यक्रम सं. 14	हानियों को अग्रेणित करना
14.	कार्यक्रम सं. 15	आयात शुल्क को बाद के लिए स्थगित करना
15.	कार्यक्रम सं. 16	उत्पादन प्रयोजन के लिए कच्ची सामग्री तथा सहायक सामानों पर शुल्क की छूट
16.	कार्यक्रम सं. 17	आयातों पर आय कर से छूट
17.	कार्यक्रम सं. 18	एसईजेड में निवेश करने आये निवेशकों के लिए कटौती
18.	कार्यक्रम सं. 19	अग्रणी उद्योग स्तर
19.	कार्यक्रम सं. 21	भूमि कर में कटौती
20.	कार्यक्रम सं. 23	वैट की वापसी

- vi. याचिकाकर्ता यह भी अनुरोध करते हैं कि आर-पार के स्वामित्व वाले संबद्धों सहित उनके संबद्धों द्वारा किसी भी रूप में प्राप्त लाभों को ध्यान में रखते हुए सब्सिडी पर भी विचार किया जाना अपेक्षित है। प्रतिकारी सब्सिडी की मौजूदगी की यदि संबद्ध कंपनियों द्वारा ऊपरी स्तर के उत्पादों की आपूर्ति की जाती है तो ऊपरी स्तर के उत्पाद में प्रतिकारी सब्सिडी के संबंध में जांच की जानी अपेक्षित है।
- vii. चूंकि इन कुछ योजनाओं के तहत लाभ अनावर्ती हैं, अतः प्रतिकारी सब्सिडी की मौजूदगी की एयूएल (औसत उपयोगी जीवनकाल) में जांच किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार, यदि कोई अनावर्ती सब्सिडी वापस भी ली गई हो अथवा प्रस्तावित जांच की अवधि में प्राप्त न की गई हो तो निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे वहां तक उसकी जांच करें जहां तक यह सिद्ध हो कि इस योजना के तहत लाभ अनावर्ती था।

- viii. याचिकाकर्ता की कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील के उत्पादन और बिक्री में लगी एक अनुबंधित कंपनी है। यह कंपनी परिसंपत्तियों के एयूएल के रूप में 16 वर्षों से है। इस आधार पर याचिकाकर्ता अनुरोध करते हैं कि प्राधिकारी कृपया परिसंपत्तियों के जीवनकाल के रूप में 16 वर्षों पर विचार करें।

## च.2 परिकलन सिद्धांत

36. एएससीएम के अनुच्छेद 14 में अनुच्छेद 1 के पैरा 1 के अनुसरण में प्राप्तकर्ता को प्रदत्त लाभ के परिकलन के लिए दिशा-निर्देशों तथा सिद्धांत का प्रावधान है और उसमें यह भी प्रावधान है कि प्राप्तकर्ता को लाभ का परिकलन करने के लिए जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रयुक्त कोई भी पद्धति पारदर्शी और पर्याप्त रूप से स्पष्ट होगी। इसके अतिरिक्त, प्राप्तकर्ता को लाभ का परिकलन करने के लिए जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रयुक्त कोई भी पद्धति उनके राष्ट्रीय कानून अथवा संबंधित सदस्य के कार्यान्वयन विनियमों में दी जाएगी और प्रत्येक प्रकरण विशेष में उसका अनुप्रयोग पारदर्शी तथा पर्याप्त रूप से स्पष्ट होगा। आवश्यकता के अनुसार, सीमा प्रशुल्क (सब्सिडीयुक्त वस्तुओं पर प्रतिकारी शुल्क पहचान, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 में सब्सिडीकरण की मात्रा के निर्धारण के लिए सिद्धांत निर्धारित है। इस जांच में निर्धारण इन दिशा-निर्देशों के अनुसार है।

## च.3 याचिकाकर्ताओं द्वारा आरोपित सब्सिडी कार्यक्रमों की जांच

### (i) कार्यक्रम सं. 1: विद्युत के लिए कोयले की कीमत का निर्धारण

#### क. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

37. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि इंडोनेशिया सरकार कोयले के लिए अधिकतम बिक्री कीमत की सीमा निर्धारित करती है। विद्युत के लिए कोयले की बिक्री कीमत पर प्रति मी. टन 70 अमेरिकी डॉलर निर्धारित है। कोयले के उत्पादन में लगी किसी भी कंपनी के लिए यह अपेक्षित है कि वह अपने कानूनी स्तर को ध्यान में न रखते हुए इंडोनेशिया सरकार द्वारा जारी डिक्री को अपनाते हुए उस कोयले की बिक्री करे। कोयला विद्युत उत्पादन के प्रयोजन के लिए कोयले पर अधिकतम कीमत सीमा रखकर संबद्ध सामानों के घरेलू उत्पादकों को सस्ती दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

#### ख. इंडोनेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

38. इंडोनेशिया सरकार सार्वजनिक विद्युत के लिए कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 70 अमेरिकी डॉलर/मी. पर सार्वजनिक विद्युत के लिए कोयले की बिक्री हेतु निर्धारित कीमत तय करती है। "सार्वजनिक" समग्र रूप से लोगों की खपत के लिए विद्युत का विपणन दर्शाता है। इस प्रकार, निर्धारित कीमत अपनी खपत के लिए निजी स्वामित्व वाले विद्युत संयंत्रों को कोयले की बिक्री के लिए लागू नहीं है।
39. कोयले के लिए निर्धारित कीमत केवल 2018 और 2019 की अवधियों के लिए लागू होती है। विनियम में अधिकतम बिक्री मात्रा भी निर्धारित है जो निर्धारण वार्षिक रूप से 100 मिलियन मी. टन कोयला पर लागू होता है। कोई आवेदन पत्र प्रक्रिया लागू नहीं की जाती है। इस योजना में उत्तरदाता कंपनियों को कोई सहायता का प्रावधान नहीं है।
40. निर्यातकों ने अनुरोध किया कि उन्होंने इस योजना के तहत कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है क्योंकि यह योजना उस विद्युत के लिए कोयले की कीमतों पर भी लागू होती है जिसकी आपूर्ति जनहित में की जाती है। चूंकि वे विद्युत की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं, अतः यह योजना लागू नहीं है। वे अंतरराष्ट्रीय कोयला निर्धारण दर के आधार पर कोयले की खरीद कर रहे हैं।

### (ii) कार्यक्रम सं. 2: निर्यात तथा घरेलू बाजार दायित्व के लिए न्यूनतम मूल्य वर्धन

#### क. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

41. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि इंडोनेशियाई सरकार सुनिश्चित करती है कि खनिज तथा धातु के निचले स्तर के उद्योगों के लिए कच्ची सामग्री की प्रचुर आपूर्ति हो। यह (i) बिना प्रसंस्करण और परिष्करण के खनिज अयस्क तथा उसके संकेंद्रणों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर, (ii) प्रसंस्कृत एवं परिष्कृत खनिज तथा धातुओं पर

निर्यात कर की बहुत उच्च दर लगाकर, और (iii) कोयले की आपूर्ति की गारंटी देकर जो कि घरेलू मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक है, घरेलू बाजार दायित्व सृजित कर किया जाता है।

42. खनन कंपनियों को घरेलू उपभोक्ताओं को अपने खनिज/कोयला उत्पादन के बिक्री कर डीएमओ की अपेक्षाओं का अनुपालन करना होता है। यह मुख्य रूप से खनिज/कोयले का अपने इनपुट में प्रयोग करने वाले व्यापार को दिया जाता है। निर्यात को शुल्क/ प्रतिबंधों तथा अनिवार्य घरेलू बाजार बिक्री के अध्यक्षीन रखकर सरकार घरेलू बाजार में खनिजों/कोयले की कीमतों का कृत्रिम रूप से न्यूनीकरण कर रही है जो उन्हें कम कीमत पर खरीदने के लिए इनपुट के रूप में प्रयोग करने वाले निचले स्तर के उद्योगों को अनुमति देती है।

**ख. इंडोनेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध**

43. इंडोनेशिया सरकार ने 2010 के सरकारी विनियम संख्या 1 के चौथे संशोधन के रूप में 2017 का सरकारी विनियम संख्या 1 जारी किया जिसमें खनन लाइसेंसधारकों को देश में ही प्रसंस्करण करना अपेक्षित होता है ताकि खनिजों और कोयला उत्पादों का मूल्य बढ़ाया जा सके और खनन क्षेत्रों में निवेश को गति दी जा सके। इंडोनेशिया सरकार खनिजों और कोयला उत्पादों के निर्यात के अधिकार को भी बनाए रखती है। खनिज उत्पाद ऊर्जा तथा खनिज संसाधन मंत्रालय के 2018 के विनियम संख्या 25 के तहत विनियमित प्रसंस्करण अपेक्षा का न्यूनतम स्तर पूरा करने पर ही निर्यात किए जाने की अनुमति दी जाती है। कोयला उत्पादों के निर्यात के लिए प्रसंस्करण अपेक्षा का कोई न्यूनतम स्तर नहीं है। इस कार्यक्रम में उत्तरदाता कंपनियों द्वारा कोई सहायता/ लाभ प्राप्त नहीं किया गया था।
44. यह बताने का कोई आधार नहीं है कि सामान्य रूप से अथवा इस विशेष मामले में ऐसे प्रतिबंध लगाने से अनिवार्य रूप से बाजार स्तर में कीमतों में गिरावट आएगी। यह नोट करना भी महत्वपूर्ण है कि निर्यात कर लगाना राज्य का हस्तक्षेप नहीं कहा जा सकता जिसके परिणामस्वरूप बाजार का ह्रास हो रहा है। निर्यात कर लगाना पूर्णतया वैध है और जीएटीटी के अनुच्छेद XX(छ) और (झ) के प्रावधानों के अंतर्गत है।

**(iii) कार्यक्रम संख्या 4: घरेलू बाजार दायित्व (डीएमओ) योजना**

**क. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध**

45. इंडोनेशिया सरकार की नीति का आशय बढ़ती हुई घरेलू मांग को पूरा करने के लिए खनिज/कोयले की आपूर्ति की गारंटी देना है। केंद्र सरकार प्रत्येक खनन उत्पाद के उत्पादन और निर्यात का नियंत्रण करती है। क्षेत्रीय सरकार का भी केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले उत्पादन एवं निर्यात नियंत्रणों का अनुपालन करने का दायित्व है। डीएमओ सभी प्रकार के कोयला एवं खनिजों पर लागू होता है। खनन कंपनियों को अपने खनिज/कोयला उत्पादन को घरेलू उत्पादकों को देखकर डीएमओ अपेक्षाओं का पालन करना ही चाहिए। यद्यपि इन दायित्वों को लगाकर सरकार घरेलू बाजार में खनिजों/कोयले की कीमतों का कृत्रिम रूप से न्यूनीकरण कर रही है जो कम कीमतों पर उनका उत्पादन करने के लिए इनपुट के रूप में इसका प्रयोग करने वाले निचले स्तर के उद्योगों को अनुमति देती है।

**ख. इंडोनेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध**

46. 2009 का कानून संख्या 4, भारत सरकार के लिए ऊर्जा एवं खनिज संसाधन मंत्रालय के 2008 के विनियम संख्या 25 द्वारा यथासंशोधित ऊर्जा एवं खनिज संसाधन मंत्रालय के 2009 के विनियम संख्या 39 के माध्यम से खनिज एवं कोयले के लिए घरेलू बाजार को न्यूनतम बिक्री अपेक्षित है।
47. इंडोनेशिया सरकार प्रत्येक वर्ष में जनहित के लिए कोयले की न्यूनतम प्रतिशत बिक्री निर्धारित करती है। क्रमशः 2018 और 2019 में इंडोनेशिया सरकार निर्धारित करती है कि घरेलू उत्पादन की 25 प्रतिशत दर घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। ऊर्जा एवं खनिज संसाधन मंत्रालय के 2017 के विनियम संख्या 5 के तहत 2017 में भारत सरकार ने निर्धारित किया कि निकिल पिघलाने वाले कंपनी को अपनी संस्थापित क्षमता के कम से कम 30 प्रतिशत पर 1.7 प्रतिशत से कम निकिल वाले निकिल का प्रयोग करना चाहिए। तथापि, विनियम ऊर्जा एवं खनिज संसाधन मंत्रालय के 2018 के विनियम संख्या 25 द्वारा 2018 में हटा दिया गया था और बाद में यह अपेक्षा नहीं रह गई थी। इस प्रकार, खनिज उत्पादों के लिए घरेलू बाजार की आवश्यकता के लिए कोई न्यूनतम बिक्री नहीं है।

**क. कार्यक्रम संख्या 1, 2 और 4 के लिए प्राधिकारी द्वारा जांच**

48. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कार्यक्रम संख्या 1, 2 और 4 कोयला एवं अन्य खनिजों की बिक्री विनियमित करने, मॉनीटर और नियंत्रित करने के लिए इंडोनेशिया सरकार द्वारा किए गए कई उपायों से संबंधित हैं।
49. ऊर्जा एवं खनिज संसाधन मंत्रालय के विनियम में खनिजों के उत्पादन/प्रसंस्करण तथा बिक्री को विनियमित किया है जिनमें निर्यात किए जाने से पूर्व खनिज और अयस्क को घरेलू रूप से प्रसंस्कृत किया जाना अपेक्षित होता है। यह नोट किया जाता है कि खनिज और अयस्क के निर्यातों पर प्रतिबंध है।
50. इंडोनेशिया सरकार खनिज एवं कोयला उत्पादों के निर्यातों का अधिकार भी रखती है। तथापि, खनिज उत्पादों के निर्यात की तभी अनुमति दी जाती है जब वे ऊर्जा तथा खनिज संसाधन मंत्रालय के 2018 के विनियम संख्या 25 के तहत विनियमित प्रसंस्करण संबंधी अपेक्षाओं का न्यूनतम स्तर पूरा कर लिया हो। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार 1.7 प्रतिशत से कम निकिल मात्रा वाले निकिल अयस्क के निर्यात की अनुमति देती है, परंतु ये निर्यात 10 प्रतिशत निर्यात कर के अध्यक्षीन रखे जाते हैं। अतिरिक्त रूप से घरेलू बाजार दायित्व कोयले के लिए पूरे किए जाने अपेक्षित होते हैं। घरेलू बाजार दायित्व 2019 में उत्पादन के 25 प्रतिशत पर निर्धारित किया गया था।
51. इस प्रकार, कोयला उत्पादक और खननकर्ता पहले घरेलू बाजार की मांग को पूरा करने के लिए कोयला उपलब्ध कराने हेतु मजबूर किए जाते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इंडोनेशिया सरकार इंडोनेशिया में घरेलू तौर पर बिक्री करने के लिए कोयला उत्पादकों के लिए अपेक्षित कानूनी अधिनियमों की मौजूदगी की अनुमति देकर तथा निर्यात कर, निर्यात प्रतिबंधों के माध्यम से निजी कंपनियों को पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर निकिल अयस्क और कोयले की बिक्री के रूप में इस्पात उत्पादकों को वित्तीय अंशदान देने के लिए निजी कंपनियों को निर्देश दे रही है। इस प्रकार, कोयला और निकिल पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों को उपलब्ध है। लाभ की राशि इंडोनेशिया में स्टेनलेस स्टील के उत्पादकों द्वारा दी गई कीमत तथा इन उपायों के अभाव में देय होने वाली कीमत के बीच के अंतर के बराबर है। यह सब्सिडी कार्यक्रम भी विशिष्ट है क्योंकि यह निकिल, कोयला और अन्य खनिजों का प्रयोग करने वाले कतिपय विशिष्ट उद्यमों अथवा क्षेत्रों के लिए उनके परिष्कृत सामानों के उत्पादन में सीमित है।
52. कोयले के संबंध में, कोयले के लिए निर्धारित कीमत निर्धारण भी कोयला कीमतों के संबंध में ऊर्जा एवं खनिज संसाधन मंत्रालय की संख्या 0617 के/32/एमईएम/2011 में अधिनियमित किया गया था जो नेशनल इलेक्ट्रिक कंपनी (पीएलएन) पीएलएन के लिए खरीदे गए कोयले के लिए लागू हुआ। तथापि, निर्धारण सीमा उत्पादन सुविधा के प्रचालन सहित स्वयं की खपत के लिए निजी स्वामित्व वाले विद्युत संयंत्र को कोयले की बिक्री के लिए लागू नहीं होती। प्राधिकारी मानते हैं कि विद्युत उत्पादक कंपनी द्वारा बेची जाने वाली विद्युत में सब्सिडी का घटक हो सकता है। तथापि, विद्युत उत्पादन कंपनियों द्वारा उत्पाद उत्पादकों को विद्युत की बिक्री के संबंध में रिकार्ड में उपलब्ध विशिष्ट साक्ष्य के अभाव में प्राधिकारी ने आगे की जांच होने तक इस स्तर पर आगे के विश्लेषण के लिए उस पर विचार नहीं किया है। तथापि, इंडोनेशिया सरकार द्वारा कई कदम इंडोनेशिया में घरेलू तौर पर बिक्री करने के लिए कोयला उत्पादन की अपेक्षा वाले कानूनी अधिनियमों की मौजूदगी की अनुमति देकर तथा निर्यात कर, निर्यात प्रतिबंधों के माध्यम से पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर निकिल अयस्क तथा कोयला प्रदान करने के लिए निजी कंपनियों को निर्देशित कर रहे हैं। इस प्रकार, कोयला और निकिल पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों को उपलब्ध है।
53. किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने अपनी कोयला तथा निकिल अयस्क की खरीद के आधार पर इन कार्यक्रमों के अनुसरण में प्राप्त लाभ के संबंध में पूरी सूचना नहीं दी है। प्राधिकारी अनंतिम रूप से निर्धारित करते हैं कि ये कार्यक्रम प्रतिकार योग्य हैं और निर्यातकों को लाभ नियमावली और एएससीएम करार के अभिप्राय से प्रदान किया जाता है तथा इसीलिए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इन कार्यक्रमों के विरुद्ध प्रतिकारी शुल्क अनंतिम रूप से लगाया जाना चाहिए।

**(iv) कार्यक्रम संख्या 3: खनिज धातु और कोयले के लिए निर्धारण कीमत****ख. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध**

54. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि एमओईएमआर (ऊर्जा एवं खनिज संसाधन मंत्री) डीजीओएमसी (खनिज एवं कोयला महानिदेशक) के माध्यम से कोयला तथा धातु खनिजों के लिए कीमतें निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है। यदि ऊर्जा एवं खनिज संसाधन मंत्री द्वारा निर्धारित संगत धातु तथा कोयले के लिए मानक कीमत (निर्धारण) उपयुक्त बाजार दर से कम तय की जाती है तो इंडोनेशिया सरकार को देय परिकलित रॉयल्टी शुल्क बाजार दर का प्रयोग करते हुए परिकलित रॉयल्टी शुल्क से कम होगा। तदनुसार, प्रदत्त लाभ धातु तथा कोयले के लिए उपयुक्त बाजार दर का प्रयोग करते हुए परिकलित रॉयल्टी शुल्क और निर्धारण का प्रयोग करते हुए परिकलित रॉयल्टी शुल्क के बीच का अंतर है। इसके अतिरिक्त, एक अतिरिक्त रॉयल्टी शुल्क धातु तथा कोयले की विभिन्न किस्मों के संबंध में निर्धारित रॉयल्टी की प्रतिशतता से भी प्रभावित हो सकती है।

**ग. इंडोनेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध**

55. विनियम के अनुच्छेद 85 के अनुसार ऊर्जा एवं खनिज संसाधन मंत्रालय निर्धारक कीमत तय करने के लिए उत्तरदायी है। इंडोनेशिया सरकार 2018 के सरकारी विनियम संख्या 8 द्वारा यथासंशोधित 2010 के सरकारी विनियम संख्या 20 के तहत 2010 में शुरू किए गए प्रावधान द्वारा सरकारी राजस्व को अनुकूलतम करने के लिए खनिज, धातु तथा कोयला उत्पादों के संबंध में निर्धारक कीमत तय करती है।
56. खनिज, धातु तथा कोयला उत्पादों के लिए निर्धारक कीमत ऊर्जा तथा खनिज संसाधन मंत्रालय के 2017 के विनियम संख्या 7 के अनुसार बाजार तंत्र तथा/अथवा अंतरराष्ट्रीय बाजार दर्शानी चाहिए। खनन रियायत धारक को अपनी प्रत्येक खनिज तथा कोयला उत्पादों के घरेलू तथा निर्यात लेन-देन में अपनी निर्धारक कीमत का परिकलन करने में संबंधित फॉर्मूला तथा परिवर्तकों का प्रयोग करना चाहिए। भारत सरकार जो भी अधिक है, उसकी शर्त के अधीन या तो निर्धारक दर या वास्तविक लेन-देन कीमत पर रॉयल्टी लगाएगी।
57. यह योजना प्रतिकारयोग्य नहीं है क्योंकि यह निर्यातक को कोई लाभ नहीं देती है। इसके विपरीत, यह योजना इस तरह से बनाई गई है कि यह इससे अधिक शुल्क एकत्रित कर सके जो देय है, परंतु वास्तविक लेन-देन मूल्य से कभी भी कम नहीं हो।

**ग. प्राधिकारी द्वारा जांच**

58. ऊर्जा तथा खनिज संसाधन मंत्रालय विनियम के अनुच्छेद 85 के अनुसार इंडोनेशिया के निर्धारण तय करने के लिए उत्तरदायी है। वह रॉयल्टी एकत्रित करने के प्रयोजन के लिए खनिज तथा अयस्क की निर्धारक/न्यूनतम बिक्री कीमत तय करता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि खनिज तथा अयस्क का निर्धारण केवल रॉयल्टी एकत्रित करने तथा राजस्व को अनुकूलतम बनाने के प्रयोजन से किया जाता है।
59. खनन रियायत धारक को अपनी प्रत्येक खनिज तथा कोयला उत्पादों के घरेलू तथा निर्यात लेन-देन में अपनी निर्धारक कीमत का परिकलन करने में संबंधित फॉर्मूला तथा परिवर्तकों का प्रयोग करना चाहिए। यदि निर्धारक कीमत वास्तविक लेन-देन मूल्य से अधिक है तो रॉयल्टी की राशि निर्धारक कीमत के आधार पर होगी। यदि लेन-देन मूल्य निर्धारक कीमत से अधिक है तो रॉयल्टी की राशि लेन-देन मूल्य के आधार पर होगी।
60. प्राधिकारी ने पहले ही अनंतिम रूप से निष्कर्ष निकाला है कि निकिल अयस्क इंडोनेशिया उत्पादकों के लिए पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर उपलब्ध है। इस कार्यक्रम के तहत कोई और लाभ नहीं है। इस प्रकार प्राधिकारी अनंतिम रूप से मानते हैं कि इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

**(v) कार्यक्रम संख्या 5: निर्यात ऋण बीमा और हानियों की प्रतिपूर्ति****क. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध**

61. सरकारी स्वामित्व वाली फर्म असुरांसी एक्सपोर इंडोनेशिया ("एएसईआई") निर्यात की हानियों के लिए व्यापक निर्यात ऋण बीमा तथा प्रतिपूर्तियां प्रदान करती है। एएसईआई निर्यातकों को उनकी हानियों के 85 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति करती हैं। इससे निर्यातकों तथा बैंकों द्वारा वहन किए गए जोखिमों को कवर करने के लिए विशेषीकृत उत्पाद हैं। यह मुख्य रूप से तेल तथा गैसों के निर्यातों में लगे उद्यमों को छोड़कर निर्यातों में

लगे उद्यमों को प्रदान किया जाता है। यह बीमा के लिए विनियम पर प्राप्त करने वालों द्वारा दी जाने वाली राशि तथा जो राशि प्राप्तकर्ता तुलनीय बीमा कवर पर प्रदान करेगा, जिसे प्राप्तकर्ता वास्तविक रूप से बाजार पर प्राप्त कर सकता है, के बीच अंतर के बराबर लाभ प्रदान करता है।

**ख. इंडोनेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध**

62. सरकारी विनियम संख्या 1/1982 में निर्यात ऋण बीमा तथा निर्यात ऋण गारंटी कार्यक्रम अधिनियमित किए गए। निर्यात ऋण बीमा इंडोनेशियाई निर्यातकों को उनके आयातकों से गैर भुगतान जोखिम के विरुद्ध बीमा/सुरक्षा के लिए प्रदान किया जाता है जबकि निर्यात ऋण गारंटियां उधारकर्ता के निर्यात ऋण के जोखिम के विरुद्ध इंडोनेशियाई बैंकों का बीमा करने के लिए प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, सरकारी विनियम संख्या 20/1983 में निर्यात ऋण बीमा और निर्यात ऋण गारंटी का प्रावधान करने के लिए सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों की स्थापना निर्धारित की गई। जांचाधीन किसी भी कंपनी ने इस कार्यक्रम का प्रयोग नहीं किया।
63. असुरांसी एएसईआई एक राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम की सहायक कंपनी है, 99.998 प्रतिशत पर इंडोनेशिया-आरई का स्वामित्व है और 0.002 प्रतिशत पर उसके कर्मचारी सहकारी का स्वामित्व है। असुरांसी एएसईआई एक लाभोन्मुख/वाणिज्यिक कंपनी है और अपने कारपोरेट ग्राहकों को सामान्य बीमा उत्पाद तथा सेवाएं (ऋण बीमा सहित) प्रदान करती रहती है। असुरांसी एएसईआई ने 1995 से निर्यात गारंटियां नहीं दी हैं।

**ग. प्राधिकारी द्वारा जांच**

64. सरकारी विनियम संख्या 20/1983 में निर्यात ऋण बीमा तथा निर्यात ऋण गारंटी का प्रावधान करने के लिए सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम ("एसओई") की स्थापना निर्धारित है।
65. पीटी. असुरांसी एक्सपोर इंडोनेशिया (परसेरो) निर्यात ऋण गारंटी और बीमा के लिए व्यापार करने हेतु स्थापित की गई थी। परसेरो ने पीटी. असुरांसी एएसईआई इंडोनेशिया (असुरांसी एएसईआई) नामक सहायक कंपनी की स्थापना की और बाद में दिसंबर, 2014 में अपना बीमा व्यापार स्पन-ऑफ किया। यह दावा किया गया है कि असुरांसी एएसईआई ने 1995 से निर्यात गारंटियां नहीं दी हैं।
66. हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने इस कार्यक्रम के तहत कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है। प्राधिकारी अनंतिम रूप से निर्धारित करते हैं कि आगे की जांच के अध्यक्षीन इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई प्रतिकारी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता नहीं है।

**(vi) कार्यक्रम संख्या 6: निर्यात ऋण गारंटी**

**क. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध**

67. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि सरकारी स्वामित्व वाला इंडोनेशिया एक्विजम बैंक निर्यात ऋण गारंटी प्रदान करता है जो बैंकों को निर्यात वित्तपोषण के लिए कम दर लगाने की गारंटी देता है जिसके परिणामस्वरूप निर्यातोन्मुख उद्यमों को कम दर पर वित्तपोषण उपलब्ध है।

**ख. इंडोनेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध**

68. दोनों इंडोनेशिया एक्विजम बैंक ऋणी के बकाया के जोखिम के विरुद्ध बैंक अथवा वित्तीय संस्था को निर्यात ऋण गारंटी प्रदान करते हैं।
69. यह कार्यक्रम इंडोनेशिया गणराज्य क्षेत्र में मूल निवासियों तथा व्यापारिक कंपनियों के लिए पात्र है। पात्रता के मानदंडों को शासित करने वाले कोई कानून अथवा विनियम नहीं हैं। इंडोनेशिया एक्विजम बैंक की आंतरिक प्रक्रिया पात्रता निर्धारित करने के लिए लागू होगी। किसी भी प्रतिभागी कंपनी ने जांच की अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के लिए आवेदन नहीं किया, अथवा उपार्जन नहीं किया।

**ग. प्राधिकारी द्वारा जांच**

70. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इंडोनेशिया एक्विजम बैंक लेमबागा पेम्बियान एक्सपोर इंडोनेशिया (एलपीईआई) अधिनियम के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है और इस पर इंडोनेशिया सरकार का 100 प्रतिशत स्वामित्व है। इंडोनेशिया एक्विजम बैंक का प्रचालन इंडोनेशिया केंद्रीय विनियम (बैंक इंडोनेशिया/बीआई) तथा वित्तीय सेवाएं प्राधिकारी (ऑटोरिटस जासा किउंगन/ओजेके) विनियम के अध्यक्षीन है। अतः इंडोनेशिया

एक्जिम बैंक द्वारा दी गई निर्यात ऋण गारंटी पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर सार्वजनिक निकाय द्वारा सेवा के प्रावधान के रूप में वित्तीय अंशदान है।

71. उद्यम को लाभ इंडोनेशिया एक्जिम बैंक द्वारा लगाए गए शुल्क तथा गारंटी प्रदान करने के लिए अन्य वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लगाए गए शुल्क के बीच के अंतर के अनुसार प्रदान किया जाता है। तथापि, किसी भी प्रतिभागी कंपनी ने जांच की अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के लिए आवेदन नहीं किया है अथवा लाभ प्राप्त नहीं किया है। प्राधिकारी अनंतिम रूप से निर्धारित करते हैं कि आगे की जांच होने तक इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई प्रतिकारी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता नहीं है।

**(vii) कार्यक्रम संख्या 7: आय कर की कटौती**

**क. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध**

72. इंडोनेशियाई सरकार निर्धारित अवधि के भीतर किए गए कुल निवेशों की निर्धारित सीमा तक निवल आय की कटौती प्रदान करती है। इंडोनेशिया गणराज्य के कानून के अनुच्छेद 18 में पात्रता निर्धारित है:

- (i) निवेश करता है (अपना व्यापार बढ़ाता है; अथवा नया निवेश करता है)
- (ii) किसी एक पात्रता को पूरा करता है-
  - कई कामगारों को खपाता है
  - उच्च प्राथमिकता मानदंड के तहत आता है
  - अवसंरचना निर्माण में लगा हुआ है
  - प्रौद्योगिकी अंतरित करता है
  - अग्रणी उद्योग में लगा हुआ है
  - सुदूर क्षेत्र, कम विकसित क्षेत्र, निकटवर्ती क्षेत्र अथवा जरूरतमंद माने गए अन्य क्षेत्र में स्थित है
  - पर्यावरण को संधारणीय रखता है
  - अनुसंधान, विकास तथा नवोनव्य क्रियाकलाप करता है
  - सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों अथवा सहकारी समितियों में भागीदारी में है।

73. आय की कटौती के परिणामस्वरूप आय कर देयता कम होती है। इसके अतिरिक्त, इंडोनेशिया स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों के लिए 5 प्रतिशत कटौती लागू है।

**ख. इंडोनेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध**

74. इंडोनेशिया स्टॉक एक्सचेंज (आईडीएक्स) में सूचीबद्ध कंपनियों के लिए आय कर की कटौती सबसे पहले 2013 के सरकारी विनियम संख्या 77 द्वारा यथासंशोधित 2007 के सरकारी विनियम संख्या 81 के तहत विनियमित की जाती है। पूर्व के विनियम में निर्धारित किए गए अनुसार, यह कटौती वित्तपोषक व्यापारिक क्षेत्रों में पूंजी व्यापार की भूमिका संदर्भित करने, सार्वजनिक कंपनियों, प्रचार प्रसारित करने तथा व्यापारिक कंपनियों में सार्वजनिक स्वामित्व बढ़ाने के लिए है। यह कटौती कतिपय अपेक्षाओं को पूरा करने वाली आईडीएक्स में सूचीबद्ध कंपनियों को कारपोरेट आय की 5 प्रतिशत की दर पर प्रदान किया जाता है। कोई भी प्रतिभागी कंपनी सार्वजनिक कंपनी तथा आईडीएक्स में सूचीबद्ध नहीं है। इस प्रकार, उनमें से किसी ने भी जांच की अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के लिए आवेदन नहीं किया, उपार्जन नहीं किया अथवा इससे लाभ प्राप्त नहीं किए।

**ग. प्राधिकारी द्वारा जांच**

75. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आय कर से कटौती के रूप में इस कार्यक्रम के तहत दो प्रदान के लाभ प्रदान किए जाते हैं (i) निर्धारित अवधि के दौरान निवेश करने वाली और कतिपय शर्तों को पूरा करने वाली कंपनियों को कुल आय से निर्धारित प्रतिशतता की कटौती की अनुमति दी जाएगी और (ii) इंडोनेशिया में स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों को 5 प्रतिशत कटौती प्रदान की जाती है।

76. सभी प्रतिभागी कंपनियों ने अनुरोध किया है कि उन्होंने इस कार्यक्रम के तहत कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है। 5 प्रतिशत की दर पर आय कर की कटौती के संदर्भ में प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोई भी प्रतिभागी कंपनी सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। तथापि, हितबद्ध पक्षकारों और इंडोनेशिया सरकार ने निवेश मानदंडों के आधार पर प्रतिभागी कंपनियों को लाभ के अभाव के संबंध में पूर्ण सूचना तथा स्पष्टीकरण नहीं दिया है। प्राधिकारी के पास यह निष्कर्ष निकालने के लिए इस स्तर पर पर्याप्त सूचना तथा साक्ष्य भी है कि उद्यमों को आय कर से छूट निवेश मानदंडों के आधार पर दी गई थी।
77. इस प्रकार प्राधिकारी आगे की जांच होने तक अनंतिम रूप से निर्धारित करते हैं कि इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई प्रतिकारी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता नहीं है।

**(viii) कार्यक्रम संख्या 8: कर अवकाश**

**क. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध**

78. उन संगत अग्रणी उद्योग करदाताओं को कारपोरेट आय कर से कटौती के रूप में कर अवकाश लागू है जिन्होंने कम से कम आरपी 500 बिलियन की नई पूंजी निवेश योजनाएं बनाई हैं।

**ख. इंडोनेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध**

79. कर अवकाश में कारपोरेट आय कर कटौती सुविधा उस मुख्य व्यापार क्रियाकलाप के प्राप्त अथवा उपार्जित आय को प्रदान की जाएगी जो अग्रणी उद्योग है। अप्रैल, 2018 में 5 से 20 वर्ष के लिए 100 प्रतिशत आय कर कटौती प्रदान करने हेतु कर अवकाश में संशोधन किया गया था। चूंकि यह वर्तमान में लागू है, अतः कर अवकाश कुल निवेश मूल्य के आधार पर 50 प्रतिशत और 100 प्रतिशत के लिए आय कर कटौती प्रदान करता है।
80. कर कटौती प्राप्त करने वाले निगम को "व्यापक अंतर संयोजन के साथ जो वर्धित मूल्य तथा उच्च बाहरी स्थिति प्रदान करता है, नई प्रौद्योगिकी शुरू करता है तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए जिसका नीतिगत मूल्य है" वाले उद्योग के रूप में परिभाषित "अग्रणी उद्योग" में कार्यरत होना होता है।
81. जांचाधीन किसी भी कंपनी ने जांच के अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के लिए आवेदन नहीं किया, उससे उपार्जन नहीं किया अथवा लाभ प्राप्त नहीं किए।

**ग. प्राधिकारी द्वारा जांच**

82. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम में निवेश करने वाले और निर्धारित पात्रता मानदंड पूरे करने वाले कतिपय उद्यमों को आय कर की कटौती के लिए प्रावधान है। इस कार्यक्रम में उस छोड़े गए राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है जो अन्यथा देय है तथा जिससे लाभ प्रदान किया जाता है।
83. किसी भी प्रतिभागी कंपनी ने जांच के अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के लिए आवेदन करने का, उपार्जन करने का अथवा लाभ प्राप्त करने का दावा नहीं किया है। आगे की जांच होने तक प्राधिकारी अनंतिम रूप से निर्धारित करते हैं कि इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई प्रतिकारी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता नहीं है।

**(ix) कार्यक्रम संख्या 9: इंडोनेशिया एक्जिम से निर्यात वित्तपोषण**

**क. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध**

84. इंडोनेशिया एक्जिम बैंक – लेमबागा पेम्बियान एक्सपोर इंडोनेशिया ("एलपीईआई") वित्तपोषण प्रदान कर राष्ट्र के प्रमुख निर्यात उत्पादों के सुधार में सहायता के लिए तथा उच्च प्रतिस्पर्द्धी उत्पादों के लिए अधिमान्य दरों पर निर्यात वित्तपोषण प्रदान करता है। एलपीईआई का मुख्य कार्य इंडोनेशियाई निर्यातों को आगे बढ़ाने में सहायता करना है और वह उन क्षेत्रों को वित्तपोषण प्रदान करता है जिनमें वाणिज्यिक बैंक अथवा वाणिज्यिक वित्तीय संस्थाएं आने के लिए उदार हैं।
85. निर्यातकों के लिए वित्तपोषण के अलावा, इंडोनेशिया एक्जिम बैंक इंडोनेशिया से सामानों और सेवाओं के आयात के उद्देश्य से विदेशी क्रेता को भी वित्तपोषण प्रदान कर सकता है। एलपीईआई के अनुच्छेद 22 अधिनियम के अनुसार इंडोनेशिया एक्जिम बैंक की निधियों के स्रोत (i) विपणनीय प्रतिभूतियों का बीमा; (ii) विदेशी सरकारों, बहुपक्षीय एजेंसियों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और इंडोनेशिया सरकार से ऋण; (iii) अनुदान; तथा (iv) बैंक इंडोनेशिया द्वारा निधि लगाना हैं।



**ख. इंडोनेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध**

86. इंडोनेशिया एक्जिम बैंक इंडोनेशिया सरकार के स्वामित्व वाली एक विशेष वित्तीय संस्था है और लेमबागा पेम्बियान एक्सपोर इंडोनेशिया (एलपीईआई) के संबंध में अधिनियम संख्या 2/2009 के अधिदेश के भाग के रूप में स्थापित किया गया था। तथापि, इंडोनेशिया एक्जिम बैंक का प्रचालन इंडोनेशिया केंद्रीय विनियम (बैंक इंडोनेशिया/बीआई) तथा वित्तीय सेवाएं प्राधिकारी (ऑटोरिटस जासा किउंगन/ओजेके) विनियम के अधीन है।
87. इसके अतिरिक्त, इंडोनेशिया एक्जिम बैंक के प्रमुख क्रियाकलाप वित्तपोषण (पारंपरिक एवं शरिया अनुपालक दोनों); गारंटी; बीमा; बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, निर्यात सामानों के निर्यातक विनिर्माताओं, विशेष रूप से लघु और मध्यम आकार के उद्यमों तथा सहकारी समितियों को कोचिंग तथा सलाहकार सेवाएं; और राष्ट्रीय निर्यात कार्यक्रम की सहायता के लिए सरकार द्वारा विशेष कार्य के लिए वित्तपोषण प्रदान करना है। इंडोनेशिया सरकार ने अनुरोध किया कि जांचाधीन किसी भी कंपनी ने जांच की अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के लिए आवेदन नहीं किया, इससे उपार्जन नहीं किया अथवा लाभ प्राप्त नहीं किए।

**ग. प्राधिकारी द्वारा जांच**

88. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इंडोनेशिया एक्जिम बैंक सामानों के निर्यात में लगे उद्यमों सहित अन्य उद्यमों को वित्तपोषण प्रदान करता है। सभी प्रतिभागी कंपनियां अधिमान्य वित्तपोषण के रूप में इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।
89. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इंडोनेशिया एक्जिम बैंक लेमबागा पेम्बियान एक्सपोर इंडोनेशिया (एलपीईआई) अधिनियम के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है और इस पर इंडोनेशिया सरकार का 100 प्रतिशत स्वामित्व है। इंडोनेशिया एक्जिम बैंक का प्रचालन इंडोनेशिया केंद्रीय विनियम (बैंक इंडोनेशिया/बीआई) तथा वित्तीय सेवाएं प्राधिकारी (ऑटोरिटस जासा किउंगन/ओजेके) विनियम के अधीन है। अतः इंडोनेशिया एक्जिम बैंक द्वारा दिया जाने वाला निर्यात वित्तपोषण सार्वजनिक निकाय द्वारा निधियों के सीधे अंतरण के रूप में वित्तीय अंशदान है।
90. लाभ की राशि इंडोनेशिया एक्जिम बैंक/किसी अन्य सरकारी स्वामित्व वाले बैंक द्वारा लगाए गए ब्याज और तुलनीय वाणिज्यिक ऋण पर किसी अन्य वाणिज्यिक बैंक द्वारा लगाए गए ब्याज के बीच अंतर के बराबर है। किसी भी प्रतिभागी कंपनी ने जांच की अवधि अथवा एयूएल अवधि के दौरान एक्जिम बैंक और/अथवा किसी अन्य सरकारी स्वामित्व वाले बैंक से प्राप्त ऋणों के संबंध में सूचना प्रदान नहीं की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी प्रतिभागी कंपनी ने ऋण परिशिष्टों के तहत अनुरोध किए गए ऋणों के संबंध में सूचना प्रदान नहीं की है।
91. किसी भी प्रतिभागी कंपनी ने अपने इस दावे को सिद्ध करने के लिए कोई समर्थक सूचना अथवा दस्तावेज नहीं दिया है कि इस कार्यक्रम के तहत कोई लाभ प्राप्त नहीं किया गया था। इस प्रकार, इंडोनेशिया एक्जिम बैंक अथवा किसी अन्य सरकारी स्वामित्व वाले बैंक से ऋणों के माध्यम से निधियों के सीधे अंतरण के संदर्भ में प्राप्त लाभ का प्रतिभागी निर्यातकों द्वारा इंकार करना ऋण परिशिष्टों में अनुरोध की गई सूचना के उत्तर में बैंकों से प्राप्त सभी ऋणों के संबंध में समर्थक सूचना के बिना स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्राधिकारी अनंतिम रूप से निर्धारित करते हैं कि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सभी प्रतिभागी उत्पादकों/निर्यातकों पर इस कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिकारी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता है।

**(x) कार्यक्रम संख्या 10: आयात शुल्क पर छूट****क. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध**

92. इंडोनेशिया सरकार सामग्री सामानों के आयातों पर तब आयात शुल्कों से छूट देती है जब उनका प्रयोग निर्यात प्रयोजनों के लिए विनिर्माण सामानों में किया जाता है। यह छूट आवश्यकताओं के अनुसार और कठोर निगरानी के तहत दी जाती है। यदि छूट के लिए दी गई आयातित सामग्री और उत्पादन में प्रयुक्त सामग्री के बीच कमी है तो उस कमी के लिए छूट लागू नहीं होगी और सीमा शुल्क विनियम के अनुसार दंड दिया जाएगा।

93. छूट मुख्य रूप से बांडेड जोनों, फ्री ट्रेड जोनों अथवा समान जोन में उद्यमों को प्रदान की जाती है। छूट की वास्तविक राशि निर्यात के लिए अंतिम विनिर्माण सामानों में प्रयुक्त आयातित सामग्री की राशि के माध्यम से निर्धारित की जाती है।

**ख. इंडोनेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध**

94. यह कार्यक्रम निर्यात प्रयोजन के लिए आयात सुविधा (केआईटीई) योजना के तहत निर्धारित है, जो अधिनियम संख्या 10/1995 द्वारा यथाअधिदेशित और सीमा शुल्क के संबंध में अधिनियम संख्या 17/2006 द्वारा आंशिक रूप से यथासंशोधित वित्त मंत्री के निर्णय संख्या 580/केएमके.04/2003 के अनुसरण में दिसंबर, 2003 में स्थापित की गई थी।
95. निर्यात प्रयोजनों के लिए विनिर्माण सामानों में प्रसंस्कृत, असेंबलड अथवा संस्थापित सामानों पर आयात शुल्क से छूट दी जा सकती है। अचल संपत्तियों के आयातों पर इस कार्यक्रम के तहत आयात शुल्कों से छूट नहीं दी जाती है।
96. छूट आवश्यकताओं तथा कठोर निगरानी के तहत प्रचालित की जाती है। आयातित सामग्री के परिणामस्वरूप सभी अंतिम सामानों का निर्यात किया जाना चाहिए और यदि परिवर्तन परीक्षण के अनुसार छूट के लिए दी गई आयातित सामग्री तथा उत्पादन में प्रयुक्त सामग्री के बीच कोई कमी है तो उस कमी के कारण छूट लागू नहीं होगी और सीमा शुल्क विनियम के अनुसार इसके लिए दंड दिया जाएगा।
97. सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क महानिदेशालय – वित्त मंत्रालय के अधीन प्रचालित क्षेत्रीय सीमा शुल्क कार्यालय इस योजना का संचालन करता है और कठोर निगरानी रखता है। यदि वसूली निर्यात रिपोर्ट पर क्षेत्रीय सीमा शुल्क कार्यालय की सहमति होती है तो छूट लागू की जाती है। सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क महानिदेशक के विनियम संख्या 04/बीसी/2014 द्वारा आंशिक रूप से संशोधित सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क महानिदेशक के विनियम संख्या 16/बीसी/2012 के अनुसार आवेदक के पास छूट के प्रयोजन के लिए पहचान संख्या (एनआईपीआईआर) होनी चाहिए। एनआईपीआईआर प्राप्त करने की प्रक्रिया में आवेदक को क्षेत्रीय सीमा शुल्क कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिए और कई अपेक्षाएं पूरी करनी चाहिए। सभी एनआईपीआईआर धारक कंपनियां इस छूट से लाभ ले सकती हैं। तथापि, किसी भी जांचाधीन कंपनी ने जांच की अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के लिए आवेदन नहीं किया, उपार्जन नहीं किया अथवा लाभ प्राप्त नहीं किए।

**ग. प्राधिकारी द्वारा जांच**

98. इंडोनेशिया सरकार ने अनुरोध किया कि उपर्युक्त कार्यक्रम निर्यात प्रयोजन के लिए आयात सुविधा (केआईटीई) योजना के तहत निर्धारित है जिसकी स्थापना वित्त मंत्री के निर्णय संख्या 580/केएमके.04/2003 के अनुसरण में दिसंबर, 2003 में की गई थी और अंतिम रूप से वित्त मंत्री के विनियम संख्या 253/पीएमके.04/2011 तथा वित्त मंत्री के विनियम संख्या 177/पीएमके.04/2013 द्वारा संशोधित की गई थी।
99. यह कार्यक्रम एससीएम करार की पाद टिप्पणी 1 तथा सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9ख(1)(ख) के तहत अनुमति योग्य शुल्क प्रेषण कार्यक्रम नहीं है। यह कार्यक्रम निर्यातित उत्पाद के उत्पादन में प्रयुक्त कच्ची सामग्री को छूट प्रदान करती है। ऐसे किसी सत्यापन तंत्र का पर्याप्त साक्ष्य नहीं है जो यह सुनिश्चित करे कि उद्यम को कोई अतिरिक्त लाभ नहीं है। यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि दंड अथवा शुल्क की वसूली वास्तव में उन उद्योगों से की गई थी जो निर्यातित सामानों के उत्पादन में कच्ची सामग्री का उपयोग करने में असमर्थ थे।
100. इस कार्यक्रम में छोड़े गए राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है और उससे लाभ प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह निर्यात के संबंध में आकस्मिक है। तथापि, प्राधिकारी ने निर्धारित किया है कि प्रतिकारी शुल्क बांडेड जोन कार्यक्रम के लिए और प्रतिभागी कंपनियों को आयात शुल्क से छूट प्रदान करने वाले अन्य दो आयात शुल्क छूट कार्यक्रमों (अन्य कार्यक्रमों) के लिए लगाया जाना चाहिए। प्राधिकारी अनंतिम रूप से मानते हैं कि इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई अतिरिक्त प्रतिकारी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता नहीं है।

**(ख) कार्यक्रम संख्या 11: आयात शुल्क वापसी****क. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध**

101. इंडोनेशियाई सरकार निर्यात प्रयोजनों के लिए विनिर्मित सामानों में प्रसंस्कृत, असेंबलड अथवा संस्थापित सामानों के लिए उद्यमों द्वारा देय आयात शुल्क के छूट की अनुमति देती है। निर्दिष्ट क्षेत्रीय सीमा शुल्क कार्यालय पूंजी सामान रिपोर्टों के आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित शुल्क वापसी की राशि का मूल्यांकन करता है।

**ख. इंडोनेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध**

102. यह कार्यक्रम निर्यात प्रयोजन के लिए आयात सुविधा (केआईटीई) योजना के तहत निर्धारित है, जो अधिनियम संख्या 10/1995 द्वारा यथाअधिदेशित और सीमा शुल्क के संबंध में अधिनियम संख्या 17/2006 द्वारा आंशिक रूप से यथासंशोधित वित्त मंत्री के निर्णय संख्या 580/केएमके.04/2003 के अनुसरण में दिसंबर, 2003 में स्थापित की गई थी। वित्त मंत्री के दोनों विनियमों के अनुसार, आयात शुल्क वापसी योजना में निर्यात प्रयोजन के लिए विनिर्माण सामानों में प्रसंस्कृत, असेंबलड अथवा संस्थापित सामानों के आयातों के लिए देय आयात शुल्कों से छूट का प्रावधान है। आवेदक अंतिम सामानों का निर्यात किए जाने के बाद शुल्क वापसी प्राप्त करेगा।
103. यह योजना सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क महानिदेशालय – वित्त मंत्रालय के अधीन प्रचालित प्रत्येक क्षेत्रीय सीमा शुल्क कार्यालय द्वारा संचालित की जाती है। इस योजना का प्रशासन सीमा शुल्क एवं उत्पादक शुल्क महानिदेशक के विनियम संख्या 05/बीसी/2014 द्वारा आंशिक रूप से यथासंशोधित सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क महानिदेशक के विनियम संख्या 15/बीसी/2012 के संबंध में विनियमित की गई थी। निर्दिष्ट सीमा शुल्क क्षेत्रीय कार्यालय को आवेदन पत्र पर कार्रवाई करने और आवेदन पत्र का निर्णय जारी करने का प्राधिकार है। पात्रता मानदंड कंपनी पहचान संख्या (एनआईपीआईआर) धारक है।
104. किसी भी जांचाधीन कंपनी ने जांच की अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के लिए आवेदन नहीं किया, उपार्जन नहीं किया अथवा लाभ प्राप्त नहीं किए।

**ग. प्राधिकारी द्वारा जांच**

105. इंडोनेशिया सरकार ने अनुरोध किया कि उपर्युक्त कार्यक्रम निर्यात प्रयोजन के लिए आयात सुविधा (केआईटीई) योजना के तहत निर्धारित है जिसकी स्थापना वित्त मंत्री के निर्णय संख्या 580/केएमके.04/2003 के अनुसरण में दिसंबर, 2003 में की गई थी और अंतिम रूप से वित्त मंत्री के विनियम संख्या 253/पीएमके.04/2011 तथा वित्त मंत्री के विनियम संख्या 177/पीएमके.04/2013 द्वारा संशोधित की गई थी।
106. वित्त मंत्रालय के विनियम के अनुसार, वापसी की योजना में निर्यात प्रयोजनों के लिए विनिर्माण सामानों में प्रसंस्कृत, असेंबलड अथवा संस्थापित किए जाने पर अंतिम सामानों के निर्यात के समय प्राप्य सामानों के आयातों के लिए देय आयात शुल्कों का प्रावधान है, ये आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से लौटाए जाने हो सकते हैं। वर्तमान योजना भी सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क महानिदेशालय – वित्त मंत्रालय के अधीन प्रचालित क्षेत्रीय सीमा शुल्क अधिकारी के पर्यवेक्षण में है।
107. पात्रता मानदंड वित्त मंत्री के विनियम संख्या 177/पीएमके.04/2013 में स्पष्ट किए गए अनुसार कंपनी पहचान संख्या (एनआईपीआईआर) है। शुल्क वापसी की राशि निर्यातों के लिए अंतिम सामानों में निहित सामानों पर दिए गए शुल्क की राशि की मात्रा है। प्राधिकारी ने पहले ही निर्धारित कर दिया है कि केआईटीई कार्यक्रम में छोड़े गए राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है और उससे लाभ प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह निर्यात के संबंध में आकस्मिक है। प्राधिकारी ने निर्धारित किया है कि प्रतिकारी शुल्क बांडेड जोन कार्यक्रम के लिए और प्रतिभागी कंपनियों को आयात शुल्क से छूट प्रदान करने वाले अन्य दो आयात शुल्क छूट कार्यक्रमों (अन्य कार्यक्रमों) के लिए लगाया जाना चाहिए। प्राधिकारी अनंतिम रूप से निर्धारित करते हैं कि इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई अतिरिक्त प्रतिकारी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता नहीं है।

**(xii) कार्यक्रम संख्या 13: निवल कर योग्य आय की कटौती****क. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध**

108. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि इंडोनेशिया सरकार वाणिज्यिक उत्पादन के छः वर्षों के लिए 5 प्रतिशत आनुपातिक दर पर अचल परिसंपत्तियों (भूमि सहित) के रूप में निवेश की गई राशि के 30 प्रतिशत तक निवल कर योग्य आय में उद्यमों को कटौती प्रदान करती है, बशर्ते कि निवेश की गई परिसंपत्तियों का दुरुपयोग न हो अथवा किसी अवधि के अंतर्गत वे अंतरित न हों। यह मुख्य रूप से एसईजेड जोनों में स्थित उद्यमों को प्रदान की जाती है।

**ख. इंडोनेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध**

109. केईके (क्वासन इकोनॉमी खुसुस), जैसा कि वह विशेष आर्थिक क्षेत्र के संबंध में अधिनियम संख्या 39/2009 के माध्यम से स्थापित की गई है, केईके में स्थित और मुख्य व्यापार प्रचालित करने वाली कंपनी को कराधान से रोजगार तक कई सुविधाएं एवं प्रोत्साहन प्राप्त करने की अनुमति देता है। वर्तमान में, पूरे इंडोनेशिया में 13 निर्दिष्ट केईके हैं। इनके कार्यान्वयन में, केईके, केईके नेशनल काउंसिल द्वारा स्थापित हैं। केईके नेशनल काउंसिल का एक मुख्य दायित्व यह निर्धारित करना है कि केईके में कौन सा व्यापारिक क्षेत्र मुख्य व्यापार हो। इन क्षेत्रों में वृक्षारोपण, संभारिकी से लेकर पर्यटन तक विकसित किए जाने की संभावनाएं हैं। चूंकि यह वर्तमान में है, अतः एसईजेड अभी तक पूर्ण रूप से प्रचालित नहीं है।
110. सरकारी विनियम संख्या 96/2015 में निर्धारित किए गए अनुसार केईके में निवल कर योग्य आय की कटौती से संबंधित प्रावधान वाणिज्यिक उत्पादन के छः वर्षों के लिए 5 प्रतिशत आनुपातिक दर पर अचल परिसंपत्तियों (भूमि सहित) के रूप में निवेश की गई राशि के 30 प्रतिशत तक निवल कर योग्य आय की कटौती करता है। इस सुविधा के लिए आवेदन पत्र संबंधित केईके के प्रशासक के माध्यम से वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
111. केईके के अलावा, सरकारी विनियम संख्या 18/2015 के तहत विनियमित आय कर अलाउंस सुविधाएं निवल कर योग्य आय की समान कटौती प्रदान करती हैं। तथापि, कंपनी के लिए दोहरी आय कर सुविधा प्राप्त करना असंभव है। किसी भी जांचाधीन कंपनी ने जांच की अवधि के दौरान केईके में स्थित अथवा इस कार्यक्रम के लिए आवेदन नहीं किया है, उपार्जन नहीं किया है अथवा लाभ प्राप्त नहीं किए हैं।

**ग. प्राधिकारी द्वारा जांच**

112. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित उद्योगों के लिए उपलब्ध है और इसमें 30 प्रतिशत तक कर योग्य आय की कटौती का प्रावधान है। यह कार्यक्रम सरकारी विनियम संख्या 18/2015 द्वारा शासित किया जाता है। आय कर छूट इस कार्यक्रम के तहत ही विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित उद्योगों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है न कि किसी अन्य कार्यक्रम के अंतर्गत।
113. सब्सिडी कार्यक्रम में छोड़े गए राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है जो अन्यथा देय है। यह कार्यक्रम भी विशिष्ट है क्योंकि यह क्षेत्र विशिष्ट है। तथापि, किसी भी जांचाधीन कंपनी ने जांच की अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के लिए आवेदन नहीं किया है, उपार्जन नहीं किया है अथवा लाभ प्राप्त नहीं किए हैं। प्राधिकारी रिकार्ड का सत्यापन होने तक अनंतिम रूप से यह मानते हैं कि इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई प्रतिकारी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता नहीं है।

**(xiii) कार्यक्रम संख्या 14: हानियों को अग्रेणित करना****क. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध**

114. इंडोनेशियाई सरकार 5 वर्षों की अवधि तक निवेशकों को उनकी हानियां अग्रेणित करने का विकल्प प्रदान करती है जिसे आगे 5 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है:

- यदि पूंजी निवेश आरपी 200 बिलियन से अधिक है तो 1 वर्ष का विस्तार;
- 1 वर्ष या 2 वर्ष का विस्तार यदि:

- 5 वर्षों के लिए इंडोनेशियाई कामगारों को रोजगार देता है जो 500 से कम न हों;
- 5 वर्षों के लिए इंडोनेशियाई कामगारों को रोजगार देता है जो 1000 से कम न हों;
- 1 वर्ष का विस्तार, यदि एसईजेड में आर्थिक तथा सामाजिक अवसंरचना के लिए नए पूंजी निवेश की आवश्यकताओं का निवेश अथवा खर्च कम से कम आरपी 10 बिलियन है;
- 2 वर्ष का विस्तार, यदि उत्पाद विकास के लिए घरेलू तौर पर अनुसंधान तथा विकास पर खर्च करता है अथवा उत्पाद दक्षता 5 वर्षों के लिए निवेश से कम से कम 5 प्रतिशत है;
- 1 वर्ष का विस्तार, यदि घरेलू कच्ची सामग्री का प्रयोग अंतिम उत्पादों के विनिर्माण के लिए किया गया;
- 2 वर्ष का विस्तार, यदि एसईजेड में व्यापारिक प्रचालन के विस्तार में पूंजी निवेश है;
- 2 वर्षों का विस्तार, यदि निर्यात बिक्री कुल बिक्री की कम से कम 30 प्रतिशत है।

115. यह मुख्य रूप से एसईजेड क्षेत्रों में प्रचालन कर रही व्यापारिक कंपनियों और व्यापारियों को प्रदान किया जाता है।

**ख. इंडोनेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध**

116. विशेष आर्थिक क्षेत्र संबंधी कराधान, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क व्यवहार के संबंध में वित्त मंत्री के विनियम संख्या 104/2016 के अनुसार इस सुविधा के लिए आवेदन पत्र इंडोनेशियाई निवेश समन्वय बोर्ड को संबंधित केईके के प्रशासक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

117. केईके के अलावा, सरकारी विनियम संख्या 18/2015 के तहत विनियमित आय कर अलाउंस सुविधाएं निवल कर योग्य आय की समान कटौती प्रदान करती हैं। तथापि, सरकारी विनियम संख्या 96/2015 के अनुच्छेद 11 में निर्धारित किए गए अनुसार केईके में करदाता निवल कर योग्य आय की कटौती की सुविधा तथा किसी अन्य आय कर सुविधा के लिए सरकारी विनियम संख्या 96/2015 के तहत अपेक्षा के माध्यम से आवेदन कर सकता है। इस प्रकार, कंपनी के लिए दोहरी आय कर सुविधा प्राप्त करना असंभव है। यह सुविधा केईके क्षेत्र के अंतर्गत प्रचालन करने वाली व्यापारिक कंपनियों/व्यापारियों के लिए सीमित है। किसी भी जांचाधीन कंपनी ने जांच की अवधि के दौरान केईके में स्थित अथवा इस कार्यक्रम के लिए आवेदन नहीं किया है, उपार्जन नहीं किया है अथवा लाभ प्राप्त नहीं किए हैं।

**ग. प्राधिकारी द्वारा जांच**

118. इस कार्यक्रम में व्यापारी उद्यम को हानियों को अग्रेणीत करने का प्रावधान है। सब्सिडी कार्यक्रम में उस छोड़े गए राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है जो अंततः देय है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह केईके में स्थित उद्यम विशेष के लिए है। तथापि, किसी भी प्रतिभागी कंपनी के बारे में यह दावा नहीं किया गया है कि उसने जांच की अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के लिए आवेदन नहीं किया है, उपार्जन नहीं किया है अथवा लाभ प्राप्त नहीं किए हैं। प्राधिकारी सत्यापन होने तक अनंतिम रूप से यह मानते हैं कि इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई प्रतिकारी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता नहीं है।

**(xiv) कार्यक्रम संख्या 15: आयात शुल्क को बाद के लिए स्थगित करना**

**क. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध**

119. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि इंडोनेशियाई सरकार पूंजीगत सामानों और उपस्करों, प्रसंस्करण के लिए सामानों और सामग्री पर आयात शुल्क के भुगतान को बाद के लिए स्थगित करती है। यह मुख्य रूप से एसईजेड क्षेत्रों में प्रचालन करने वाली व्यापारिक कंपनियों तथा व्यापारियों को प्रदान की जाती है।

**ख. इंडोनेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध**

120. केईके की स्थापना केईके नेशनल काउंसिल द्वारा की गई है। केईके नेशनल काउंसिल का एक प्रमुख दायित्व यह निर्धारित करना है कि केईके में मुख्य व्यापार बनने के लिए कौन से व्यापारिक क्षेत्र हैं। उन क्षेत्रों में वृक्षारोपण, संभारिकी से लेकर पर्यटन तक विकसित किए जाने की संभावनाएं हैं।

121. केईके नेशनल काउंसिल प्रत्येक केईके में प्रशासक की स्थापना सहित कार्यान्वयन निष्पादित करने के लिए क्षेत्रीय परिषदें बनाती है। क्षेत्रीय परिषद भी प्रत्येक केईके में अपने प्रबंध निष्पादन के बारे में केईके नेशनल काउंसिल को रिपोर्ट करती है।
122. सरकारी विनियम संख्या 96/2015 में निर्धारित किए गए अनुसार, केईके में आयात शुल्क के भुगतान को आगे के लिए स्थगित करने का कार्य धारक प्रणाली के माध्यम से प्रचालित किया जाता है। इस सुविधा के लिए आवेदन पत्र संबंधित केईके प्रशासक के माध्यम से वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कार्यक्रम की आवेदन पत्र प्रक्रिया आयात संबंधी सामान्य विनियम के अनुरूप है। कंपनी अपने आयातों का सीमा शुल्क अधिसूचित करती है और मानक सीमा शुल्क प्रपत्र प्रस्तुत करती है। किसी भी जांचाधीन कंपनी ने जांच की अवधि के दौरान केईके में स्थित अथवा इस कार्यक्रम के लिए आवेदन नहीं किया है, उपार्जन नहीं किया है अथवा लाभ प्राप्त नहीं किए हैं।

**ग. प्राधिकारी द्वारा जांच**

123. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम में उद्यम के लिए आयात शुल्क को आगे के लिए स्थगित करने का प्रावधान है। इस प्रकार, इस कार्यक्रम में करों के स्थगन का प्रावधान है। उद्यम को प्रदत्त लाभ ब्याज मुक्त अल्पावधि और दीर्घावधि ऋण के रूप में है। इस लाभ की राशि वाणिज्यिक ऋण पर बैंक द्वारा लगाए गए ब्याज की राशि के बराबर है।
124. इस कार्यक्रम में छोड़े गए राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित किसी उद्यम को लाभ प्रदान करता है। तथापि, प्राधिकारी ने निर्धारित किया है कि प्रतिकारी शुल्क बांडेड जोन कार्यक्रम के लिए और प्रतिभागी कंपनियों को आयात शुल्क से छूट प्रदान करने वाले अन्य दो आयात शुल्क छूट कार्यक्रमों (अन्य कार्यक्रमों) के लिए लगाया जाना चाहिए। अतः प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह निर्धारित करता है कि इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई अतिरिक्त प्रतिकारी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता नहीं है।

**(xv) कार्यक्रम संख्या 16: उत्पादन प्रयोजन के लिए कच्ची सामग्री तथा सहायक सामानों पर शुल्क की छूट क. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध**

125. इंडोनेशियाई सरकार उन निवेशकों के लिए कच्ची सामग्री और सहायक सामानों पर शुल्क की छूट प्रदान करती है जो एसईजेड में अपने उत्पादन का विस्तार कर रहे हैं।
126. यह कर लाभ दो श्रेणियों को उपलब्ध है:
- एसईजेड के व्यापारिक क्रियाकलाप आयोजित करने वाला करदाता-
  - एसईजेड विकसित करने वाली अथवा उनका प्रबंधन करने वाली व्यापारिक कंपनी होने के लिए संगत सरकारी एजेंसी द्वारा पंजीकृत।
  - सरकारी एजेंसी के साथ एसईजेड के संबंध में करार हों।
  - एसईजेड के क्रियाकलापों की संगत सीमाएं सृजित करें।
  - एसईजेड में व्यापार करने वाले करदाता-
  - जिनके पास एसईजेड के प्रशासक के लिए वैध नई पूंजी निवेश योजना हो।
  - जिनके पास सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क महानिदेशक से जुड़ी कोई सूचना प्रणाली हो।

**ख. इंडोनेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध**

127. सरकारी विनियम संख्या 96/2015 के अनुच्छेद 19 में निर्धारित किए गए अनुसार केईके में उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री तथा सहायक सामानों पर शुल्क की छूट किसी अवधि के लिए उद्योग के विकास और विस्तार हेतु व्यापारिक कंपनियों और व्यापारियों को दी जाती है।
128. वित्त मंत्री के विनियम संख्या 104/2016 के अनुच्छेद 40 एवं 41 में निर्धारित किए गए अनुसार, व्यापारिक कंपनियों द्वारा पूंजीगत सामानों के आयात पर 3 वर्ष के लिए आयात शुल्क से छूट दी जाती है जबकि व्यापारी पूंजीगत सामान और/अथवा सामग्री के लिए 2 वर्षों के लिए आयात शुल्क की छूट प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि

आगे उल्लेख किया गया है, छूट के अध्यधीन सामानों का प्रकार एवं राशि केईके प्रशासक द्वारा निर्धारित की जाती है और आयातित सामानों का प्रयोग केवल केईके क्षेत्र के अंतर्गत ही किया जा सकता है।

129. यह कार्यक्रम संबंधित केईके के प्रशासक के माध्यम से सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित किया जाता है। किसी भी जांचाधीन कंपनी ने जांच की अवधि के दौरान केईके में स्थित अथवा इस कार्यक्रम के लिए आवेदन नहीं किया है, उपार्जन नहीं किया है अथवा लाभ प्राप्त नहीं किए हैं।

**क. प्राधिकारी द्वारा जांच**

130. इस कार्यक्रम में छोड़े गए राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह केईके क्षेत्र में स्थित किसी उद्यम को लाभ प्रदान करता है। तथापि, प्राधिकारी ने निर्धारित किया है कि प्रतिकारी शुल्क बांडेड जोन कार्यक्रम के लिए और प्रतिभागी कंपनियों को आयात शुल्क से छूट प्रदान करने वाले अन्य दो आयात शुल्क छूट कार्यक्रमों (अन्य कार्यक्रमों) के लिए लगाया जाना चाहिए। अतः प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह निर्धारित करता है कि इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई अतिरिक्त प्रतिकारी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता नहीं है।

**(xvi) कार्यक्रम संख्या 17: आयातों पर आय कर से छूट**

**क. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध**

131. इंडोनेशियाई सरकार, यदि कंपनी एसईजेड में स्थित है तो, कुछ सामानों के आयातों पर आय कर में छूट प्रदान करती है।
132. यह कर लाभ दो श्रेणियों को उपलब्ध है:

- एसईजेड के व्यापारिक क्रियाकलाप आयोजित करने वाला करदाता-
- एसईजेड विकसित करने वाली अथवा उनका प्रबंधन करने वाली व्यापारिक कंपनी होने के लिए संगत सरकारी एजेंसी द्वारा पंजीकृत।
- सरकारी एजेंसी के साथ एसईजेड के संबंध में करार हों।
- एसईजेड के क्रियाकलापों की संगत सीमाएं सृजित करें।
- एसईजेड में व्यापार करने वाले करदाता-
- जिनके पास एसईजेड के प्रशासक के लिए वैध नई पूंजी निवेश योजना हो।
- जिनके पास सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क महानिदेशक से जुड़ी कोई सूचना प्रणाली हो।

**ख. इंडोनेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध**

133. सरकारी विनियम संख्या 96/2015 के अनुच्छेद 19 में निर्धारित किए गए अनुसार केईके में आयातों पर आय कर की छूट सीमा शुल्क क्षेत्र के बाहर से केईके में व्यापारियों; केईके के अंतर्गत अन्य व्यापारियों; अन्य केईके में अन्य व्यापारियों, केईके से बाहर बांडेड जोनों; मुक्त व्यापार क्षेत्र तथा मुक्त पत्तन; और/अथवा अन्य क्षेत्रीय टीएलडीपीपी को निर्दिष्ट सामानों के लिए लागू की जाती है। इस सुविधा के लिए आवेदन पत्र संबंधित केईके के प्रशासक के माध्यम से वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। किसी भी जांचाधीन कंपनी ने जांच की अवधि के दौरान केईके में स्थित अथवा इस कार्यक्रम के लिए आवेदन नहीं किया है, उपार्जन नहीं किया है अथवा लाभ प्राप्त नहीं किए हैं।

**ग. प्राधिकारी द्वारा जांच**

134. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सरकारी विनियम संख्या 96/2015 के अनुच्छेद 19 में निर्धारित किए गए अनुसार व्यावसायिक इकाइयों और व्यवसायियों को एक निश्चित अवधि के लिए उद्योग के विकास एवं विस्तार हेतु केईके में उत्पादन के लिए कच्चे माल तथा सहायक वस्तुओं पर शुल्क में छूट दी जाती है।
135. इस कार्यक्रम के अंतर्गत छूट से आय कर का भुगतान आस्थगित हो जाता है चूंकि आयात पर भुगतान किया गया आय कर वार्षिक आय कर भुगतान की एक किस्त होता है। इस कार्यक्रम में निधि के प्रत्यक्ष अंतरण के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है। इसमें लाभ व्यावसायिक बैंक से ऐसी आस्थगित राशि हेतु लिए गए ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज के बराबर होता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह केईके क्षेत्र में स्थित कुछ उद्योगों को लाभ प्रदान करता है। तथापि पीओआई के दौरान इसमें भाग लेने वाली किसी भी कंपनी द्वारा

इस कार्यक्रम के तहत लाभ हेतु आवेदन करने, लाभ के उपार्जन, या लाभ प्राप्त करने का दावा नहीं किया गया है। इसलिए प्राधिकारी ने आगे की जांच जारी रहने तक अनंतिम रूप से निर्णय लिया है कि इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई प्रतिकारी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता नहीं है।

**(xvii) कार्यक्रम सं. 18: सेज में निवेश कर रहे निवेशकों के लिए कमी**

**क. घरेलू उद्योग का पक्ष**

136. याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इंडोनेशिया की सरकार सेज में निवेश कर रहे निवेशकों को आय कर में कम से कम 10 वर्ष तथा अधिकतम 25 वर्ष के लिए 20-100% तक और कम से कम 5 वर्ष तथा अधिकतम 15 वर्ष के लिए 20-100% तक की छूट प्रदान करती है। विशेष आर्थिक जोन में सीमा शुल्क, तथा उत्पाद शुल्क संबंधी नियमों में प्रावधान है कि करदाता:

- नया करदाता होना चाहिए;
- नया पूंजीगत निवेश करे या नए पूंजीगत निवेश का विस्तार करे;
- इसका व्यवसाय क्षेत्र सेज में प्रमुख व्यवसाय के अनुरूप हो;
- डीईआर आवश्यकताओं को पूरा करता हो;
- इसने निवेश मूल्य के कम से कम 10% के डिपॉजिट के साथ इंडोनेशिया में बैंकिंग संस्थाओं में निधि जमा कराने के लिए आशय पत्र प्रस्तुत कर दिया हो;
- उसके पास 15 अगस्त, 2011 से कानूनी इकाई का दर्जा हो।

**ख. इंडोनेशिया सरकार/अन्य इच्छुक पार्टियों का पक्ष**

137. सरकारी विनियम संख्या 96/2015 में निर्धारित किए गए अनुसार केईके में निवेश करने वाले निवेशकों या कर छूट प्रोत्साहन के लिए आय कर में छूट को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

क) निवेश > 1 ट्रिलियन रुपये, 10-25 वर्ष के लिए आय कर में 20-100% के बीच छूट;

ख) निवेश = 500 बिलियन रुपये – 1 ट्रिलियन रुपये, 5-15 वर्ष के लिए आय कर में 20-100% के बीच छूट;

ग) निवेश < 500 बिलियन रुपये, 5-15 वर्ष के लिए आय कर में 20-100% के बीच छूट;

138. निर्धारित अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए आय कर में कमी की राशि एक समान रहेगी। यह सुविधा विशेष रूप से केईके में मुख्य व्यवसाय प्रचालन से प्राप्त आय पर दी जाती है। तथापि इसके मुख्य प्रचालन के अतिरिक्त किन्हीं अन्य क्रियाकलापों से प्राप्त आय अभी भी कर लगाए जाने के शर्ताधीन है। इस सुविधा के लिए आवेदन संबंधित केईके के प्रशासक के माध्यम से इंडोनेशिया निवेश समन्वय बोर्ड को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

139. सरकारी विनियम संख्या 96/2015 के अनुच्छेद 7 के अनुसार वित्त मंत्रालय करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर आय कर में छूट की अवधि तथा राशि का निर्धारण करता है। छूट की राशि का निर्धारण करने के लिए वित्त मंत्रालय सत्यापन समिति का गठन करता है।

140. इसके लिए पात्रता केईके क्षेत्र के अंदर प्रचालन करने वाली व्यावसायिक इकाइयों/व्यवसायियों तक सीमित है। पीओआई के दौरान जांच के अधीन किसी भी कंपनी ने इस कार्यक्रम से लाभ के लिए आवेदन, लाभ का उपार्जन, या लाभ प्राप्त नहीं किया या केईके में स्थापित नहीं हुई।

**ग. प्राधिकारी द्वारा जांच**

141. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम में आय कर में छूट प्रदान की गई है। प्राधिकारी ने पहले से ही निर्धारित किया हुआ है कि आय कर में कमी या छूट प्रदान करने वाले सब्सिडी कार्यक्रम से वित्तीय अंशदान छोड़े गए राजस्व में बदल जाता है जो अन्यथा देय होता है। यह सब्सिडी कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह सरकारी विनियम के अनुसार निवेश करने वाले कुछ निश्चित उद्योगों पर लागू होता है।

142. तथापि पीओआई के दौरान इसमें भाग लेने वाली किसी भी कंपनी द्वारा इस कार्यक्रम के तहत लाभ हेतु आवेदन करने, लाभ के उपार्जन, या लाभ प्राप्त करने का दावा नहीं किया गया है। इसलिए प्राधिकारी ने सत्यापन किए जाने तक अनंतिम रूप से निर्णय लिया है कि इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई प्रतिकारी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता नहीं है।



**(xviii) कार्यक्रम संख्या 19: अग्रणी उद्योग दर्जा****क. घरेलू उद्योग का पक्ष**

143. इंडोनेशिया सरकार ने अग्रणी उद्योग कर लाभ कार्यक्रम शुरू किया। पीओआई में कार्यक्रम की स्थिति और इसकी वर्तमान स्थिति के अनुसार यह कार्यक्रम कुछ कॉर्पोरेट करदाताओं को आय कर में पाँच से पंद्रह वर्ष के लिए 10 से 100 प्रतिशत तक की छूट प्रदान करता है। कर में छूट कॉर्पोरेशन के व्यावसायिक उत्पादन के समय के प्रथम वर्ष से प्रारंभ होती है। कर में छूट प्राप्त करने वाला कॉर्पोरेशन “संवर्धित मूल्य तथा उच्च बाह्यता प्रदान करने वाले, नई प्रौद्योगिकी लाने वाले, और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए नीतिगत मूल्य के साथ विस्तृत अंतरसंबंधों वाले” उद्योग के रूप में परिभाषित एक “अग्रणी उद्योग” होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुल निवेश मूल्य को देखते हुए कॉर्पोरेशन को उच्च प्रौद्योगिकी लाने वाले सूचना, संचार एवं प्रौद्योगिकी (आईसीटी) क्षेत्र को छोड़ कर अग्रणी उद्योगों के सभी क्षेत्रों के लिए कम से कम आईडीआर 1,000,000,000,000.00 (एक ट्रिलियन रुपिया) का निवेश करना होगा। आईसीटी क्षेत्र में लाभ के लिए पात्र होने हेतु कॉर्पोरेशन को न्यूनतम आईडीआर 500,000,000,000.00 (पाँच सौ बिलियन रुपिया) का निवेश करना होगा। इसके अतिरिक्त, कॉर्पोरेशन को कर में छूट के लिए अन्य आवश्यकताओं को पूरा करना होगा जैसे निवेश योजना की कम से कम 10 प्रतिशत राशि इंडोनेशिया के बैंकों में जमा करना, ऋण तथा इक्विटी में कम से कम 4:1 का अनुपात रखना, और 15 अगस्त, 2011 से इंडोनेशिया की कानूनी रूप से वैध इकाई का दर्जा प्राप्त होना।
144. इस कार्यक्रम के अंतर्गत उद्यमों को प्राप्त लाभों में सरलीकृत पर्यावरणीय रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ तथा लाइसेंसिंग आवश्यकताएँ, वित्तीय प्रोत्साहन जैसे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय, दोनों स्तरों पर कर प्रोत्साहन तथा करमुक्त आय, क्षेत्रीय करों या लेवी में कमी, करमुक्त आय या छूट शामिल है।

**ख. इंडोनेशिया सरकार/अन्य इच्छुक पार्टियों का पक्ष**

145. अग्रणी उद्योग दर्जे को “संवर्धित मूल्य तथा उच्च बाह्यता प्रदान करने वाले, नई प्रौद्योगिकी लाने वाले, और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए नीतिगत मूल्य के साथ विस्तृत अंतरसंबंधों वाले” उद्योग के रूप में परिभाषित किया गया है। तथापि यह दर्जा केवल कर प्रोत्साहन कार्यक्रम के लिए पात्र है न कि करमुक्त आय सुविधा के लिए जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा कहा गया है।
146. अग्रणी उद्योगों में 18 क्षेत्र शामिल हैं। तथापि यह सूची परिपूर्ण नहीं है। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्रालय के अनुमोदन के शर्ताधीन कार्यक्रम में वर्तमान में निर्धारित क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों के लिए अवसर खुले हैं। इस प्रकार यह कार्यक्रम कुछ सेक्टरों या क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। परंतु कथित निर्यातकों में से किसी ने भी इस कार्यक्रम के तहत लाभ के लिए न तो आवेदन किया और न ही लाभ प्राप्त किया।

**ग. प्राधिकारी द्वारा जांच**

147. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम में आय कर में छूट प्रदान की गई है। प्राधिकारी ने पहले से ही निर्धारित किया हुआ है कि आय कर में कमी या छूट प्रदान करने वाले सब्सिडी कार्यक्रम से वित्तीय अंशदान छोड़े गए राजस्व में बदल जाता है जो अन्यथा देय होता है। यह सब्सिडी कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह अग्रणी उद्योग का दर्जा प्राप्त कुछ निश्चित उद्योगों पर लागू होता है।
148. तथापि पीओआई के दौरान इसमें भाग लेने वाली किसी भी कंपनी द्वारा इस कार्यक्रम के तहत लाभ हेतु आवेदन करने, लाभ के उपार्जन, या लाभ प्राप्त करने का दावा नहीं किया गया है। इसलिए प्राधिकारी ने सत्यापन किए जाने तक अनंतिम रूप से निर्णय लिया है कि इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई अतिरिक्त प्रतिकारी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता नहीं है।

**(xix) कार्यक्रम संख्या 21: भूमि कर में छूट****क. घरेलू उद्योग का पक्ष**

149. याचिकाकर्ता ने कहा है कि इंडोनेशिया की सरकार सेज क्षेत्र में स्थित उद्योगों को भूमि कर में लाभ प्रदान करती है।
150. यह कर लाभ दो प्रकार की श्रेणियों के लिए उपलब्ध है:

- जो उद्योग सेज में स्थित हैं:
- संबंधित सरकारी एजेंसी द्वारा एक ऐसी व्यावसायिक इकाई के रूप में पंजीकृत जो सेज का विकास या प्रबंधन करती है
- जिनका सरकारी एजेंसी के साथ सेज पर कोई करार है
- सेज के क्रियाकलापों की संगत सीमाएं बनाते हैं
- सेज में व्यवसाय करने वाले करदाता:
- जिनके पास सेज के प्रबंधक के लिए एक कानूनी रूप से वैध नई पूंजी निवेश योजना है
- महानिदेशक, सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क से जुड़ी एक सूचना प्रणाली है

#### **ख. इंडोनेशिया सरकार/अन्य इच्छुक पार्टियों का पक्ष**

151. इंडोनेशिया की कर प्रणाली में भूमि एवं भवन कर (पीबीबी) क्षेत्रीय/शहरी कर या प्रतिफल का हिस्सा है, और इसका निर्धारण क्षेत्रीय/मेयर विनियम के प्रमुख के माध्यम से क्षेत्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। अधिनियम संख्या 39/2009 में पीबीबी में छूट विनियम के अनुसार प्रदान की गई है। तथापि सरकारी विनियम संख्या 96/2015 में पर्यटन के लिए केईके में सुविधाओं के अंतर्गत पीबीबी प्रदान किया जाता है जिसमें यह प्रावधान है कि क्षेत्रीय सरकार क्षेत्रीय कर में 50% से 100% तक की कमी या छूट निर्धारित कर सकती है।
152. जैसा कि स्पष्ट है, केवल पर्यटन में प्रमुख व्यवसाय वाले केईके जैसे केईके तांजुंग केलायंग, केईके मंडालिका, केईके तांजुंग लेसुंग, केईके मोरोताई, केईके सोरोंग ने क्षेत्रीय/शहरी कर में छूट के लिए आवेदन किया। पर्यटन के लिए केईके में सुविधाओं के अंतर्गत पीबीबी प्रदान किया जाता है जिसमें यह प्रावधान है कि क्षेत्रीय सरकार क्षेत्रीय कर में 50% से 100% तक की कमी या छूट निर्धारित कर सकती है। इस जांच में शामिल किसी भी कंपनी ने इस कार्यक्रम का लाभ नहीं लिया।

#### **ग. प्राधिकारी द्वारा जांच**

153. इस कार्यक्रम के तहत एक उद्यम को भूमि कर में छूट दी जाती है यदि यह उद्यम विशेष आर्थिक जोन में स्थित है। तथापि छूट का लाभ पर्यटन से संबंधित व्यावसायिक कार्यकलाप करने वाले उद्यम को ही उपलब्ध है। इसलिए प्राधिकारी ने निर्णय लिया है कि इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई प्रतिकारी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता नहीं है।

#### **(xx) कार्यक्रम संख्या 23: वैट की वापसी**

##### **क. घरेलू उद्योग का पक्ष**

154. इंडोनेशिया सरकार कुछ मामलों में वैट वापस लौटाती है। इंडोनेशिया में कुछ पूर्व-निर्धारित प्रकार की वस्तुओं तथा सेवाओं को छोड़ कर वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति सामान्यतः वैट के शर्ताधीन है। वैट की वर्तमान दर 10% है। विद्यमान वैट कानून में यह निर्धारित किया गया है कि जिन सोने की बार, कोयले, तथा प्राकृतिक संसाधन की आपूर्ति सीधे उनके स्रोत से ली गई है, वे वैट के शर्ताधीन नहीं हैं। वैट की यह स्थिति संबंधित खनन उत्पाद की प्रोसेसिंग के स्तर के अनुसार बदल सकती है। उत्पादन-पूर्व अवधि में पूंजी वस्तुओं की खरीद पर जो इनपुट वैट दिया गया है केवल वह क्रेडिट योग्य है। इसके अतिरिक्त क्योंकि उत्पादन-पूर्व अवधि में कंपनी का कोई आउटपुट वैट नहीं होगा, इसलिए वैट का भुगतान अधिक होने की संभावना है। अधिकतर कंपनियों के लिए वैट की वापसी केवल वर्ष के अंत में उपलब्ध होती है। तथापि जो कंपनियाँ उत्पादन-पूर्व अवधि के दौरान वैट का भुगतान करती हैं वे मासिक आधार पर पूंजी वस्तुओं पर वैट के रिफंड के लिए आवेदन कर सकती हैं। लेकिन यदि उनके द्वारा इनपुट वैट क्रेडिट किए जाने की तारीख से तीन वर्ष (कुछ परिस्थितियों में पाँच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है) के अंदर उत्पादन (वैट-योग्य वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति के रूप में परिभाषित) शुरू करने में विफल रहती हैं तो उन्हें उत्पादन शुरू करने में विफल रहने की अंतिम तारीख के बाद के महीने के अंत में वैट रिफंड को वापस लौटाना होगा। विद्यमान वैट कानून में यह निर्धारित किया गया है कि जिन सोने की बार, कोयले, तथा प्राकृतिक संसाधन की आपूर्ति सीधे उनके स्रोत से ली गई है, वे वैट के शर्ताधीन नहीं हैं।

**ख. इंडोनेशिया सरकार/अन्य इच्छुक पार्टियों का पक्ष**

155. मूल्य संवर्द्धित कर (वैट) ऐसी वस्तुओं या सेवाओं के संवर्द्धित मूल्य पर लगाया जाने वाला कर है जो उत्पादक से उपभोक्ता तक परिचालित होती हैं।
156. इंडोनेशिया में वैट के लिए एकल प्रशुल्क प्रणाली है, जो 10% है। इंडोनेशिया में वैट लागू किए जाने के लिए मुख्य कानूनी आधार 1983 का कानून संख्या 8 है जिसे अंतिम बार 2009 के कानून संख्या 42 के साथ संशोधित किया गया था।
157. मूर्त वस्तुओं के निर्यात, अमूर्त वस्तुओं के निर्यात और सेवाओं के निर्यात पर 0 प्रतिशत की वैट दर लागू होती है। वैट एक अप्रत्यक्ष कर है। वैट लेवी लागू किए जाने में करदाता एक ही वित्तीय अवधि के अंदर इनपुट कर और आउटपुट कर को क्रेडिट करेंगे। यदि वित्तीय अवधि के अंदर आउटपुट कर अधिक है तो अधिक कर आउटपुट को राजकोष में जमा किया जाना चाहिए।
158. इसके विपरीत, यदि कर अवधि में, इनपुट कर आउटपुट कर से अधिक है तो अधिक इनपुट कर को अगली कर अवधि में समायोजित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में करदाताओं द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि भुगतान किए गए इनपुट कर के अनुसार बदल सकती है। मूलभूत रूप से सभी वस्तुएँ और सेवाएँ करयोग्य वस्तुएँ और सेवाएँ हैं, इसलिए वे मूल्य संवर्द्धित कर (वैट) के शर्ताधीन हैं, केवल वस्तुओं तथा सेवाओं पर मूल्य संवर्द्धित कर पर 1983 के कानून संख्या 8 में तीसरे संशोधन से संबंधित 2009 के कानून संख्या 42 के अनुच्छेद 4ए में निर्धारित वस्तुओं के प्रकार और सेवाओं के प्रकार को छोड़ कर।
159. 2009 के कानून संख्या 42 के अनुच्छेद 4ए में यह निर्धारित किया गया है कि जो वस्तुएँ मूल्य संवर्द्धित कर के शर्ताधीन नहीं हैं वे वस्तुओं के समूहों में कुछ निश्चित वस्तुएँ होंगी: 1) अपने स्रोत से सीधे लिए जाने वाले खनन तथा ड्रिलिंग उत्पाद; 2) मूलभूत वस्तुएँ जिनकी अधिकतर लोगों को आवश्यकता होती है; 3) अंदर बैठ कर खाने तथा पैक करा कर बाहर ले जाने वाले खाने सहित, कैटरिंग कंपनियों द्वारा परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थ तथा पेय पदार्थ सहित, होटल, रेस्टोरेन्ट, फूड शॉप, दुकान, या ऐसे किसी स्थान में परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थ तथा पेय पदार्थ; और 4) पैसा, सोने की ईंट, और प्रतिभूति।
160. वैट रिफ्रंड निर्यात निष्पादन या घरेलू वस्तुओं के प्रयोग पर निर्भर नहीं है। यह प्रावधान सभी करदाताओं पर लागू होता है। वित्त मंत्रालय के 2010 के विनियम संख्या 72 के अनुच्छेद 6 में वैट की वापसी का कानूनी आधार दिया गया है। जांच में शामिल किसी भी कंपनी ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभों के लिए आवेदन, लाभ का उपार्जन, या लाभ प्राप्त नहीं किए।

**ग. प्राधिकारी द्वारा जांच**

161. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इंडोनेशिया में सभी उत्पाद वैट के शर्ताधीन हैं। तथापि खनन तथा ड्रिलिंग उत्पाद, जो सीधे अपने स्रोत से लिए जाते हैं, वैट के शर्ताधीन नहीं हैं।
162. इसके अतिरिक्त, इस कार्यक्रम के अंतर्गत वैट रिफ्रंड किया जाता है। यदि वित्तीय अवधि के अंदर आउटपुट कर अधिक है तो अधिक कर आउटपुट को राजकोष में जमा किया जाना चाहिए। यदि कर अवधि में, इनपुट कर आउटपुट कर से अधिक है तो अधिक इनपुट कर को अगली कर अवधि में समायोजित किया जा सकता है।
163. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि अलग-अलग वैट दर तय करने से ऐसे उत्पाद की अधिप्राप्ति करने वाले उद्यमों को वित्तीय अंशदान प्राप्त नहीं होता। इसके अतिरिक्त भुगतान किए गए अधिक वैट का रिफ्रंड भी वित्तीय अंशदान नहीं है क्योंकि इससे राजस्व देना छूट नहीं जाता जो अन्यथा देय है।

**(xxi) अन्य कार्यक्रम 1: बॉडेड जोन****क. घरेलू उद्योग का पक्ष**

164. घरेलू उद्योग ने अपनी याचिका में इस कार्यक्रम के अस्तित्व के बारे में नहीं कहा है।

**ख. इंडोनेशिया सरकार/अन्य इच्छुक पार्टियों का पक्ष**

165. एक "बॉडेड जोन" को एक बंद भंडारण स्थल के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका प्रयोग इन्हें प्रोसेस या असेंबल करने के लिए सीमा शुल्क क्षेत्र में अन्य स्थानों से दूर आयातित वस्तुओं और/या वस्तुओं के भंडारण के

लिए किया जाता है। तथापि जैसा कि वित्त मंत्रालय के विनियम संख्या 147/पीएमके.04/2013 में निर्धारित किया गया है, बॉर्डर जोन को सीमा शुल्क क्षेत्र के भाग के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसे सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क महानिदेशालय के पूर्ण पर्यवेक्षण में प्रचालित किया जाता है। क्योंकि यह इंडोनेशिया सीमा शुल्क क्षेत्र का हिस्सा है जो कि तटस्थ है, इसलिए बॉर्डर जोन में प्रवेश करने वाली वस्तुओं को अभी भी पूरी तरह से आयातित वस्तुएँ नहीं माना जाता। इस अवधारणा के अनुसार सीमा शुल्क विभाग आयात शुल्क, आय कर, मूल्य संवर्द्धित कर (वैट), लगजरी कर, और उत्पाद शुल्क एकत्र नहीं कर सकता।

166. कच्चे माल और पूंजीगत वस्तुओं पर वैट आयात छूट एससीएम के अनुरूप है। आयात सामग्री और पूंजीगत वस्तुओं पर आय कर में छूट आय कर के संबंध में भी लाभ नहीं पहुंचाते क्योंकि आयात वार्षिक रूप से देय आय कर का एक भाग है। पूंजीगत वस्तुओं और सामग्री के आयात पर आयात शुल्क को निलंबित करने का वास्तविक लाभ नहीं होता क्योंकि आयात की गई सामग्री 0% से अधिकतम 5% तक के अधिमान्य आयात प्रशुल्क के शर्ताधीन है।

#### ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

167. प्राधिकारी नोट करते हैं कि बॉर्डर जोन में आयात के लिए आयात शुल्क में छूट दी जाती है। सहभागी कंपनियाँ पीटी इंडोनेशिया सिंगशन स्टेनलेस स्टील, पीटी गुयांग चिंग निकल एंड स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री, पीटी इंडोनेशिया रूईपू निकल एंड क्रोम एलोय, पीटी सिंगशन स्टील इंडोनेशिया, पीटी सुलावेसी माइनिंग इनवेस्टमेंट बॉर्डर जोन में स्थित हैं और इन्हें बॉर्डर जोन में आयात की जाने वाली पूंजीगत वस्तुओं पर शुल्क में छूट के संबंध में सूचना दी जाती है।
168. प्राधिकारी नोट करते हैं कि बॉर्डर जोन में आयात की गई वस्तुओं पर आयात शुल्क में छूट से वित्तीय अंशदान छोड़े गए राजस्व में बदल जाता है जो अन्यथा देय होता है। लाभ की राशि आयात पर आयात शुल्क और आयात पर भुगतान किए गए आय कर तथा आयात शुल्क के बीच के अंतर के समान है। प्राधिकारी ने निर्धारित किया है कि इस कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।

#### (xxii) अन्य कार्यक्रम 2: अनुच्छेद 32 के तहत आयात आय कर में छूट

##### क. घरेलू उद्योग का पक्ष

169. घरेलू उद्योग ने अपनी याचिका में इस कार्यक्रम के अस्तित्व के बारे में नहीं कहा है।

##### ख. इंडोनेशिया सरकार/अन्य इच्छुक पार्टियों का पक्ष

170. कर महानिदेशालय के विनियम संख्या 1/पीजे/2011 के तहत इंडोनेशिया सरकार ऐसे करदाताओं को अंतिम रूप से निर्धारित आय कर तथा आयात आय कर में छूट देती है जो (1) कुछ कारणों से वित्तीय नुकसान का सामना करते हैं जैसे क) नया करदाता निवेश के चरण में है; ख) करदाता व्यावसायिक प्रचालन के चरण में नहीं है; या ग) कोई अप्रत्याशित घटना; (2) वित्तीय हानि की प्रतिपूर्ति का पात्र हो और (3) भुगतान किए गए आय कर की राशि देय आय कर से अधिक हो।
171. जो करदाता उपर्युक्त मानदंडों को पूरा करते हैं वे सहायक दस्तावेजों जैसे पिछले वर्ष के अधिसूचना पत्र आदि के साथ स्थानीय कर कार्यालय में एक लिखित आवेदन के माध्यम से छूट हेतु निवेदन कर सकते हैं। यदि उन्हें छूट दी जाती है तो यह छूट अंतिम रूप से निर्धारित आय कर पर 10% या आयात आय कर पर 2.5% की दर से लागू होगी और उसी कर वर्ष के लिए होगी। 2.5% की दर से आयात आय कर में छूट लाभ नहीं पहुंचाती क्योंकि यह वार्षिक रूप से देय आय कर का हिस्सा होती है।

#### प्राधिकारी द्वारा जांच

172. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत वह उद्यम इस सुविधा के लिए आवेदन कर सकता है जो (1) कुछ कारणों से वित्तीय नुकसान का सामना करता है जैसे नया करदाता निवेश के चरण में है, करदाता व्यावसायिक प्रचालन के चरण में नहीं है, कोई अप्रत्याशित घटना या (2) वित्तीय हानि की प्रतिपूर्ति का पात्र हो और (3) भुगतान किए गए आय कर की राशि देय आय कर से अधिक हो। यदि उन्हें छूट दी जाती है तो यह

छूट अंतिम रूप से निर्धारित आय कर पर 10% या आयात आय कर पर 2.5% की दर से लागू होगी और उसी कर वर्ष के लिए होगी।

173. पीटी आईएमआर एआरसी स्टील ने \*\*\* % की दर से छूट प्राप्त की। इस कार्यक्रम के अंतर्गत छूट से आय कर का भुगतान आस्थगित होता है चूंकि आयात पर भुगतान किया गया आय कर वार्षिक रूप से भुगतान किए जाने वाले आय कर का हिस्सा होता है। इस कार्यक्रम में निधि के प्रत्यक्ष अंतरण के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है। इसमें लाभ व्यावसायिक बैंक से ऐसी आस्थगित राशि पर प्राप्त किए गए ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज के समान होता है। प्राधिकारी प्रारंभिक तौर पर यह निर्धारित करता है कि इस कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।

### (xxiii) अन्य कार्यक्रम 3: मशीनरी और पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए निवेश सुविधा

#### क. घरेलू उद्योग का पक्ष

174. घरेलू उद्योग ने अपनी याचिका में इस कार्यक्रम के अस्तित्व के बारे में नहीं कहा है।

#### ख. इंडोनेशिया सरकार/अन्य इच्छुक पार्टियों का पक्ष

175. 2015 के सरकारी विनियम संख्या 81 (जीआर 81/2015) में नीतिगत वस्तुओं के आयात का प्रावधान किया गया है, जिसमें अन्य वस्तुओं के साथ-साथ नए स्थापित उद्योग और/अथवा उद्योग के विस्तार द्वारा उत्पादन के लिए संस्थापित तथा प्रयुक्त मशीनरी और फैक्टरी उपकरण शामिल हैं, जिनके लिए आयात शुल्क और वैट में छूट के रूप में आयात सुविधा प्राप्त की जा सकती है।
176. आयात शुल्क में छूट के लिए पहले प्रस्तावित मदों तथा आयातित वस्तुओं के मूल्य को पर्यवेक्षण एजेंसियों, नामतः BKPM के समक्ष प्रस्तावित किया जाएगा और उनके द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, और वैट में छूट के लिए आयात करने वाली कंपनियाँ कर महानिदेशालय के अंतर्गत स्थानीय कर कार्यालय के समक्ष प्रस्ताव रख सकती हैं और उनका अनुमोदन ले सकती हैं।
177. आयात की जाने वाली मशीनरी और उपकरणों का प्रयोग केवल आयात करने वाले उद्योगों द्वारा किया जाएगा (गैर-हस्तांतरणीय) और केवल आवेदन में उल्लिखित अभीष्ट प्रयोजन से किया जाएगा।

#### ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

178. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम के तहत नई इकाइयों के लिए और विस्तार करने वाली इकाइयों के लिए माल के आयात को सीमा शुल्क और वैट से छूट दी गई है। इंडोनेशिया में वैट की सामान्य दर 10% है। पीटी आईएमआर एआरसी ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत वैट में छूट प्राप्त की है। यदि वैट देय है तो करदाता आउटपुट कर भुगतान के सामने इनपुट कर क्रेडिट करेंगे।
179. पीटी आईएमआर एआरसी को इस कार्यक्रम के तहत पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर छूट मिली। पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क की छूट से राजस्व के पूर्वगामी रूप में वित्तीय योगदान होता है जो अन्यथा होता है। लाभ की राशि पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर भुगतान सीमा शुल्क की राशि और इस कार्यक्रम के तहत छूट के अभाव में देय सीमा शुल्क की राशि के बराबर है। पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर वैट से छूट वित्तीय योगदान प्रदान नहीं करती है क्योंकि इससे राजस्व में कमी नहीं होती है जो अन्यथा होती है। प्राधिकारी अंतिम रूप से यह निर्धारित करते हैं कि पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क में छूट के लिए इस कार्यक्रम के खिलाफ काउंटरवेलिंग झूठी लगाई जानी चाहिए।

#### इंडोनेशिया के उत्पादक/निर्यातक

#### पीटी गुयांग चिंग निकेल एंड स्टेनलैस स्टील इंडस्ट्री (जीसीएनएस)

180. पीटी गुयांग चिंग निकेल एंड स्टेनलैस स्टील इंडस्ट्री इंडोनेशिया में सबजेक्ट उत्पाद की उत्पादक/निर्यातक है। पीटी जीसीएनएस ने प्रश्नावली का उत्तर दाखिल किया है और इसके द्वारा प्राप्त की गई सब्सिडी के संबंध में सूचना प्रदान की है। इंडोनेशिया में संबंधित कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं \*\*\* और \*\*\* ने भी प्रश्नावली का उत्तर दाखिल किया है। पीटी जीसीएनएस ने संबंधित ट्रेडर्स नामतः \*\*\*, \*\*\*, के माध्यम से और \*\*\* के माध्यम से भारत को सबजेक्ट उत्पाद का निर्यात किया है। सभी तीनों संबंधित निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर दाखिल कर दिया है।
181. पीटी जीसीएनएस इंडोनेशिया में अन्य उत्पादक/निर्यातक \*\*\* और \*\*\* से संबंधित है, और इन्होंने भी अलग से प्रश्नावली के उत्तर दाखिल किए हैं।

182. प्राधिकारी ने पीटी जीसीएनएस, इसके संबंधित कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं और इसके संबंधित निर्यातकों के उत्तर की जांच की है। इन उत्तरों की जांच के बाद प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबंधित निर्यातक भारत को निर्यात करने के लिए इंडोनेशिया में अन्य आपूर्तिकर्ताओं से भी सबजेक्ट वस्तुएँ खरीद रहे हैं। तथापि संबंधित निर्यातकों द्वारा भारत को ट्रांजेक्शन दर ट्रांजेक्शन निर्यात के बारे में प्रदान की गई सूचना में इंडोनेशिया में उत्पादक का नाम नहीं दर्शाया गया है। प्रश्नावली के उत्तर की जांच के आधार पर प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि भारत को एक निर्यात ट्रांजेक्शन में भारत में अंतिम रूप से उपभोक्ता को वस्तुओं का निर्यात किए जाने से पहले एक से अधिक संबंधित ट्रेडर इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं परंतु प्रश्नावली के उत्तर में दी गई सूचना के आधार पर कोई स्पष्ट निर्यात मूल्य श्रृंखला निर्धारित नहीं की गई है या पहचानी नहीं जा सकती। प्रश्नावली के उत्तर में दी गई सूचना के आधार पर प्राधिकारी पीटी जीसीएनएस के लिए विशिष्ट निर्यात मूल्य का निर्धारण करने में असमर्थ है। संबंधित निर्यातकों द्वारा प्रश्नावली के उत्तर में प्राधिकारी द्वारा अपनी जांच में प्रस्तावित पीसीएन (PCN) के अनुसार सूचना भी नहीं दी गई है। इस प्रकार प्राधिकारी नोट करता है कि पीटी जीसीएनएस और इसके संबंधित निर्यातकों द्वारा प्रदान की गई सूचना पूर्ण नहीं है और कई पहलुओं पर इसमें कमी है। तथापि पीटी जीसीएनएस द्वारा भारत को ट्रांजेक्शन दर ट्रांजेक्शन निर्यात के संबंध में दी गई सूचना की जांच करने के बाद प्राधिकारी नोट करता है कि पीटी जीसीएनएस ने भारत को केवल एक प्रकार की ग्रेड का निर्यात किया है। तदनुसार प्राधिकारी ने संबंधित निर्यातकों द्वारा भारत के लिए अंतिम निर्यात मूल्य के आधार पर भारत को निर्यात के लिए निर्यात मूल्य तथा लैंडेड मूल्य निर्धारित किया और पीटी जीसीएनएस और इसके संबंधित निर्यातकों द्वारा प्रश्नावली के उत्तर में प्रदान की गई सूचना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया है।
183. प्राधिकारी ने उन कार्यक्रमों के लिए, जिनके लिए इंडोनेशिया में पीटी जीसीएनएस और इसके संबंधित कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रश्नावली के उत्तर में सूचना प्रदान की गई थी, सब्सिडी मार्जिन पीओआई के दौरान प्राप्त या उपार्जित लाभ के बराबर निर्धारित किया है। यह नोट किया गया है कि पीटी जीसीएनएस और इसके संबंधित कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं ने बॉडेड जोन में आयात शुल्क से छूट संबंधी अन्य कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त किया। प्राधिकारी यह निर्धारित करता है कि सब्सिडी कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप वित्तीय अंशदान के रूप में राजस्व छूट गया जो अन्यथा देय था। इसके परिणामस्वरूप इस लाभ के प्राप्तिकर्ता के रूप में लाभ पीटी जीसीएनएस को दे दिया गया। सब्सिडी कार्यक्रम विशिष्ट भी था क्योंकि वे बॉडेड जोन में स्थित पीटी जीसीएनएस सहित कुछ उद्यमों तक सीमित थे।
184. प्राधिकारी ने सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध सूचना पर निर्भर करते हुए पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर कच्चे माल कोयला तथा निकाल अयस्क के प्रावधान के लिए सब्सिडी मार्जिन निर्धारित करने के लिए उपलब्ध तथ्यों पर निर्भर रहते हुए भी कार्यवाही की है। प्राधिकारी ने इंडोनेशिया एक्जिमबैंक द्वारा निर्यात वित्तपोषण से संबंधित कार्यक्रम के लिए सब्सिडी मार्जिन का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर भी किया है।
185. नीचे दी गई तालिका में सब्सिडी कार्यक्रमों के नाम और संगत सब्सिडी मार्जिन दिया गया है।

कार्यक्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	संक्षिप्त विवरण	सब्सिडी मार्जिन %	सब्सिडी मार्जिन श्रेणी
अन्य कार्यक्रम	बॉडेड जोन	पूँजीगत वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क तथा आय कर में छूट	***	0-5%
कार्यक्रम संख्या 1, 2 और 4	निर्यात एवं घरेलू बाजार बाध्यता की आवश्यकता के लिए न्यूनतम मूल्य संबद्धन	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर खनिजों का प्रावधान	***	15-20%
कार्यक्रम संख्या 9	इंडोनेशिया एक्जिम बैंक (Indonesia Exim Bank) की ओर से निर्यात वित्तपोषण	राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों/सार्वजनिक निकायों से ऋण के रूप में निधि का सीधा अंतरण	***	5-10%
कुल			***	20-30%

**पीटी इंडोनेशिया सिंगशन स्टील (आईटीएसएस)**

186. पीटी इंडोनेशिया सिंगशन स्टील इंडोनेशिया में संबद्ध उत्पाद की उत्पादक/निर्यातक है। पीटी आईटीएसएस इंडोनेशिया ने प्रश्नावली का उत्तर दाखिल किया है और इसके द्वारा प्राप्त की गई सब्सिडी के संबंध में सूचना प्रदान की है। इंडोनेशिया में संबंधित कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं \*\*\* और \*\*\* ने भी प्रश्नावली का उत्तर दाखिल किया है। पीटी आईटीएसएस इंडोनेशिया ने संबंधित ट्रेडर्स नामतः \*\*\*, \*\*\*,\*\*\* और \*\*\* के माध्यम से भारत को सबजेक्ट उत्पाद का निर्यात किया है। सभी चार संबंधित निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर दाखिल कर दिया है।
187. पीटी आईटीएसएस इंडोनेशिया में अन्य उत्पादक/निर्यातक \*\*\* और \*\*\* से संबंधित है, और इन्होंने भी अलग से प्रश्नावली के उत्तर दाखिल किए हैं।
188. प्राधिकारी ने पीटी आईटीएसएस, इसके संबंधित कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं और इसके संबंधित निर्यातकों के उत्तर की जांच की है। इन उत्तरों की जांच के बाद प्राधिकारी नोट करता है कि संबंधित निर्यातक भारत को निर्यात करने के लिए इंडोनेशिया में अन्य आपूर्तिकर्ताओं से भी सबजेक्ट वस्तुएँ खरीद रहे हैं। तथापि संबंधित निर्यातकों द्वारा भारत को ट्रांजेक्शन दर ट्रांजेक्शन निर्यात के बारे में प्रदान की गई सूचना में इंडोनेशिया में उत्पादक का नाम नहीं दर्शाया गया है। प्रश्नावली के उत्तर की जांच के आधार पर प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि भारत को एक निर्यात ट्रांजेक्शन में भारत में अंतिम रूप से उपभोक्ता को वस्तुओं का निर्यात किए जाने से पहले एक से अधिक संबंधित ट्रेडर इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं परंतु प्रश्नावली के उत्तर में दी गई सूचना के आधार पर कोई स्पष्ट निर्यात मूल्य श्रृंखला निर्धारित नहीं की गई है या पहचानी नहीं जा सकती। प्रश्नावली के उत्तर में दी गई सूचना के आधार पर प्राधिकारी पीटी आईटीएसएस इंडोनेशिया के लिए विशिष्ट निर्यात मूल्य का निर्धारण करने में असमर्थ है। पीटी आईटीएसएस इंडोनेशिया और इसके संबंधित निर्यातकों द्वारा प्रश्नावली के उत्तर में प्राधिकारी द्वारा अपनी जांच में प्रस्तावित पीसीएन (PCN) के अनुसार सूचना भी नहीं दी गई है। तथापि पीटी आईटीएसएस इंडोनेशिया द्वारा भारत को ट्रांजेक्शन दर ट्रांजेक्शन निर्यात के संबंध में दी गई सूचना की जांच करने के बाद प्राधिकारी नोट पीटी आईटीएसएस कि पीटी आईटीएसएस ने भारत को केवल दो प्रकार की ग्रेड का निर्यात किया है। तदनुसार प्राधिकारी ने संबंधित निर्यातकों द्वारा भारत के लिए अंतिम निर्यात मूल्य के आधार पर भारत को निर्यात के लिए निर्यात मूल्य तथा लैंडेड मूल्य निर्धारित किया और पीटी आईटीएसएस इंडोनेशिया और इसके संबंधित निर्यातकों द्वारा प्रश्नावली के उत्तर में प्रदान की गई सूचना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया है।
189. प्राधिकारी ने कार्यक्रमों के लिए सब्सिडी मार्जिन निर्धारित किए हैं, जिसके लिए इंडोनेशिया में पीटी आईटीएसएस और इसके संबंधित कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं की प्रश्नावली उत्तर में जानकारी प्रदान की गई थी, जो पीओआई के दौरान प्राप्त या अर्जित लाभ के बराबर है। यह नोट किया जाता है कि पीटी आईटीएसएस और इसके संबंधित कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं को बॉन्डेड ज़ोन में आयात शुल्क से छूट के विषय में अन्य कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त हुआ है। प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि सब्सिडी कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप राजस्व में कमी के रूप में वित्तीय योगदान का प्रावधान था जो अन्यथा देय था। परिणामस्वरूप, इस लाभ के प्राप्तकर्ता के रूप में पीटी आईटीएसएस को लाभ प्रदान किया गया। सब्सिडी कार्यक्रम भी विशिष्ट था क्योंकि वे बॉन्डेड ज़ोन में स्थित पीटी आईटीएसएस सहित कुछ उद्यम तक सीमित थे।
190. प्राधिकारी ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचनाओं पर भरोसा करके, पर्याप्त पारिश्रमिक से कम के लिए कच्चे माल कोल और निकल अयस्क के प्रावधान के लिए सब्सिडी मार्जिन का निर्धारण करने के लिए उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा किए हैं। प्राधिकारी ने इंडोनेशिया एक्जिम बैंक द्वारा निर्यात वित्तपोषण से संबंधित कार्यक्रम के लिए सब्सिडी मार्जिन निर्धारित करने के लिए उपलब्ध तथ्यों पर भी भरोसा किए हैं।
191. नीचे दी गई तालिका में सब्सिडी कार्यक्रमों और संगत सब्सिडी मार्जिन का नाम प्रदान किया गया है।

कार्यक्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	संक्षिप्त विवरण	सब्सिडी मार्जिन%	सब्सिडी मार्जिन रेंज
अन्य कार्यक्रम	बॉन्डेड ज़ोन	पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क और आयकर से छूट	***	0-2%

कार्यक्रम सं. 1, 2 और 4	निर्यात और घरेलू बाजार दायित्व की आवश्यकता के लिए न्यूनतम मूल्य संवर्धन	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर खनिजों का प्रावधान	***	15-25%
कार्यक्रम संख्या 9	इंडोनेशिया एक्जिम बैंक से निर्यात वित्तपोषण	राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों / सार्वजनिक निकायों से ऋण के रूप में निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण	***	5-10%
कुल			***	20-30%

### पीटी. इंडोनेशिया रुइपु निकल एंड क्रोम अलॉय (आईआरएनसी)

192. पीटी. इंडोनेशिया रुइपु निकल एंड क्रोम अलॉय (आईआरएनसी) इंडोनेशिया में संबद्ध उत्पाद के निर्माता/निर्यातक हैं। पीटी आईआरएनसी ने प्रश्नावली उत्तर दायर की है और इसके द्वारा प्राप्त सब्सिडी के बारे में जानकारी प्रदान की \*\*\* और \*\*\* में संबंधित कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं ने भी प्रश्नावली का उत्तर दिया है। पीटी आईआरएनसी ने संबंधित व्यापारियों के माध्यम से भारत में \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, \*\*\* और \*\*\* के माध्यम से विषय उत्पाद का निर्यात किया है। सभी संबंधित निर्यातकों ने प्रश्नावली उत्तरों को दर्ज किया है।
193. पीटी. आईआरएनसी इंडोनेशिया में अन्य निर्माता/निर्यातकों \*\*\*, \*\*\* से संबंधित है, जिन्होंने पृथक प्रश्नावली उत्तरों को भी दर्ज किया है।
194. प्राधिकारी, पीटी आईआरएनसी, इसके संबंधित कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं और इसके संबंधित निर्यातकों द्वारा दायर प्रतिक्रिया की जांच करते हैं। इन उत्तरों की जांच करने पर, प्राधिकारी ध्यान देते हैं कि संबंधित निर्यातक भारत में निर्यात के लिए इंडोनेशिया में अन्य आपूर्तिकर्ताओं से भी संबद्ध वस्तु खरीद रहे हैं। हालाँकि, भारत को लेन-देन के निर्यात द्वारा लेन-देन के संबंध में संबंधित निर्यातकों द्वारा दी गई जानकारी इंडोनेशिया में निर्माता के नाम का खुलासा नहीं करती है। प्रश्नावली उत्तरों की जांच के आधार पर, प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि भारत को दिए गए निर्यात लेनदेन में, एक से अधिक संबंधित व्यापारी शामिल हैं, इससे पहले कि माल भारत में ग्राहक को निर्यात किया जाता है, लेकिन प्रश्नावली प्रतिक्रिया में दी गई जानकारी पर कोई स्पष्ट निर्यात मूल्य श्रृंखला निर्धारित नहीं है या पहचान योग्य नहीं है। प्राधिकारी प्रश्नावली उत्तर में प्रदान की गई जानकारी के आधार पर पीटी आईआरएनसी के लिए विशिष्ट निर्यात मूल्य निर्धारित करने में असमर्थ है। पीटी आईआरएनसी और उसके संबंधित निर्यातकों द्वारा प्रश्नावली की प्रतिक्रिया भी इस जांच में प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावित पीसीएन के अनुसार जानकारी प्रदान नहीं की है। हालाँकि, पीटी आईआरएनसी द्वारा भारत को प्रदान किए गए लेन-देन निर्यात द्वारा लेनदेन की जांच करने पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीटी आईआरएनसी ने भारत को केवल एक प्रकार का ग्रेड निर्यात किया है। प्राधिकारी ने तदनुसार निर्यात मूल्य निर्धारित किए हैं और संबंधित निर्यातकों द्वारा भारत को अंतिम निर्यात मूल्य के आधार पर निर्यात के लिए भारत को निर्यात मूल्य और पीटी आईआरएनसी और इसके संबंधित निर्यातकों की प्रश्नावली प्रतिक्रिया में दी गई जानकारी को पूरी तरह से खारिज नहीं किए हैं।
195. प्राधिकारी ने कार्यक्रमों के लिए सब्सिडी मार्जिन निर्धारित किए हैं, जिसके लिए इंडोनेशिया में पीटी आईआरएनसी और इसके संबंधित कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं की प्रश्नावली उत्तर में जानकारी दी गई थी, जो पीओआई के दौरान प्राप्त या अर्जित लाभ के बराबर है। यह नोट किया जाता है कि पीटी आईआरएनसी और इसके संबंधित कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं को बॉन्डेड ज़ोन में आयात शुल्क से छूट के विषय में अन्य कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त हुआ है। प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि सब्सिडी कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप राजस्व में कमी के रूप में वित्तीय योगदान का प्रावधान था जो अन्यथा था। परिणामस्वरूप, इस लाभ के प्राप्तकर्ता के रूप में पीटी आईआरएनसी को लाभ प्रदान किया गया। सब्सिडी कार्यक्रम भी विशिष्ट था क्योंकि वे बॉन्डेड ज़ोन में स्थित पीटी आईआरएनसी सहित कुछ उद्यम तक सीमित थे।



196. प्राधिकारी ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचनाओं पर भरोसा करके, पर्याप्त पारिश्रमिक से कम के लिए कच्चे माल कोल और निकल अयस्क के प्रावधान के लिए सब्सिडी मार्जिन का निर्धारण करने के लिए उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा किए हैं। प्राधिकारी ने इंडोनेशिया एक्जिम बैंक द्वारा निर्यात वित्तपोषण से संबंधित कार्यक्रम के लिए सब्सिडी मार्जिन निर्धारित करने के लिए उपलब्ध तथ्यों पर भी भरोसा किए हैं।

197. नीचे दी गई तालिका में सब्सिडी कार्यक्रमों और संगत सब्सिडी मार्जिन का नाम प्रदान किया गया है।

कार्यक्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	संक्षिप्त विवरण	सब्सिडी मार्जिन%	सब्सिडी मार्जिन रेंज
अन्य कार्यक्रम	बंधुआ अंचल	पूँजीगत वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क और आयकर से छूट	***	0-5%
कार्यक्रम सं. 1, 2 और 4	निर्यात और घरेलू बाजार दायित्व की आवश्यकता के लिए न्यूनतम मूल्य संवर्धन	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर खनिजों का प्रावधान	***	15-25%
कार्यक्रम संख्या 9	इंडोनेशिया एक्जिम बैंक से निर्यात वित्तपोषण	राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों / सार्वजनिक निकायों से ऋण के रूप में निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण	***	5-10%
<b>कुल</b>			***	<b>20-30%</b>

### पीटी आईएमआर एआरसी स्टील, लंदन

198. पीटी आईएमआर एआरसी स्टील, इंडोनेशिया ने इंडोनेशिया में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक/ निर्यातक है। पीटी आईएमआर एआरसी ने प्रश्नावली उत्तर प्रस्तुत किया है और इसके द्वारा प्राप्त सब्सिडी के संबंध में जानकारी प्रदान की है। \*\*\* में पीटी आईएमआर एआरसी का संबंधित आयातक है। पीटी आईएमआर एआरसी ने भारत को सीधे संबंधित और असंबंधित आयातक को संबंधित निर्यातक \*\*\* के माध्यम से भारत में संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है।

199. प्राधिकारी ने कार्यक्रमों के लिए सब्सिडी मार्जिन निर्धारित किए हैं, जिसके लिए पीओआई आईएमआर एआरसी की प्रश्नावली उत्तर में जानकारी प्रदान की गई थी जो पीओआई के दौरान प्राप्त या अर्जित की गई थी। यह ध्यान दिया जाता है कि पीटी आईएमआर एआरसी और इसके संबंधित कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं को आयात शुल्क से छूट के विषय में अन्य कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त हुआ है। प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि सब्सिडी कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप राजस्व में कमी के रूप में वित्तीय योगदान का प्रावधान था जो अन्यथा था। परिणामस्वरूप, इस लाभ के प्राप्तकर्ता के रूप में पीटी आईएमआर एआरसी को लाभ प्रदान किया गया। सब्सिडी कार्यक्रम भी विशिष्ट था क्योंकि वे पीटी आईएमआर एआरसी सहित कुछ निश्चित उद्यम तक सीमित थे, जिन्होंने कार्यक्रम के तहत पात्रता मानदंड को पूरा किया था।

200. प्राधिकारी ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचनाओं पर भरोसा करके, पर्याप्त पारिश्रमिक से कम के लिए कच्चे माल कोल और निकल अयस्क के प्रावधान के लिए सब्सिडी मार्जिन का निर्धारण करने के लिए उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा किए हैं। प्राधिकारी ने इंडोनेशिया एक्जिम बैंक द्वारा निर्यात वित्तपोषण से संबंधित कार्यक्रम के लिए सब्सिडी मार्जिन निर्धारित करने के लिए उपलब्ध तथ्यों पर भी भरोसा किए हैं।

201. नीचे दी गई तालिका में सब्सिडी कार्यक्रमों और संगत सब्सिडी मार्जिन का नाम प्रदान किया गया है।

कार्यक्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	संक्षिप्त विवरण	सब्सिडी मार्जिन%	सब्सिडी मार्जिन रेंज
अन्य कार्यक्रम	सुविधा सेवा पूंजी निवेश (मास्टर सूची योजना)	मशीनों पर सीमा शुल्क से छूट	***	0-5%
अन्य कार्यक्रम		पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर आयकर से छूट	***	0-5%
अन्य कार्यक्रम	कच्चे माल पर आयकर से छूट	कच्चे माल के आयात पर आयकर से छूट	***	0-5%
कार्यक्रम सं. 1, 2 और 4	निर्यात और घरेलू बाजार दायित्व की आवश्यकता के लिए न्यूनतम मूल्य संवर्धन	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर खनिजों का प्रावधान	***	15-25%
कार्यक्रम संख्या 9	इंडोनेशिया एक्जिम बैंक से निर्यात वित्तपोषण	राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों / सार्वजनिक निकायों से ऋण के रूप में निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण	***	5-10%
कुल			***	20-30%

### पीटी बिनटैंग एशिया उसाहा (बीएयू), इंडोनेशिया

202. पीटी बिनटैंग एशिया उसाहा (बीएयू) इंडोनेशिया में विषय उत्पाद के निर्माता/निर्यातक हैं। पीटी बीएयू ने निर्यातक प्रश्नावली उत्तर प्रस्तुत किया है। पीटी बीएयू ने दावा किया है कि पीटी बीएयू द्वारा निर्यात किया गया उत्पाद पीयूसी के दायरे में नहीं आता है। प्राधिकारी ने पीटी बीएयू की प्रतिक्रिया की जांच किए हैं। प्राधिकारी ने नोट किए हैं कि भारत में पीटी बीएयू द्वारा निर्यात किया जाने वाला उत्पाद "स्टेनलेस स्टील सर्किल" है और यह विचाराधीन उत्पाद के दायरे में आता है। प्राधिकारी आगे कहते हैं कि पीटी बीएयू ने पीओआई के दौरान भारत को किए गए निर्यात के बारे में लेनदेन की जानकारी द्वारा पूर्ण लेनदेन प्रदान नहीं किए हैं। इस प्रकार, प्राधिकारी ने इस प्रारंभिक निर्धारण में पीटी बीएयू के निर्यात मूल्य को निर्धारित करने के लिए उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा किए हैं।

203. प्राधिकारी ने पीटी बीएयू द्वारा दायर प्रश्नावली प्रतिक्रिया की जांच किए हैं। पीटी बीएयू ने शुरूआती नोटिस में पहचाने गए कार्यक्रमों के बारे में और उन कार्यक्रमों के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी है जिनके तहत पीटी बीएयू को लाभ मिलता है। इस प्रकार, प्राधिकारी पीटी बीएयू द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली उत्तर को खारिज कर देते हैं और इस प्रारंभिक निर्धारण में इंडोनेशिया से पीटी बीएयू को गैर-सहयोगी उत्पादक/निर्यातक के रूप में निर्धारित करते हैं। तदनुसार, प्राधिकरण ने पीटी बीएयू के लिए सब्सिडी मार्जिन निर्धारित करने के लिए उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा किए हैं।

### इंडोनेशिया के लिए सब्सिडी कार्यक्रमों का सारांश

204. इंडोनेशिया से भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों के तीन समूह हैं। पहले समूह में इंडोनेशिया में तीन संबंधित निर्माता \*\*\*, \*\*\* और \*\*\* और उनके संबंधित कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता और संबंधित व्यापारी/निर्यातक शामिल हैं। दूसरे समूह में निर्माता \*\*\* में इसके संबंधित निर्यातक \*\*\* और \*\*\* में इसके संबंधित आयातक शामिल हैं। तीसरे समूह में निर्माता/निर्यातक पीटी बीएयू, इंडोनेशिया शामिल हैं। प्राधिकारी ने अपने प्रश्नावली उत्तरों में दी गई जानकारी के आधार पर पहले दो समूहों के लिए सब्सिडी मार्जिन निर्धारित किए हैं।

205. इंडोनेशिया से अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए काउंटरवेलिंग ड्यूटी सहयोगी दलों के लिए सब्सिडी मार्जिन के उच्चतम के आधार पर निर्धारित की गई है।

कार्यक्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	संक्षिप्त विवरण	सब्सिडी मार्जिन%	सब्सिडी मार्जिन रेंज
अन्य कार्यक्रम	बॉन्डेड ज़ोन	पूँजीगत वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क और आयकर से छूट	***	0-5
अन्य कार्यक्रम	कच्चे माल पर आयकर से छूट	कच्चे माल के आयात पर आयकर से छूट	***	0-5
कार्यक्रम सं. 1, 2 और 4	निर्यात और घरेलू बाजार दायित्व की आवश्यकता के लिए न्यूनतम मूल्य संवर्धन	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर खनिजों का प्रावधान	***	15-25%
कार्यक्रम सं. 9	इंडोनेशिया एक्जिम बैंक से निर्यात वित्तपोषण	राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों/सार्वजनिक निकायों से ऋण के रूप में निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण	***	5-10%
कुल			***	20-30%

#### क. क्षति मूल्यांकन और करणीय लिंक

##### छ.1. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतियाँ

206. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति के मुद्दों के संबंध निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ में की गई हैं:

- क. भारत में संबंधित उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और अन्य सभी देशों से आयात के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। उन उत्पादकों का उत्पादन/बिक्री जिनके इनपुट और आउटपुट दोनों वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद के दायरे में हैं, को नजरअंदाज करने की आवश्यकता है। क्षति की अवधि के दौरान मांग में वृद्धि हुई है।
- ख. क्षति की अवधि में संबद्ध देश से आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आधार वर्ष में आयात केवल 93 मीट्रिक टन था और पीओआई में 76,102 मीट्रिक टन तक बढ़ गया है। इस प्रकार, क्षति की अवधि में आयात में 700 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है।
- ग. आधार वर्ष में संबद्ध देश से आयात में बाजार की हिस्सेदारी लगभग शून्य थी और पीओआई में कुल आयात का 17% तक बढ़ गया। आयात न केवल निरपेक्ष रूप से बढ़ा है, बल्कि उसी अनुपात में उत्पादन, खपत, बिक्री और कुल आयात के संबंध में भी बढ़ा है।
- घ. आधार वर्ष में उत्पादन का केवल \*\*\*% उत्पादन का संबद्ध आयात हुआ है जो पीओआई में \*\*\*% हो गया है।
- ड. इसी प्रकार, संबद्ध आयात से घरेलू उद्योग की खपत का कोई प्रतिशत नहीं बनता है और यह 2016-17 में केवल \*\*\*% था जो पीओआई में बढ़कर \*\*\*% हो गया। आधार वर्ष में घरेलू उद्योग की बिक्री में संबद्ध आयात केवल \*\*\*% था, जो अब बढ़कर \*\*\*% हो गया है।
- च. मूल्य कम करने का निर्धारण केवल उन आयात लेन-देन पर विचार किया जाना चाहिए, जिनके आयात की भूमि की कीमत घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य से कम है। याचिकाकर्ता का संबंध हानिकारक आयातों से है।
- छ. प्राधिकारी को केवल उन लेनदेन पर विचार करना चाहिए जो क्षति के मार्जिन की गणना के लिए गैर-हानिकारक कीमत से नीचे हैं।

- ज. इनपुट की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि के मद्देनजर मौजूदा क्षति की अवधि में उत्पादन की लागत बढ़ गई है। स्क्रेप, निकल, फेरो मिश्र जैसे प्रमुख इनपुट की कीमतें क्षति की अवधि में बढ़ गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप क्षति की अवधि में प्रत्यक्ष लागत में वृद्धि हुई है। विशेष रूप से, पीओआई और पूर्ववर्ती वर्ष के बीच, इनपुट की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और इसके परिणामस्वरूप सामग्री की लागत में वृद्धि हुई है। हालांकि, कच्चे माल की लागत में वृद्धि के अनुपात में विक्रय मूल्य में वृद्धि नहीं हुई है।
- झ. घरेलू उद्योग के साथ क्षति की अवधि में क्षमता समान रही है। भारत में अन्य उत्पादकों के साथ घरेलू उद्योग में घरेलू मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है। इस प्रकार, इस सीमा तक आयात आवश्यक नहीं है।
- ञ. घरेलू उद्योग का उत्पादन और बिक्री क्षति की अवधि के दौरान बढ़ी है। इंडोनेशिया से सब्सिडी आयात ने घरेलू उद्योग को अपनी घरेलू बिक्री को उत्पादन की सीमा तक बढ़ाने से रोक दिया है, जिससे घरेलू उद्योग को निर्यात का सहारा लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- ट. घरेलू उद्योग अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहा है। घरेलू उद्योग, घरेलू बाजार में पर्याप्त मांग के बावजूद महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान पर उत्पाद निर्यात कर रहा है। घरेलू उद्योग के लिए उत्पाद का निर्यात करने का एकमात्र कारण बाजार में मांग के महत्वपूर्ण हिस्से के लिए सब्सिडी वाला आयात और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग से बाजार में हिस्सेदारी लेना है।
- ठ. घरेलू उद्योग को कीमतों में कमी का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- ड. 2017-18 में घरेलू उद्योग के लाभ में वृद्धि हुई। तथापि, इससे पीओआई में काफी गिरावट आई। नकद लाभ और निवेश पर वापसी ने मुनाफे के रूप में एक ही प्रवृत्ति का पालन किया है। पीओआई में नकद लाभ और निवेश पर रिटर्न में काफी गिरावट आई है।
- ढ. उत्पाद के लिए मार्केट को मुख्य रूप से चीनी कीमतों द्वारा सीवीडी लगाने पर तय किया गया था। सब्सिडी वाले चीनी आयात के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण मूल्य की क्षति का सामना करना पड़ा। सीवीडी लगाने से उद्योग को अपनी कीमतों और लाभ में सुधार की उम्मीद थी। यह 2017-18 में कुछ हद तक हुआ। हालांकि, यह इंडोनेशिया से रियायती वस्तुओं के आयात के मद्देनजर अल्पकालिक रहा।
- ण. याचिकाकर्ताओं ने घरेलू बाजार में बिक्री के बजाय निर्यात करने के परिणामस्वरूप राजस्व और लाभ खो दिया है।
- त. रोजगार का स्तर समान क्षेत्र में बना हुआ है, जबकि मजदूरी का भुगतान बढ़ा है। याचिकाकर्ताओं ने इस संबंध में किसी भी क्षति का दावा नहीं किया है।
- थ. वॉल्यूम मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि प्रतिकूल बनी हुई है। सीवीडी कर्तव्यों को लागू करने के लिए चीन द्वारा खाली किए गए बाजार हिस्सेदारी को हासिल करने के लिए घरेलू उद्योग की उम्मीद है। हालांकि, संबद्ध देश से रियायती आयात से घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा, पीओआई में मूल्य मापदंडों के संदर्भ में वृद्धि नकारात्मक रही है।
- द. संबद्ध देश के अलावा अन्य देशों से आयात या तो नगण्य हैं या पहले से ही एंटी-डंपिंग ड्यूटी/काउंटरवेलिंग ड्यूटी को आकर्षित कर रहे हैं या एंटीडंपिंग जांच के तहत जांच की जा रही है।
- ध. क्षति की अवधि में उत्पाद की मांग में कोई गिरावट नहीं है। मांग में गिरावट घरेलू उद्योग के लिए क्षति का एक संभावित कारण नहीं है।
- न. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे जाने वाले अन्य उत्पादों के प्रदर्शन का उत्पाद के प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बाजार में रियायती आयातों की उपलब्धता घरेलू उद्योग द्वारा मौजूदा क्षति का एकमात्र कारण है।
- प. घरेलू उद्योग और विदेशी उत्पादकों द्वारा प्रदान की गई कीमतों में महत्वपूर्ण अंतर है। इसके परिणामस्वरूप, क्षति की अवधि में आयात में काफी वृद्धि हुई है।

- फ. मूल्य कम करने की प्रक्रिया ने घरेलू उद्योग को कीमतें बढ़ाने से लेकर लागत बढ़ने तक रोक दिया है। मूल्य दमन के कारण घरेलू उद्योग के मुनाफे में गिरावट आई है।
- ब. प्रस्तावित पीओआई में कई मूल्य मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग का विकास नकारात्मक हो गया है, जो देश में सब्सिडी वाले आयात के कारण है।
- भ. चीनी कंपनी सिंगशान ने विशाल क्षमता (इंडोनेशिया में मांग से अधिक) के साथ एक संयंत्र में भारी निवेश किया है।
- म. संबद्ध देश से आयात की बाजार हिस्सेदारी बढ़ी है
- कक) आयात में वृद्धि की दर भी अधिक है। आधार वर्ष के बाद से संबद्ध देश से आयात में लगभग 700 गुना की वृद्धि हुई है। संभावना है कि भविष्य में आयात और बढ़ेगा।
- खख) सिंगशान समूह ने अकेले 3 लाख टन क्षमता के साथ एक संयंत्र की स्थापना की है। सिंगशान समूह ने वैश्विक बाजार के संबंध में यह भारी निवेश किया है। इंडोनेशिया में आने वाली विशाल क्षमताओं को मुख्य रूप से अन्य बाजारों में लक्षित किया जाता है क्योंकि इंडोनेशिया में स्टेनलेस स्टील की खपत बहुत कम है और वैश्विक व्यापार संतुलन को और परेशान करने की संभावना है।
- गग) स्टेनलेस-स्टील की खपत के प्रमुख केंद्र हैं चीन, यूरोपीय संघ, जापान, कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका और ये देश पहले से ही स्थिर मांग और अतिरिक्त उत्पादन और अधिशेष क्षमता से युक्त हैं, जो अतिरिक्त मात्रा को ग्रहण करने के लिए बहुत कम जगह छोड़ते हैं।
- घघ) आयात कीमत की कीमत के साथ बिक्री मूल्य की तुलना से पता चलता है कि आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे हैं। ये कम कीमत के आयात बाजार में मूल्य दमन का नेतृत्व कर रहे हैं। इस प्रकार, यदि एंटी सब्सिडी उपायों को लागू नहीं किया जाता है तो आयात में और वृद्धि होने की संभावना है।
- ड.ड.) घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और लागत की तुलना में आयात का उतरा हुआ मूल्य बहुत कम कीमत पर है। संबद्ध देश के उत्पादकों को कीमतों के मामले में भारतीय बाजार काफी आकर्षक लग रहा है। आयात उन कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं जो घरेलू कीमतों पर एक महत्वपूर्ण दमनकारी प्रभाव डाल रहे हैं और संभवतः आगे आयात की मांग में वृद्धि होगी।

भारत न केवल स्टेनलेस स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, बल्कि एकमात्र बाजार भी है जहां प्रति वर्ष 9-10% की सीएजीआर पर स्टेनलेस स्टील की खपत बढ़ रही है। जैसा कि वैश्विक प्रति व्यक्ति 6 किलोग्राम की स्टेनलेस स्टील की खपत के लिए है, भारत में प्रति व्यक्ति खपत का आंकड़ा केवल 2 किलोग्राम है, जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि विकास एक ही प्रक्षेपवक्र में जारी रहने की उम्मीद है। यह इंडोनेशिया में स्थापित स्टेनलेस स्टील क्षमताओं के लिए भारत को एक बहुत स्पष्ट लक्ष्य बनाता है

## छ.2. प्राधिकारी द्वारा जांच

207. संबद्ध देश से रियायती आयात के कारण घरेलू उद्योग को क्षति की जांच करने के लिए प्राधिकारी द्वारा इच्छुक दलों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण का विश्लेषण किया गया है।
208. नियमों में से नियम 13 क्षति के निर्धारण को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों से संबंधित है जो इस प्रकार है:

### "13. क्षति का निर्धारण

- (1) निर्दिष्ट देशों से आयात के मामले में, नामित प्राधिकारी आगे यह पता लगाएगा कि भारत में इस प्रकार की सामग्री के आयात से भारत में स्थापित किसी भी उद्योग को सामग्री की क्षति होती है या खतरा होता है, या भारत में एक उद्योग की स्थापना को रोकता है।
- (2) उप-नियम (3) के तहत क्षति का पता लगाया जाता है, तब अन्य बातों के साथ-साथ, नियम के अनुबंध। में निर्धारित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, नामित प्राधिकारी क्षति, क्षति का खतरा, किसी उद्योग की स्थापना के लिए सामग्री की कमी और सब्सिडी के आयात और क्षति के बीच करणीय लिंक का निर्धारण करेगा।

(3) नामित प्राधिकारी, असाधारण मामलों में, उन स्थानों पर क्षति होने का परिणाम दे सकता है जहां घरेलू उद्योग का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है -

(i) वहाँ एक पृथक बाजार में सब्सिडी वाले आयात पर ध्यान केंद्रित है, और

(ii) रियायती आयात इस तरह के बाजार के भीतर लगभग सभी उत्पादन के उत्पादकों को क्षति पहुंचा रहे हैं। "

#### ख. रियायती आयातों का वॉल्यूम प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

##### (i) मांग का आकलन

209. भारत में संबंधित उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और अन्य सभी देशों से आयात के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। यह ध्यान दिया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद को कोल्ड और हॉट रोल्ड परिस्थितियों में भारत में आयात किया जा रहा है। कोल्ड रोल्ड उत्पादों के कुछ उत्पादक घरेलू बाजार से या आयात से हॉट रोल्ड की खरीद करते हैं। इसलिए, उत्पादन के दोहरे लेखांकन से बचने के लिए भारत में विचाराधीन उत्पाद की खपत का निर्धारण करने के लिए इन उत्पादकों की बिक्री की गणना नहीं की गई है। यह देखा गया है कि क्षति की अवधि और पीओआई में मांग बढ़ी है। इस प्रकार मूल्यांकन की गई मांग इस प्रकार है:

विवरण	यूओएम	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई
संबद्ध देश के आयात	मीट्रिक टन	93	4,024	8601	76,102
ट्रेंड	सूची	100	4327	9248	81,830
सीवीडी आकर्षित करने वाला देश (चीन)	मीट्रिक टन	235,949	241,703	152,821	62,705
ट्रेंड	सूची	100	100	102	65
एडीडी को आकर्षित करने वाले देश	मीट्रिक टन	39,435	30,839	34,829	59,232
ट्रेंड	सूची	100	78	88	150
चल रही एडीडी जांच के तहत देश (इंडोनेशिया और चीन को छोड़कर)	मीट्रिक टन	209,705	185,680	243,335	243,216
ट्रेंड	सूची	100	89	116	116
दूसरे देश	मीट्रिक टन	9637	6184	9651	158
ट्रेंड	सूची	100	64	100	2
डीआई द्वारा घरेलू बिक्री	मीट्रिक टन	***	***	***	***
ट्रेंड	सूची	100	107	131	133
अन्य भारतीय उत्पादकों द्वारा घरेलू बिक्री	मीट्रिक टन	***	***	***	***
ट्रेंड	सूची	100	101	110	110
कुल मांग	मीट्रिक टन	***	***	***	***
ट्रेंड	सूची	100	102	114	115

यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं की मांग पूरे क्षति की अवधि के दौरान बढ़ते ट्रेंड का अनुसरण करती है।

##### (ii) आयात

210. संबद्ध आयात की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि भारत में उत्पादन या उपभोग के सापेक्ष सब्सिडी में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है या नहीं।

211. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में पीओआई में संबद्ध देश से संबद्ध आयात की मात्रा बहुत बढ़ गई है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट है:

विवरण	यूओएम	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई
<b>आयात मात्रा</b>					
संबद्ध देश-इंडोनेशिया	मीट्रिक टन	93	4,024	8601	76,102
सीवीडी आकर्षित करने वाला देश (चीन)	मीट्रिक टन	235,949	241,703	152,821	62,705
एडीडी को आकर्षित करने वाले देश	मीट्रिक टन	39,435	30,839	34,829	59,232
चल रही एडीडी जांच के तहत देश (इंडोनेशिया और चीन को छोड़कर)	मीट्रिक टन	209,705	185,680	243,335	243,216
दूसरे देश	मीट्रिक टन	9637	6184	9651	158
कुल	मीट्रिक टन	494,819	468,429	449,237	441,412
<b>आयात में साझेदारी</b>					
संबद्ध देश-इंडोनेशिया	%	0%	1%	2%	17%
	रेंज	0%	0-10%	0-10%	15-25%
सीवीडी आकर्षित करने वाला देश (चीन)	%	48%	52%	34%	14%
	रेंज	45-55%	50-60%	30-40%	10-20%
एडीडी को आकर्षित करने वाले देश	%	8%	7%	8%	13%
	रेंज	5-15%	5-15%	5-15%	10-20%
चल रही एडीडी जांच के तहत देश (इंडोनेशिया और चीन को छोड़कर)	%	42%	40%	54%	55%
	रेंज	40-50%	35-45%	50-60%	50-60%
दूसरे देश	%	2%	1%	2%	0%
	रेंज	0-10%	0-10%	0-10%	0-10%
कुल	%	100%	100%	100%	100%

212. इंडोनेशिया से आयातों में वृद्धि वर्ष 2015-16 में 93 मीट्रिक टन से जांच की अवधि में 76,102 मीट्रिक टन हो गई है। प्राधिकारी ने यह पाया है कि भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में आयात की प्रवृत्ति में भी वही प्रवृत्ति रही जो आयातों के निरपेक्ष संदर्भ में थी। विगत वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में आयातों में काफी वृद्धि हुई है।

विवरण	यूओएम	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
<b>निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध देश के आयात</b>					
भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
	रेंज	0 %	0-10 %	0-10 %	0-10 %
खपत	%	***	***	***	***
	रेंज	0 %	0-10 %	0-10 %	0-10 %
कुल आयात	%	***	***	***	***
	रेंज	0 %	0-10 %	0-10 %	15-20 %

213. कुल घरेलू उत्पादन में संबद्ध आयातों का हिस्सा 0 % से बढ़कर 0-10 % और कुल खपत में आयातों का हिस्सा 0 % से बढ़कर 0-10 % हो गया।

(iii) बाजार अंश -

विवरण	यूओएम	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
<b>मांग में हिस्सा</b>					
संबद्ध देश - इंडोनेशिया	%	0 %	0 %	0 %	3 %
सीवीडी वाले देश (चीन)	%	10 %	10 %	6%	2 %
पाटन रोधी शुल्क वाले देश	%	2 %	1 %	1%	2 %
पाटन रोधी शुल्क जांच वाले देश (इंडोनेशिया और चीन को छोड़कर)	%	9 %	8 %	9 %	9 %
अन्य देश	%	0 %	0 %	0 %	0 %
	%	***	***	***	***
घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियां	सूचीबद्ध	35-45 %	40-50 %	45-55 %	45-55 %
	%	***	***	***	***
अन्य भारतीय उत्पादक	सूचीबद्ध	35-45 %	35-45 %	35-45 %	35-45 %
कुल मांग	%	100 %	100 %	100 %	100 %

214. यह देखा गया है कि संबद्ध देश से आयातों का बाजार अंश आधार वर्ष में लगभग शून्य था और जांच की अवधि में यह बढ़कर 0-10 % हो गया। घरेलू उद्योग के बाजार अंश में जांच की अवधि के दौरान भी वृद्धि हुई है।

I. संबद्ध आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

215. कीमतों पर रियायती आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह जांच की जानी अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में रियायती आयातों से महत्वपूर्ण कीमत कटौती हो रही है अथवा क्या ऐसे रियायती आयातों का प्रभाव कीमतों को पर्याप्त मात्रा में अन्यथा मंद करने के लिए है अथवा कीमत में वृद्धि को रोकने के लिए है जो अन्यथा पर्याप्त मात्रा में होती। इस विश्लेषण के लिए घरेलू उद्योग की भारित औसत उत्पादन लागत (सी ओ पी), भारित औसत निवल बिक्री वसूली (एन एस आर) की तुलना संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत से की गई है।

(i) कीमत कटौती

216. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयातों से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है, क्षति अवधि के दौरान आयातों की पहुंच कीमत की घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के साथ तुलना करके कीमत कटौती का आकलन किया गया है। जांच की अवधि के लिए घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित प्रत्येक पी सी एन के लिए अलग से कीमत कटौती निर्धारित की गई है और उसके बाद पूरे विचाराधीन उत्पाद के लिए निर्धारित की गई है।

विवरण	यूओएम	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
संबद्ध देश से आयात की मात्रा	मी. टन	93	4,024	8,601	76,102
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	4326	9254	81,830
आयातों की पहुंच कीमत	रु./ मी. टन	20,635	100,572	103,938	137,996
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	487	503	668
निवल बिक्री वसूली	रु./ मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	118	149
कीमत कटौती	रु./ मी. टन	***	***	***	***



प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	10	16	12
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती रेंज	%	380-390 %	5-15 %	10-20 %	5 -15 %

217. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम थीं जो जांच की अवधि सहित क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से रियायती उत्पादों के कारण हो रही कीमत कटौती को दर्शाता है।

### (ii) कम कीमत पर बिक्री/ क्षति मार्जिन

218. प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं की गैर क्षतिकारी कीमतों की गणना की है और आयातित वस्तुओं के पहुंच मूल्य के साथ उसकी तुलना की गई है ताकि कम कीमत पर बिक्री निकाली जा सके। प्रत्येक पी सी एन के लिए अलग अलग कम कीमत की बिक्री/ क्षति मार्जिन का निर्धारण किया गया है और उसके बाद पूरे विचाराधीन उपाद के लिए निर्धारण किया गया है।

219. नीचे दी गई तालिका से यह नोट किया जाता है कि कम कीमत पर बिक्री/ क्षति मार्जिन सकारात्मक है, जो यह दर्शाता है कि बाजार में आयात क्षतिकारी कीमतों पर हुए हैं।

220. सहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों और अन्यो के लिए क्षति मार्जिन का मूल्यांकन इस प्रकार किया गया है :

उत्पादक	गैर क्षतिकारी कीमत (यूएस डॉलर/ मी. टन)	पहुंच कीमत (यूएस डॉलर/ मी. टन)	क्षति मार्जिन (यूएस डॉलर/ मी. टन)	क्षति मार्जिन %	क्षति मार्जिन रेंज
पीटी इंडोनेशिया गुआंग चिंग निकेल एंड स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री	***	***	***	***	10-30 %
पीटी इंडोनेशिया त्सिंगशान स्टेनलेस स्टील	***	***	***	***	10-30 %
पीटी इंडोनेशिया रुइपु निकेल एंड क्रोम अलॉय	***	***	***	***	10-30 %
पीटी आईएमआर एआरसी स्टील	***	***	***	***	10-30 %
अन्य	***	***	***	***	10-30 %

### (iii) कीमतों का दमन और मंदी

221. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या रियायती आयातों के कारण घरेलू कीमतों में मंदी आ रही है और क्या ऐसे आयातों के प्रभाव का कारण महत्वपूर्ण मात्रा में कीमतों का दमन करना अथवा कीमत में वृद्धि को रोकना, जो सामान्य स्थिति में अन्यथा नहीं होती, प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में परिवर्तन पर विचार किया है। नीचे दी गई तालिका में स्थिति दर्शाई गई है :-

विवरण	यूओएम	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
विक्रियों की लागत	₹./ मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	104	116

विवरण	यूओएम	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
बिक्री कीमत	रु./ मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	118	149
पहुंच कीमत	रु./ मी. टन	20,635	100,572	103,938	137,996
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	487	504	669

222. उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि संबद्ध देशों से आयातों का पहुंच मूल्य विगत वर्षों की तुलना में क्षति अवधि में ऊपर की प्रवृत्ति की ओर दर्शाया गया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और बिक्री की कीमत में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

## II. घरेलू उद्योग के संबंध में आर्थिक मापदंड

223. नियमावली में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों इन आयातों के परिणामी प्रभाव की एक उद्देश्यपरक जांच शामिल होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में नियमावली में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर रियायती आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों एवं सूचकांकों का एक उद्देश्यपरक और भेदभाव रहित मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, जिनका उद्योग की स्थिति से कोई संबंध हो, जिसमें बिक्रियों, लाभों, आउटपुट, बाजार अंश, उत्पादकता, निवेशों पर प्रतिफल, व्यय क्षमता, क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट, घरेलू कीमतों पर प्रभाव डालने वाले कारक, नकदी प्रवाह, इन्वेंट्रियों, रोजगार मजदूरी, विकास, पूंजीगत निवेश जुटाने की योग्यता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। तदनुसार क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच की गई है।

(i) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्रियां

224. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्रियों के संबंध में क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की स्थिति इस प्रकार थी :

विवरण	यूओएम	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
क्षमता	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
उत्पादन	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	127	125
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	126	125
बिक्री मात्रा कुल	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	130	126

225. प्राधिकारी यह नोट करते हैं -

- क) घरेलू उद्योग के पास क्षति अवधि के दौरान क्षमता वही रही।
- ख) घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्रियों तथा क्षमता उपयोग में जांच की अवधि में मामूली गिरावट के साथ पूरी क्षति अवधि के दौरान वृद्धि रही।
- (ii) लाभप्रदता, निवेश पर प्रतिफल और नकदी लाभ

226. लाभप्रदता, निवेश पर प्रतिफल और नकदी लाभ के संबंध में क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की स्थिति इस प्रकार है :

विवरण	यूओएम	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
बिक्रियों की लागत	रु. / मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	104	116
विक्री कीमत	रु. / मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	118	129
लाभ	रु. / मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-19	9	-4
नकदी लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	19	73	47
पी वी आई टी	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	76	133	107
निवेश पर प्रतिफल	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	82	138	120

227. उपरोक्त सूचना से प्राधिकारी यह नोट करते हैं :

- क) घरेलू उद्योग के लाभ में वर्ष 2017-18 में वृद्धि हुई लेकिन जांच की अवधि में यह हानि में परिवर्तित हो गया।  
 ख) नकदी लाभ, ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ तथा निवेशों पर प्रतिफल में लाभ की तरह की ही प्रवृत्ति रही। वर्ष 2017-18 में नकदी लाभ, ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ तथा निवेशों पर प्रतिफल में वृद्धि हुई लेकिन इसके बाद जांच की अवधि में गिरावट आई।

(iii) बाजार अंश

228. मांग में बाजार अंश के संबंध में क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की स्थिति इस प्रकार है :

विवरण	यूओएम	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
<b>मांग में बाजार अंश</b>					
संबद्ध देश – इंडोनेशिया	%	0 %	0 %	0 %	3 %
सीवीडी वाले देश (चीन)	%	10 %	10 %	6 %	2 %
पाटन रोधी शुल्क वाले देश	%	2 %	1 %	1 %	2 %
पाटन रोधी शुल्क जांच वाले देश (इंडोनेशिया और चीन को छोड़कर)	%	9 %	8 %	9 %	9 %
अन्य देश	%	0 %	0 %	0 %	0 %
घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियां	%	35-45 %	40-50 %	45-55 %	45-55 %
अन्य भारतीय उत्पादक	%	35-45 %	35-45 %	35-45 %	35-45 %
कुल मांग	%	100 %	100 %	100 %	100 %

229. विगत वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान संबद्ध आयातों के बाजार अंश में वृद्धि हुई है।

(iv) रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

विवरण	यूओएम	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	107	107
वेतन एवं मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	162	157
वेतन एवं मजदूरी प्रति यूनिट	रु./ मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	128	125
उत्पादकता प्रति कर्मचारी	मी. टन /सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	119	117
उत्पादकता प्रति दिन	मी. टन / दिन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	127	125

230. विगत वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान वेतन एवं मजदूरी प्रति यूनिट और उत्पादकता प्रति दिन में मामूली गिरावट आई है।

(v) मालसूचियां

231. जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की माल सूचियों में गिरावट आई है।

विवरण	यूओएम	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
माल सूची	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	97	83

(vi) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

232. याचिकाकर्ता ने यह प्रस्तुत किया है कि विचाराधीन उत्पाद के लिए वर्तमान और भावी मांग को देखते हुए नए निवेश जुटाने की क्षमता को ध्यान में रखा गया है। विचाराधीन उत्पाद की दीर्घावधिक व्यवहार्यता सशक्त लाभयोग्य कारोबार पर निर्भर करती है जिस पर संबद्ध आयातों के कारण प्रभाव पड़ा है।

III. कारणात्मक संबंध

233. प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या नीचे दिए गए अन्य ज्ञात कारकों की वजह से घरेलू उद्योग को कारणात्मक क्षति हुई है।

क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमतें

234. अन्य देशों से आयातों से या तो पाटन रोधी शुल्क अपेक्षित है या पाटनरोधी जांच अपेक्षित है या ये उच्च कीमतों पर हो रहे हैं।

ख. मांग में कमी और खपत के पैटर्न में परिवर्तन

235. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मांग में कोई कमी नहीं है। इसके प्रतिकूल संबद्ध वस्तुओं के लिए समग्र मांग में क्षति अवधि के दौरान सुधार दर्शाया है। विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। खपत के पैटर्न में परिवर्तन घरेलू उद्योग की क्षति के कारण हो सकता है।

ग. विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएं और प्रतिस्पर्धा

236. ऐसी कोई ज्ञात व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया नहीं है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

घ. प्रौद्योगिकी में परिवर्तन

237. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्रौद्योगिकी में किसी परिवर्तन को दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया है जिससे कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति हुई हो।

ड. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

238. घरेलू उपयोग और निर्यात के लिए क्षति की सूचना पर अलग अलग इस तरह से विचार किया गया है कि उन्हें अलग किया जा सके।

**च. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित किए जा रहे और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों का निष्पादन**

239. प्राधिकारी ने केवल विचाराधीन उत्पाद के संबंध में डाटा पर विचार किया है।

**IV. कारणात्मक संबंध पर निष्कर्ष**

240. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि :

- क) जांच की अवधि के दौरान भारत में संबद्ध देश से भारी मात्रा में रियायती आयात आ रहे हैं।
- ख) जांच की अवधि के दौरान आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है।
- ग) जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन में लाभों और निवेशों पर प्रतिफल के संदर्भ में गिरावट आई है। वर्ष 2017-18 में नकदी लाभों, ब्याज व कर पूर्व लाभ और निवेशों पर प्रतिफल में वृद्धि हुई है जबकि जांच की अवधि में गिरावट आई है।

241. अतः प्राधिकारी ने अनंतिम रूप से यह पाया है कि संबद्ध वस्तुओं की रियायत और घरेलू उद्योग के समक्ष क्षति के बीच कारणात्मक संबंध है।

**V. वास्तविक क्षति की आशंका**

242. वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित प्रावधान सब्सिडी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 3 में दिए गए हैं जिनमें निम्नलिखित प्रावधान है।

3. वास्तविक क्षति के खतरे का निर्धारण तथ्यों के आधार पर होगा और न कि मात्र आरोप, अनुमानों अथवा सुदूर संभावना पर। परिस्थितियों में ऐसे परिवर्तन को, जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, जिसमें सब्सिडी के कारण क्षति होती है, स्पष्टतया प्रत्याशित और आसन्न माना जाना चाहिए। वास्तविक क्षति के खतरे के विद्यमान होने का निर्धारण करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारकों पर विचार करेंगे :
  - i. प्रश्नगत सब्सिडी अथवा सब्सिडियों की प्रकृति तथा उनसे उत्पन्न होने वाले संभावित व्यापार प्रभाव;
  - ii. पर्याप्त रूप से बढ़े हुए आयात की संभावना दर्शाते हुए घरेलू बाजार में सब्सिडीयुक्त आयातों की काफी वृद्धि दर।
  - iii. किसी अतिरिक्त निर्यात को लेने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार में पर्याप्त रूप से बढ़े हुए सब्सिडीयुक्त निर्यातों की संभावना दर्शाने वाले निर्यातक की, क्षमता में पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान योग्य अथवा आसन्न और वृद्धि,
  - iv. क्या आयात इन कीमतों पर आ रहे हैं जिनका घरेलू कीमतों पर महत्वपूर्ण मंदी अथवा दमनकारी प्रभाव होगा और आगे आयातों के लिए मांग में वृद्धि होने की संभावना होगी; और
  - v. जांच किए जा रहे उत्पाद की मालसूची।

243. वास्तविक क्षति की आशंका के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं :

- क) घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित की गई कीमतों और विदेशी उत्पादकों की कीमतों के बीच महत्वपूर्ण अन्तर है। इंडोनेशिया में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों को प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इंडोनेशिया से सभी सहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए सब्सिडी मार्जिन न्यून से अधिक है।
- ख) प्राधिकारी ने संबद्ध देश से सहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों की क्षमता के व्यौरों की जांच की है और यह नो किया जाता है कि किसी भी सहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों द्वारा कोई महत्वपूर्ण क्षमता नहीं जोड़ी गई है।
- ग) आयातित उत्पाद से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है। इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग उचित कीमतें लेने से रोक रहा है।
- घ) प्राधिकारी ने संबद्ध देश से सहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों की मालसूची की जांच की है और यह नोट किया जाता है कि उनमें से किसी के पास भी संबद्ध वस्तुओं की कोई महत्वपूर्ण मालसूची नहीं है।

**ज. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मामले**

244. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सामान्य तौर पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने का प्रयोजन रियायत की अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करना है ताकि भारतीय बाजार में मुक्त और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति की पुनर्स्थापना हो सके, जो कि देश के सामान्य हित में है। प्रतिसंतुलनकारी

शुल्क लगाने से संबद्ध देश से आयातों को किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा और इसीलिए इससे उपभोक्ताओं के उत्पादों की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

245. यह स्वीकार किया जाता है कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने से संबद्ध वस्तुओं की लागत पर प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा में प्रतिसंतुलनकारी उपायों के कारण कमी नहीं आएगी, विशेषकर यदि अनंतिम प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने को उस मात्रा तक सीमित किया जाए जो कि रियायती संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त हो। इसके प्रतिकूल प्रतिसंतुलनकारी उपायों के कारण रियायत के चलते प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होगा और एक समान अवसर प्राप्त होंगे।

#### झ. निष्कर्ष और सिफारिशें

246. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनमें उठाए गए मामलों की जांच करने के बाद और रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि :
- क. संबद्ध देशों से भारत को विचाराधीन उत्पाद रियायती कीमतों पर निर्यात किए गए हैं।
- ख. घरेलू उद्योग को विचाराधीन उत्पाद की रियायत के कारण वास्तविक क्षति हुई है।
- ग. संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के रियायती आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है।
247. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और इंडोनेशिया सरकार सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया गया था तथा निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सब्सिडी, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलू पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। नियमावली के तहत विनिर्दिष्ट प्रावधानों के तहत सब्सिडी, क्षति और कारणात्मक संबंध के लिए जांच शुरू किए जाने और ऐसे सब्सिडी आयातों के कारण सकारात्मक सब्सिडी मार्जिन और घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति साबित होने पर प्राधिकारी का यह विचार है कि सब्सिडी और क्षति को दूर करने, जांच पूरी होने में विलंब को देखते हुए अनंतिम प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाना आवश्यक है। अतः प्राधिकारी इसे आवश्यक मानते हैं और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं। तथापि, प्राधिकारी इंडोनेशिया से संबद्ध वस्तु के आयातों पर नीचे दिए गए रूप में और तरीके से अनंतिम प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं।
248. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी सब्सिडी के मार्जिन और क्षति के मार्जिन में कमतर के समान अनंतिम प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से अनंतिम प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं जो नीचे दी गई शुल्क तालिका के कालम 7 में उल्लिखित राशि के समान होगा। इस प्रयोजन के लिए आयातों का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सीमा शुल्क द्वारा यथा निर्धारित आकलनयोग्य मूल्य होगा और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9क के तहत लगाए गए शुल्क को छोड़कर सीमा शुल्क का लागू स्तर होगा।

#### जूटी टेबल

क्र. सं.	शीर्ष/ उप शीर्ष	वस्तुओं का विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	सीआईएफ मूल्य प्रतिशत के रूप में शुल्क राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	स्टेनलेस स्टील के फ्लैट उत्पाद	7219 और 7220	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया सहित कोई देश	पीटी इंडोनेशिया गुआंगचिन निकल एंड स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री	22.31 %

2.	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया सहित कोई देश	पीटी इंडोनेशिया स्मिंशगन स्टेनलेस स्टील	22.31 %
3.	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया सहित कोई देश	पीटी इंडोनेशिया रुइपु निकल एंड क्रोम अलॉय	22.31 %
4.	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया सहित कोई देश	पीटी आईएमआर एआरसी स्टील	22.65 %
5.	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया सहित कोई देश	उपरोक्त क्रम सं. 1 से 4 में उल्लिखित उत्पादकों के अलावा कोई अन्य उत्पादक	24.83%
6.	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया के अलावा कोई अन्य देश	इंडोनेशिया	कोई भी	24.83 %

### ख. आगे की प्रक्रिया

249. प्रारंभिक जांच परिणाम अधिसूचित करने से पूर्व निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा:-

- प्राधिकारी सभी हितबद्ध पक्षकारों से इन अनंतिम जांच परिणामों पर टिप्पणियां आमंत्रित करते हैं और प्राधिकारी द्वारा उन्हें संगत पाए जाने पर अंतिम जांच परिणामों में विचार किया जाएगा।
- घरेलू उद्योग, निर्यातक, आयातक और ऐसे अन्य हितबद्ध पक्षकार, जो इससे संबंधित हैं, उन्हें प्राधिकारी द्वारा अलग से भेजा जा रहा है, जो इन प्रारंभिक जांच परिणामों को प्रकाशित करने की तारीख से चालीस दिनों के भीतर अपने विचारों से अवगत कराएंगे।
- अन्य कोई हितबद्ध पक्षकार भी इन जांच परिणामों के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों के भीतर अपने विचारों से अवगत करा सकते हैं।
- प्राधिकारी नियम 7 (6) के प्रावधानों के अनुसार सभी हितबद्ध पक्षकारों को जांच के लिए संगत अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए एक अवसर प्रदान करने के लिए मौखिक सुनवाई का आयोजन करेंगे। मौखिक सुनवाई के दौरान उठाए गए मुद्दों और चिंताओं की अंतिम जांच परिणामों में जांच की जाएगी।
- मौखिक सुनवाई की तारीख की घोषणा डीजीटीआर की वेबसाइट ([dgtr.gov.in](http://dgtr.gov.in)) पर की जाएगी।
- प्राधिकारी आवश्यकतानुसार आगे सत्यापन करेंगे।
- प्राधिकारी अंतिम जांच परिणामों की घोषणा करने से पूर्व नियमानुसार आवश्यक तथ्यों को प्रकट करेंगे।

बी. बी. स्वैन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th August, 2020

**PRELIMINARY FINDINGS****Case No: CVD-OI-05/2019****Sub: Preliminary Findings in the anti-subsidy investigation concerning imports of “Flat Products of Stainless Steel” from Indonesia.****F. No.6/16/2019-DGTR .— A. BACKGROUND OF THE CASE**

Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as “the Act”), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter also referred to as “the Rules”) thereof:

1. Indian Stainless Steel Development Association (ISSDA), Jindal Stainless Limited (JSL), Jindal Stainless (Hisar) Limited and Jindal Stainless Steelway Limited (JSSL) (hereinafter also referred to as “the Applicants” or “the Domestic Industry”) have filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as “the Authority”) in accordance with the Act and the Rules for imposition of Countervailing duty on imports of “Flat Products of Stainless Steel” (hereinafter also referred to as “subject goods”) from Indonesia (hereinafter also referred to as the “subject country”).
2. The Authority, on the basis of sufficient prima facie evidence submitted by the Applicant, issued a public notice vide Notification No. 6/16/2019 - DGTR dated 18<sup>th</sup> October, 2019, published in the Gazette of India, initiating the subject investigation in accordance with Rule 6 to determine the existence, degree and effect of the alleged subsidy and to recommend the amount of anti-subsidy/countervailing duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

**B. PROCEDURE**

3. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to the subject investigation:
  - a) The Authority notified the Embassy of the Subject Country in India about the receipt of the present anti-subsidy application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule (5) of Rule 6 supra.
  - b) The Authority invited the Government of Indonesia for consultation with the aim of clarifying the situation and arriving at a mutually agreed solution in accordance with Article 13 of the Agreement on subsidies and countervailing measures. The consultation was held on 23<sup>rd</sup> September, 2019 at New Delhi, which was attended by representatives of the Government of Indonesia.
  - c) The Authority issued a public notice dated 18<sup>th</sup> October 2019, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating anti-subsidy investigation concerning imports of the subject goods from the subject country.
  - d) The Authority sent a copy of the initiation notification to the Embassy of the Subject Country in India, known producers/exporters from the subject country, known



importers/users and the Domestic Industry as well as other domestic producers as per the addresses made available by the Applicants and requested them to make their views known in writing within the prescribed time-limit.

- e) The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassy of the subject country in India in accordance with Rule 7(3) of the Rules.
- f) The Embassy of the subject country in India was also requested to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject country.
- g) The Authority sent questionnaire to the Government of Indonesia in order to seek relevant facts/information with regard to various schemes/programs where countervailable benefit might have been conferred by the Government.
- h) The Authority sent questionnaires to the following known producers/exporters in the subject country in accordance with Rule 7(4) of the Rules:
  - (i) PT IMR ARC Steel
  - (ii) PT Bintang Asia Usaha
  - (iii) PT Tsingshan Steel
- i) In response, the following exporters/producers from the subject country filed exporter's questionnaire response:
  - (i) PT Indonesia Guang Ching Nikel and Stainless Steel Industry
  - (ii) PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel
  - (iii) PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy
  - (iv) PT Tsingshan Steel Indonesia
  - (v) PT Sulawesi Mining Investment, Indonesia
  - (vi) PT EKASA YAD RESOURCES, Indonesia
  - (vii) PT Bintangdelapan ;Mineral, Indonesia
  - (viii) Eternal Tsingshan Group Limited
  - (ix) Celerity Asia Trade Limited
  - (x) Golden Harbour International PTE. Ltd.
  - (xi) Hanwa Co. Ltd.
  - (xii) Schuang International Development Limited
  - (xiii) Stratus Steels DMCC
  - (xiv) Recheer Resources (Singapore) PTE. Ltd.
  - (xv) PT Hanwa Indonesia
  - (xvi) PT IMR ARC Steel, Indonesia
  - (xvii) IMR Metallurgical Resources AG

- j) Pursuant to the initiation notification, apart from the above producers/ exporters from the subject country, Government of Indonesia also filed the questionnaire response.
- k) The Authority sent Importer's Questionnaire to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 7(4) of the Rules:
- i. Accurate Steel
  - ii. Moonlight Tube Industries
  - iii. Amanat Steels Pvt. Ltd.
  - iv. Naman Steel
  - v. Aminox international
  - vi. National peroxide limited
  - vii. Ankur exports
  - viii. Navgrah fastners Pvt. Ltd.
  - ix. Anupam impex
  - x. Navgrah fastners Pvt. Ltd.
  - xi. Montex stainless and alloys
  - xii. Navpad steel centre
  - xiii. Ashok metal corporation
  - xiv. Navyug metal corporation
  - xv. Ashwin impex
  - xvi. Nenava metal corporation
  - xvii. B.V.S. Overseas
  - xviii. Neptune Steel Impex
  - xix. Balaji Impex
  - xx. NG Industries
  - xxi. Balaji Niryaat Private
  - xxii. Nickel Impex LLP
  - xxiii. Bhalaria metal craft Pvt. Ltd.
  - xxiv. Numax steels
  - xxv. Bharat Exports
  - xxvi. Ohsung Electronics India Private Limited
  - xxvii. Bhavyadeep Impex
  - xxviii. Om Gurudev Metals
  - xxix. Chanchal Metal & Tube
  - xxx. P.P. Impex (india)
  - xxxi. Chirag Udyog

- xxxii. Pacific Metal Trading Co
- xxxiii. Devdeep Steel Alloys
- xxxiv. Param Industries
- xxxv. Dhanera Impex.
- xxxvi. Paras Impoexpo Pvt. Ltd..
- xxxvii. Dhanera Metal Supply Corporation
- xxxviii. Phoenix Foils Pvt. Ltd.
- xxxix. Minox Metal Private Limited
  - xl. Posco-India Pune Processing Center Pvt. Ltd.
  - xli. Divine Overseas Private Limited
  - xlii. Rajesh Steel
  - xliii. Flange Forge India
  - xliv. Rajguru Enterprises Pvt. Ltd
  - xlv. Forte Impex Pvt. Ltd.
  - xlvi. Ramani Steel House
  - xlvii. Godrej & Boyce Mfg. Co. Ltd.
  - xlviii. Randen Engineering Pvt.Ltd.
  - xlix. Goodluck Metal Corporation
    - l. Riddhi Siddhi Impex
    - li. Goodluck Steels
    - lii. Welkin Infotech Private Limited
    - liii. H. K. Impex Pvt. Ltd.
    - liv. S S Impex
    - lv. Him Enterprises
    - lvi. Saneet Steelsa
    - lvii. Hindustan Inox Limited
    - lviii. Saraswati Steel India
    - lix. Hindustan Syringes And Medical Devices Ltd.
    - lx. Seth Iron & Steel Pvt. Ltd.
    - lxi. Home Zone Metals Private
    - lxii. Shah Foils Limited
    - lxiii. Home Zone Stainless Private Limited
    - lxiv. Shakti Pumps India Limited
    - lxv. Horizon Chutes Pvt.
    - lxvi. Shree Ashapura Steel Centre

- 
- lxvii. Hypro Engineers Pvt. Ltd..
  - lxviii. Shree Mahavir Steel
  - lxix. Igp Engineers Private Limited
  - lxx. Shree Ramdev Metal Mart
  - lxxi. Inco Steel
  - lxxii. Shree Ramdev Steels Pvt.Ltd.
  - lxxiii. Inox Stainless
  - lxxiv. Shree Swangiya Metal Industries
  - lxxv. J.Y. International
  - lxxvi. Shree Tube Mfg.Co.Pvt.Ltd.
  - lxxvii. Jagdamba Cutlery Private Limited
  - lxxviii. Shree Vallabh Metals
  - lxxix. Jaiman Metalloys Llp
  - lxxx. Shriram Handles
  - lxxxii. Jainex Steel & Metal
  - lxxxiii. Siddhant Steel
  - lxxxiv. Jay Laxmi Metal Corporation
  - lxxxv. Siddhivinayak Steel
  - lxxxvi. Jayna Steel India
  - lxxxvii. Silver Steels
  - lxxxviii. Jewel Impex Pvt. Ltd.
  - lxxxix. Stainox Alloys Pvt. Ltd.
  - lxxxix. Jfe Shoji Trade India Private Limited
  - xc. Steel International Mahavir Darshan
  - xc. Kamal Metal Corporation
  - xcii. Steel Line (India)
  - xciii. Keshoram Industries
  - xciv. Steel Yard Overseas
  - xcv. Keyur Kitchenware
  - xcvi. Stride Industries LLP
  - xcvii. Kitchen Essentials
  - xcviii. Suchi Fasteners Pvt. Ltd.
  - xcix. Kraftwares (India) Private Limited
  - c. Suman Metalshop
  - ci. Kunal Housewares Pvt.Ltd.

- cii. Suncity Sheets Pvt. Ltd.
  - ciii. Larsen & Toubro Limited
  - civ. Suncity Strips & Tubes Private Limited
  - cv. Lubi Industries Llp
  - cvi. Sunder Impex Pvt. Ltd.
  - cvii. M. P. Steel Centre
  - cviii. Super Impex
  - cix. Magppie International Ltd
  - cx. Swastik Industries
  - cxi. Mahaveer Stainless Steel
  - cxii. Trident Steel
  - cxiii. Mars Housewares
  - cxiv. Uttam Steel Alloys Pvt. Ltd.
  - cxv. Maruti Suzuki India Limited
  - cxvi. Vishal Steels
  - cxvii. Maxim Tubes Company Pvt. Ltd.
  - cxviii. Veena Steel Industries
  - cxix. Mayfair International
  - cxx. Victora Auto Pvt. Ltd.
  - cxxi. Metal One Corporation India Private Limited
  - cxxii. Vikram Metal [India]
  - cxxiii. Milan Steel
- l) In response, the following importers/users have responded and filed importer's questionnaire response.
- (i) Indian Coke and Power Pvt. Ltd.
- m) Apart from the respondent exporters and importers mentioned above, some legal submissions have been received on behalf of the following parties during the course of this investigation.
- (i) PT Bintang Asia Usaha (BAU), Indonesia
- n) The Authority made available non-confidential version of the evidence presented / submissions made by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties. Submissions made by all interested parties have been taken into account in this Preliminary Finding Notification.
- o) Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigation, which was received by the Authority. The Authority has relied upon the DGCI&S data for computation of the volume and value of imports and its analysis after due examination of the transactions.

- p) The Non-Injurious Price (NIP) has been determined based on the cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the Domestic Industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) so as to ascertain whether countervailing duty lower than the subsidy margin would be sufficient to remove the injury to the Domestic Industry.
- q) Considering the fact that the subject goods are being imported in various grades/sizes/forms, the applicants have proposed Product Control Numbers (PCNs) in order to make a PCN to PCN comparison for computing the injury margin. The Authority proposes to adopt the same PCN methodology as published vide notification 6/12/2019-DGTR dated 14th August, 2019 in a parallel anti-dumping investigation concerning imports of Flat Rolled Products of Stainless Steel initiated vide Notification 6/12/2019-DGTR dated 3rd July, 2019.
- r) The Period of Investigation for the purpose of the present anti-subsidy investigation is from April 2018 to March 2019 (12 Months). The injury investigation period covers the period Apr2015-Mar16, Apr2016-Mar17, Apr2017-Mar18 and the POI.
- s) The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority in this preliminary findings.
- t) Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- u) Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the preliminary findings on the basis of the facts available.
- v) \*\*\*in this preliminary finding represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- w) The exchange rate adopted for the subject investigation is US\$1 = ₹70.82.

#### **C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE**

4. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as:

*“The product under consideration in the present application is “Flat Rolled Products of Stainless Steel”, excluding the following:*

- a. *Blade Steel, or commercially known as razor blade grade steel used in the production of razor*
- b. *Coin Blank falling under 7326 9099 used in the production of monetary coins.*

*Product under consideration can be transacted in a number of different forms, such as coils, sheets, plates, circles, strips or otherwise. All forms of the product are within the scope of the product under consideration. The subject goods fall under Customs Sub-heading ‘7219’ and ‘7220’ of Chapter 72 of the Act. Customs classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of present investigation.”*

**C.1. Submissions made by the Domestic Industry**

5. The submissions made by the Domestic Industry with regard to product under consideration and like article and considered relevant by the Authority are as follows:

- a) The product under consideration in the present application is “Flat Rolled Products of Stainless Steel, excluding the following
  - i. Blade Steel, or commercially known as razor blade grade steel used in production of razor
  - ii. Coin Blank falling under 7326 9099 used in production of monetary coins
- b) Product under consideration can be transacted in a number of different forms, such as coils, sheets, plates, circles, strips or otherwise. All forms of the product are within the scope of the product under consideration.
- c) Different forms/types of the product under consideration varies in terms of product specifications, which are achieved by the producers to meet the specific end application. The product under consideration is broadly classified into following series:
  - i. 200 series
  - ii. 300 series
  - iii. 400 series
  - iv. Duplex
- d) Within each of these series, the product can have a number of different specifications and are designated by different grades.
- e) Generally, the product is first produced in hot conditions (called hot rolled) and thereafter rolled in cold conditions (called cold rolled). Various properties in the product are achieved by targeting right chemical composition and by subsequent processing in the plant. The producer in subject country and the domestic industry in India typically hold sufficient production facilities to achieve different product specifications desired by the consumers.
- f) The product under consideration falls under customs sub-heading nos. 7219 and 7220 of Chapter 72 of the Customs Tariff Act, 1975. The classification is however indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation. Under Customs Tariff, the product is described variedly on the basis of following parameters:
  - i. Width – below and above 600 MM
  - ii. Whether or not further worked than hot-rolled (i.e., hot rolled, cold rolled, etc.)
  - iii. Whether or not further worked than cold-rolled
  - iv. Form – such as coils, sheets, plates and circles
  - v. Thickness – such as exceeding 14mm, 10-14mm, 4.75-10 mm, 3-4.75 mm, less than 3mm, etc.
  - vi. Chromium or nickel chromium austenitic type
- g) Product under consideration is normally produced and sold in terms of net weight expressed in terms of kgs or MT.
- h) The subject goods are used for manufacture of various kinds of products viz. architecture building construction, consumer durables, process & engineering and automobile railway transport.

- i) The petitioners proposed following PCN methodology to be adopted for the purpose of present investigation.

1	Condition	HR, CR, HRAP, CRAP
2	Grade	201, 202, 216, 204CU, 212-YKK, 253 MA, J4, J5, J6, J7, J8, JS LAUS, JSLU, JT, 301, 304/L, 309, 310/S, 316/L, 317, 321, 347, 405, 409, 410/S, 415, 420, 430, 432, 436, 439, 441, 444, 446, DUPLEX, 904 L, Super Aus and their variants under various standards
3	Form	Coil, Plate, Sheet
4	Width	Width less than 600 MM, Width 600 MM or more
5	Thickness	<0.5 MM, =>0.5 MM (only for CR/CRAP)
6	Finish	Black, No 1 HRAP, No 2B AND 2D CRAP Special (Scotch Brite, HL, NN, No 3, No 4 etc), Tempered

## C.2. Submissions made by the other interested parties

6. The submissions made by the exporters, importers, users and other interested parties with regard to product under consideration and like article, and considered relevant by the Authority, are as follows:
- a) Product exported by PT Bintang Asia Usaha (BAU) falls outside the scope of product under consideration prescribed in the notice of initiation.

## C.3. Examination by the Authority

7. The submissions made by the Domestic Industry and other interested parties with regard to the PUC related issues are examined and addressed hereunder.
8. The very first step in an investigation is to identify the product under consideration. The product under consideration is the imported product which is allegedly causing injury to the domestic industry. The product under consideration (PUC) in the present investigation, as defined in the initiation notification is "Flat rolled products of stainless steel". The product scope specifically excludes Blade Steel, or commercially known as razor blade grade steel used in the production of razor and Coin Blank falling under 73269099 used in the production of monetary coin. The product under consideration is classified in Chapter 72 under customs heading nos. 7219 and 7220 of the Customs Tariff Act, 1975.
9. The Authority notes that the subject goods are being imported in various grades/sizes/forms. The applicants have proposed Product Control Numbers (PCNs) in order to make a PCN to PCN comparison. The Authority has adopted the same PCN methodology as published vide notification 6/12/2019-DGTR dated 14th August 2019 in a parallel anti-dumping investigation concerning imports of Flat Rolled Products of Stainless Steel initiated vide Notification 6/12/2019-DGTR dated 3rd July 2019.
10. The basic production process involved in the production of the product under consideration involves melting the raw materials, scrap (alloy and non-alloy) and ferro-alloys in an electric arc furnace, where powerful electric arcs start to melt the scrap and alloys. The hot rolling process begins at the reheat furnace where the slabs are heated to between 1100 and 1300°C, depending on the stainless-steel grade. The hot rolled products are softened (annealed) and descaled (pickled



with acids). Cold rolling of the Hot rolled stainless steel takes place in Sendzimer mills (Z-mills), which produce smooth, shiny finished, cold rolled stainless steel by rolling the HR steel. The product is first produced by rolling Slab in hot condition/form. It can thereafter be sold in the market, or cold rolled further. Cold rolled products cannot be made directly from scrap or slab and cold rolled steels are formed by rolling of hot rolled coils at specific temperature.

11. Product under consideration is used for manufacture of white goods, processed equipment, dairy equipment, re-rolling, reactor vessels, material handling equipment, railways, pipes & tubes, automotive components, rail carts, metro coaches, architecture, building and construction, rolled formed sections, industrial fabrication etc.
12. Questionnaire response filed by the responding producers/ exporters and information provided by the domestic industry show that the producers tend to produce both hot rolled and cold rolled products and offer these in a wide range of shape, size, and metallurgical composition to suit specific end consumer requirements. However, the Authority notes that the domestic industry is not producing 'Flat Rolled Products of Stainless Steel of width more than 1650 MM' & 'Flat Products of Stainless Steel of thickness greater than 80 MM'. Accordingly, 'Flat Products of Stainless Steel of width more than 1650 MM' & 'Flat Products of Stainless Steel of thickness greater than 80 MM' are provisionally excluded from the scope of PUC.
13. With regard to like article, it is noted that Rule 2(ca) of the Rules provides that "like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation. On the basis of information on record, the Authority provisionally holds that there is no known difference in the subject goods produced by the Indian industry and those imported from the subject country. The two are comparable in terms of physical characteristics, functions and uses, product specifications, and tariff classifications of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The Authority, thus, provisionally holds that the products manufactured by the Applicants constitute like article to the subject goods being imported into India from the subject country.
14. On the basis of submissions made by various interested parties and the information on record, the Authority provisionally holds that the product under consideration is as under:

*"The product under consideration in the present application is "Flat Rolled Products of Stainless Steel", excluding the following:*

- a. *Blade Steel, or commercially known as razor blade grade steel used in the production of razor.*
- b. *Coin Blank falling under 73269099 used in the production of monetary coins.*
- c. *Flat Rolled Products of Stainless Steel of width more than 1650 MM.*
- d. *Flat Rolled Products of Stainless Steel of thickness greater than 80 MM.*

*Product under consideration can be transacted in a number of different forms, such as coils, sheets, plates, circles, strips or otherwise. All forms of the product are within the scope of the product under consideration. The subject goods fall under Customs Tariff heading '7219' and '7220' of Chapter 72 of the Act. Customs classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of present investigation."*

15. The Authority further notes that exclusion of Flat Rolled Products of Stainless Steel of width more than 1650 MM would only be applicable in case of bonafide use by importers/ users for end use in the same form. Exclusion would not be applicable in those cases where the imported flat

rolled products of stainless steel of width more than 1650 mm would be slit into products having width lower than 1650 mm.

#### **D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING**

##### **D.1. Submission of other interested parties**

16. Interested parties other than the domestic industry have made following submissions with regard to the standing of the Domestic Industry.

- i. M/s. Jindal Stainless (Hisar) Limited, Jindal Stainless Ltd. and Jindal Stainless Steelway Limited (collectively, hereinafter referred to as applicant industry in the above-mentioned investigation) are ineligible to be considered as eligible Domestic Industry in term of Rule 2 (b) of the CVD Rules as there is no discretion available under Rule 2(b) with the Authority to consider applicant industry as eligible Domestic Industry.
- ii. In contradiction to AD Rules, CVD Rules considers the applicant ineligible if they themselves or their related parties had imported the subject goods even from “Other Countries”.
- iii. The applicants are related to both Jindal Saw Ltd., and Jindal Quality Tubular Ltd., as is evident from annual reports of Jindal Saw Ltd., and Jindal Quality Tubular Ltd.
- iv. Jindal Saw Ltd., and Jindal Quality Tubular Ltd are importers of the product under consideration during the period under investigation. Thus, applicants are related to importer of the subject goods.
- v. PT. Jindal Stainless Indonesia, has exported the subject goods to India through a trader situated in Hong Kong during the POI.
- vi. PT. Jindal Stainless Indonesia has exported the subject goods to India even in the Injury period and the law does not say that related party transaction should be checked only with regard to POI. Such an interpretation would frustrate the intent of the legislature which did not restrict the imports to the POI to prevent any possibility of manipulation by the applicant industry.
- vii. Even the Authority calculates recurring subsidies, considering past period up to the actual useful life of the machinery (AUL), which is beyond POI. Thus, it would be inappropriate for the Authority to adopt a different interpretation with regard to relationship and restrict the test to POI only.

##### **D.2. Submissions made by the Domestic Industry**

17. The submissions made by the Domestic Industry during the course of the investigation with regard to scope of Domestic Industry & standing are as follows:

- i. Petitioner companies’ production constitutes more than 50% of Indian production. Accordingly, Production by the petitioner companies constitutes a major proportion in Indian production and therefore petitioners constitute “Domestic Industry” within the meaning of Rule 2 (b) of the CVD Rules.
- ii. Petitioner companies have not imported the subject goods during the period of investigation. Petitioner companies are related to a producer of the subject goods in Indonesia. However, that does not affect the eligibility of petitioners under Rule 2(b).

- iii. The allegation that Jindal Saw Ltd. (Jindal Saw), and Jindal Quality Tubular Ltd. (JQTL) are related party to JSL and JSHL and are importer of the subject goods and that PT. Jindal Stainless Indonesia, has exported subject goods to India during the period of investigation, is baseless and factually incorrect.
- iv. Domestic producers shall be deemed to be related to exporters or importers only if one of them directly or indirectly controls the other; or both of them are directly or indirectly controlled by a third person; or together they directly or indirectly control a third person.
- v. A producer shall be deemed to control another producer when the former is legally or operationally in a position to exercise restraint or direction over the latter. None of the mentioned situations exist in the present case and thus it should be considered that JSL/JSHL are not related to Jindal Saw/JQTL.
- vi. Applicant domestic industry does not consider these two entities as related entity in terms of legal provisions. The applicant companies have not reported in their Annual reports these companies as their related entity.
- vii. None of the shareholders (barring investment entities/financial institutions) owns or holds 5% or more of the outstanding voting stock or shares at the same time in either JSL/JSHL on one hand and JSAW/JQTL on other hand.
- viii. Barring one independent director, there are no common directors between boards of JSHL on one hand and Jindal Saw on the other hand. As per the annual Report of the companies that there are no common directors between Jindal Saw & JSL and also between JTQL & JSHL/JSL and there are no common key managerial personnel between JSL/JSHL on one hand and Jindal Saw/JQTL on the other hand .
- ix. Considering voting rights, the fact of existence of one common director, and that too an independent director, does not mean “legally or operationally in a position to control”. There are various instances of an independent director being appointed as director in more than one company.
- x. Securities and Exchange Board of India (SEBI) guidelines specifically provide that a person can be independent director in up to seven companies. Thus, the logic that merely on account of a person being a common independent director makes him “legally or operationally in a position to control” and therefore making two entities related is erroneous.
- xi. An independent director is governed by strict laws and expected to abide by the Code of Conduct under Companies Act 2013. This ensures that the independent director shall not allow any extraneous considerations that will vitiate his exercise of objective independent judgment in the paramount interest of the company as a whole, while concurring in or dissenting from the collective judgment of the Board in its decision making. An independent director therefore cannot be considered as interested in either of the companies.
- xii. Day to day functioning of Jindal saw and JSHL/JSL is conducted by their own board of directors. The Board of Directors take decision by a majority. One common director cannot in any situation influence any decision. The applicant companies have never reported these companies as related companies and reporting of the applicant companies have never been questioned by any statutory authority.

- xiii. To the allegation that PT Jindal Indonesia has exported the subject goods to India even in the injury period, the applicants have submitted a letter from PT Jindal Stainless, Indonesia, along with relevant information on the global exports made by the company.
- xiv. PT Jindal imports hot rolled stainless steel products from India and other countries and produces cold rolled stainless flat products which are sold domestically and are also exported globally. However, it has not exported subject goods to India during the entire injury period. PT Jindal has exported only “Scrap” to India to the applicant companies during POI, which is not the product under consideration in the present investigation.
- xv. PT Jindal has not exported product under consideration in Indian market in the entire injury period including POI, either directly, or indirectly. Even in a case of exports through trader, the goods are shipped directly from the manufacturer’s premises to the country concerned. Thus, even in exports through trader, PT Jindal ships the goods directly to the country concerned and is aware of the eventual country where the goods were destined. This can also be verified from sales details that have been provided by the company. Thus, it would be seen that there are no exports of the product under consideration by the related company of the applicants, PT Jindal Stainless, Indonesia to India.
- xvi. To the allegation that PT Jindal Indonesia has exported the subject goods to India even in the injury period since the Authority calculates recurring subsidies availed in the past period up to the actual useful life of the machinery (AUL), which is beyond POI, it is the consistent practice of the Designated Authority to consider imports /exports during the POI only to decide eligibility. PT Jindal Stainless though has not exported subject goods in the entire injury period.

### **D.3. Examination by the Authority**

18. Rule 2(b) of the Rules prior to amendment vide Notification 10/2020-Customs(NT) dated 2.2.2020 provided as follows:

*“domestic industry means the domestic producers as a whole of the like article or domestic producers whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article, except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged subsidized article, or are themselves importers thereof, in which case such producers shall be deemed not to form part of domestic industry”.*

19. Definition of domestic industry subsequent to amendment vide Notification 10/2020-Customs(NT) dated 2.2.2020 reads as under:

*“domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article, except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged subsidised article, or like article from other countries or are themselves importers thereof:”*

*“Explanation. - For the purposes of this clause, producers shall be deemed to be related to exporters or importers only if,-*

*(a) one of them directly or indirectly controls the other; or*

*(b) both of them are directly or indirectly controlled by a third person; or*

*(c) together they directly or indirectly control a third person, subject to the condition that there are grounds for believing or suspecting that the effect of the relationship is such as to cause the producers to behave differently from non-related producers.”*

*Note: For the purpose of this Explanation, a producer shall be deemed to control another producer when the former is legally or operationally in a position to exercise restraint or direction over the latter.”*

20. Some interested parties have argued that the applicant companies are ineligible domestic industry as they have related parties, namely Jindal Saw Ltd (Jindal saw), and Jindal Quality Tubular Ltd. (JQTL), who have imported subject goods. It has also been argued that PT Jindal, Indonesia, another related party of the applicants in Indonesia, has exported subject goods to India via Hong Kong through trader.
21. As regards the argument regarding relationship between applicant companies and Jindal Saw and JQTL on the basis of annual report of Jindal Saw and JQTL, it is noted that annual report(s) cannot be conclusive factor to decide the issue of relationship between companies. In this particular case, Jindal Saw and JQTL have been claimed to be related companies. Jindal Saw in its annual report has listed some 54 entities wherein its key management personnel and their relatives exercise significant influence and the name of the applicant companies figure therein. The applicant companies in their annual reports do not consider Jindal Saw and JQTL as related parties.
22. The Authority notes that in term of Rules, producers shall be deemed to be related to exporters or importers only if (a) one of them directly or indirectly controls the other, or (b) both of them are directly or indirectly controlled by a third person or (c) together they directly or indirectly control a third person, subject to the condition that there are grounds for believing or suspecting that the effect of the relationship is such as to cause the producers to behave differently from non-related producers. Further, a producer shall be deemed to control another producer when the former is legally or operationally in a position to exercise restraint or direction over the latter. The Authority therefore has examined the issue of relationship of the applicant companies (“first party”) with the Jindal Saw Ltd (Jindal saw), and Jindal Quality Tubular Ltd. (second party”).
23. The interested party alleging relationship between first party and second party has not established that one of the parties directly or indirectly controls the other party, or both of them are directly or indirectly controlled by a third person/parties, or together they directly or indirectly control a third person/party. The Authority further notes that it has not been demonstrated that there are grounds for believing or suspecting that the effect of the alleged relationship is such as to cause the first party to behave differently from non-related producers.
24. The Authority has taken note of information provided by the applicants showing that (a) none of the shareholders (barring investment entities/financial institutions) owns or holds 5% or more of the voting stock or shares at the same time in the first and second party. The Authority notes that the key element in regard to relationship of the applicant companies and JSW & JQTL is ‘control’, legal or operational. The Authority finds that none of the shareholders (barring investment entities/financial institutions) owns or holds more than 5% voting stock or shares at the same time in the first and second party. Mere shareholding does not amount to exercise of legal or operational control unless, the shareholding is proved to be in majority and the same has led to legal or operational control over the other party. (b) there are no common key managerial personnel between first and second party (c) day-to-day functioning of first party and second party are conducted subject to overall superintendence & control of the Board of Directors of the respective companies (d) applicant companies have not reported alleged related companies as their related entity in their annual reports. It is further seen that there is only one common independent director namely, Shri Girish Sharma in the boards of JSHL and Jindal Saw.

25. Section 149(6) of the company Act, 2013 and Provision 16 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, deal with the issue of appointment of independent director(s) in a company. The Authority notes that person having no direct or indirect relationship or interest with the promoters or shareholders of the company or any related or subsidiary company can only be appointed as an independent director in a company. The purpose of appointment of the independent director is to ensure objectivity and fair play in decision-making in a company and he is not supposed to allow to bring in any extraneous considerations that will vitiate his exercise of objective independent judgment in the paramount interest of the company as a whole, while concurring in or dissenting from the collective judgment of the Board in its decision making. An independent director therefore cannot be considered as interested in either of the companies. Even otherwise the Board of Directors take decision by a majority voting and one common independent director cannot in any situation influence any decision in the two companies and thus cannot be considered to be in a position to lead the company to legally or operationally control the other company nor such common independent director can be in a position to exercise restraint or direction over the other.
26. Based on evidence on record, it is noted that neither Applicants directly or indirectly control Jindal Saw and JQTL, nor these are directly or indirectly controlled by a third party/entity, nor together they directly or indirectly control a third party/entity. The Authority further notes that it has not been established that any of these parties is legally or operationally in a position to exercise restraint or direction over the other party. In view of the above the Authority does not consider Jindal Saw Ltd and Jindal Quality Tubular Ltd. as related parties to the applicant companies within the meaning of the Rules.
27. As regards the submission that PT. Jindal Stainless Indonesia, has exported the subject goods to India through a trader situated in Hong Kong, it is noted that PT. Jindal Stainless Indonesia has submitted their invoice by invoice details of total global sales which show that subject goods have not been exported from Indonesia to India during the entire injury period. It is seen that only “scrap” has been exported to India, which is not the product under consideration. Thus, the claim of the interested parties is factually incorrect. The Authority thus notes that Applicants are not related to any importer or exporter of the subject goods. It is further noted that evidence on record shows that Applicants have not imported the subject goods either. It is further noted that Applicants’ production account for more than 50% of Indian production.
28. In view of the above, the Authority accordingly notes that the Applicants command a major proportion of the production of the subject goods in India and satisfy the standing requirement and constitute the domestic industry in terms of Rule 2(b) and Rule 6(3) of the CVD Rules.

## **E. ISSUES RELATING TO CONFIDENTIALITY**

### **E.1. Submissions by Domestic Industry**

29. The following submissions have been made by the Domestic Industry with regard to confidentiality issues:
- a) Applicant has disclosed all the essential information in the non-confidential version of the application in accordance with Rule 8 of CVD Rules.

### **E.2. Submissions by other interested parties**

30. None of the interested parties have filed any comments regarding the confidentiality of information.

### **E.3. Examination by the Authority**

31. With regard to confidentiality of information, Rule 8 of the CVD Rules provides as follows:

*“Confidential information. (1) Notwithstanding anything contained in subrule (1), (2), (3) and (7) of rule 7, subrule (2) of rule 14, subrule (4) of rule 17 and subrule (3) of rule 19 copies of applications received under subrule (1) of rule 6 or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorisation of the party providing such information.*

*(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish nonconfidential summary thereof in sufficient details to permit a reasonable understanding of the substance of the confidential information and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.*

*(3) Notwithstanding anything contained in subrule (2), if the designated authority, is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in generalised or summary form, it may disregard such information.*

32. The Authority made available non-confidential version of the information provided by various interested parties to all interested parties through the public file containing non- confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection.
33. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.

#### **F. DETERMINATION OF SUBSIDY AND SUBSIDY MARGIN**

34. The petition filed by Domestic Industry provided *prima facie* evidence of existence of countervailable subsidies in the subject country to initiate the instant investigation. Government of Indonesia was invited for consultation, which was held on 23<sup>rd</sup> September 2019 in New Delhi. The producers and exporters from Indonesia were advised to file response to the questionnaire and were given adequate opportunity to provide verifiable evidence on the existence, degree and effect of alleged subsidy program for making an appropriate determination of existence and quantum of such subsidies, if any.
35. The following producers/exporters from Indonesia including Government of Indonesia have filed questionnaire responses:—
  - i. PT Indonesia Guang Ching Nikel and Stainless Steel Industry
  - ii. PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel
  - iii. PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy
  - iv. PT Tsingshan Steel, Indonesia

- v. PT Sulawesi Mining Investment, Indonesia
- vi. PT EKASA YAD RESOURCES, Indonesia
- vii. PT Bintangdelapan Mineral, Indonesia
- viii. Eternal Tsingshan Group Limited
- ix. Celerity Asia Trade Limited
- x. Golden Harbour International PTE. Ltd.
- xi. Hanwa Co. Ltd.
- xii. Schuang International Development Limited
- xiii. Stratus Steels DMCC
- xiv. Recheer Resources (Singapore) PTE. Ltd.
- xv. PT Hanwa Indonesia
- xvi. PT IMR ARC Steel, Indonesia
- xvii. IMR Metallurgical Resources AG

### **General overview of the alleged Subsidy Programs**

#### **F.1. Submissions made by domestic industry**

- i. The domestic industry has contended that the Government of Indonesia is providing countervailable subsidies to its producers/exporters of the subject goods and has provided prima facie evidence of existence of such subsidy schemes in terms of legislation and policy documents. Accordingly, the domestic industry identified existence of certain numbers of countervailable subsidy schemes in Indonesia, within the meaning of ASCM and Indian Rules.
- ii. The Petitioners have submitted that the producers/exporters of subject goods in Indonesia have benefited from actionable subsidies. The Government of Indonesia has maintained various programs. Petitioners have considered documents such as legal notifications in form of circulars, notifications, regulations, laws, official reports, private reports, articles, WTO notifications, annual reports, etc. The petitioners have provided elaborate information regarding various subsidy programs. Petitioners further submit that below mentioned subsidy programs significantly lower the cost of production of the subject goods.
- iii. The programs of the Government of Indonesia constitute a subsidy because of the following reasons:
  - There is a financial contribution by government or a public body, where the government practice involves a direct transfer of funds (e.g. grants, loans, and equity infusion), government revenue that is otherwise due is foregone or not collected (e.g. fiscal incentives such as tax credits), government providing goods or services other than general infrastructure at less than adequate remuneration , or purchasing goods at more than adequate remuneration;
  - Benefit is thereby conferred on the Indonesian producers/ exporters of the PUC; and
  - The program is specific within the meaning of Indian CVD Rules and ASCM.
- iv. Relevant Indonesian laws and regulations, legal notifications in form of circulars, notifications, regulations, laws, official reports, private reports, articles, WTO notifications, annual reports,



constitute sufficient evidence of the existence of countervailable subsidy programs in Indonesia. These evidences were made available by the petitioner to all interested parties, including the Government of Indonesia and the known producers and exporters in Indonesia.

- v. Following is the list of various countervailable subsidies identified by the petitioners under various heads such as tax incentives, loans, debt restructuring, duty drawback and ad-hoc subsidies which has been provided to producers/ exporters by the Government of Indonesia.

S.No.	Program No.	Schemes
1.	Program No. 1	Benchmarking Coal Price for Electricity
2.	Program No. 2	Minimum value addition for export
3.	Program No. 3	Benchmark pricing for Minerals, Metals and Coal
4.	Program No. 4	Domestic Market Obligation (DMO) Scheme
5.	Program No. 5	Export Credit Insurance/reimbursement from losses
6.	Program No. 6	Export Credit Guarantees
7.	Program No. 7	Reduction of Income tax
8.	Program No. 8	Tax Holiday
9.	Program No. 9	Export Financing from Indonesia EXIM
10.	Program No. 10	Exemption on Import Duty
11.	Program No. 11	Import Duty Drawback
12.	Program No. 13	Reduction of Net Taxable Income
13.	Program No. 14	Carry Forward of Losses
14.	Program No. 15	Postponement of Import Duty
15.	Program No. 16	Exemption of Duty on Raw Material and Supporting Goods for Production Purpose
16.	Program No. 17	Exemption from Income Tax on Imports
17.	Program No. 18	Reduction for Investors investing in SEZ
18.	Program No. 19	Pioneer Industry Status
19.	Program No. 21	Deduction in Land Tax
20.	Program No. 23	Refund of VAT

- vi. Petitioners further submit that subsidies are also required to be considered having regard to benefits received by their affiliates in any of its form, including cross owned affiliates. The existence of countervailable subsidies is required to be examined/investigated in respect of countervailable subsidies in upstream product, in case such upstream products are supplied by affiliates.
- vii. Since benefits under some of these schemes are non-recurring, the existence of countervailable subsidies is required to be examined/investigated over the AUL (Average Useful Life). Thus, even if some non-recurring subsidies might have been withdrawn or not availed in the proposed

POI, the Designated Authority is required to investigate the same as long as it is evident that the benefit under the scheme was non-recurring.

- viii. Petitioner has an affiliated company engaged in producing and selling cold rolled stainless steels. The company is following 16 years as the AUL of assets. On this basis, the petitioners submit that the Authority may kindly consider 16 years as the life of assets.

## **F.2. Calculation Methodology**

36. Article 14 of ASCM, provides guidelines and methodology for calculating the benefit conferred to the recipient pursuant to paragraph 1 of Article 1 and further provides that any method used by the investigating authority to calculate the benefit to the recipient shall be transparent and adequately explained. Further, any method used by the investigating authority to calculate the benefit to the recipient shall be provided for in their national legislation or implementing regulations of the Member concerned and its application to each particular case shall be transparent and adequately explained. In accordance with the requirement, the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 lays down the methodology for determination of quantum of subsidization. The determination in this investigation is in accordance with these guidelines.

## **F.3. Examination of the Subsidy programs alleged by the Petitioners**

### **(i) Program No. 1: Benchmarking Coal Price for Electricity**

#### **a. Submission by Domestic Industry**

37. The Petitioners submitted that Indonesian Government determines the capping of maximum selling price for coal. Selling price for coal for electricity is set at US\$ 70 per MT. Any company engaged in production of coal is required to sell such coal following the decree issued by GOI, irrespective of its legal status. Coal is being made available at a cheaper rate to the domestic producers of subject goods by putting a maximum price cap on coal for purpose of electricity generation.

#### **b. Submission by Government of Indonesia/other interested parties**

38. Govt. of Indonesia sets benchmark price for coal sales for public electricity at US\$ 70/Metric to ensure availability of coal for public electricity. "Public" refers to the distribution of electricity for people consumption as a whole. Thus, benchmark price is not applicable for coal sales to private owned power plant for self-consumption.
39. The benchmark price for coal only apply for 2018 and 2019 periods. The regulation also sets maximum selling volume which the benchmark applies at 100 million metric tonnes of coal annually. There is no application process applied. This scheme does not provide any assistance to the responding companies.
40. The exporters submitted that they have not availed benefit under the scheme as the scheme is only applicable to coal prices for electricity that is supplied in the public interest. Since they are not supplying electricity, this scheme is not applicable. They are purchasing coal on the basis of International coal benchmark rate.

**(ii) Program No. 2: Minimum value addition for export and Domestic Market Obligation****a. Submission by Domestic Industry**

41. The Petitioners submitted that Indonesian Government ensures that there is abundant supply of raw material for mineral and metal downstream industries. This is done by (i) imposing prohibition on export of mineral ore and its concentrate without processing and refining, (ii) levying very high rates of export tax on the processed and refined minerals and metals and (iii) creating domestic market obligation by guaranteeing the supply of coal which is necessary for meeting the domestic demand.
42. Mining companies have to comply with the DMO requirements by selling their mineral/coal production to domestic consumers. It is mainly provided to business using Mineral/Coal as its input. By subjecting exports to duty/ restrictions and obligatory domestic market sales the government is artificially suppressing prices of minerals/coal in the domestic market which allows the downstream industries using it as inputs to procure them at low prices.

**b. Submission by Government of Indonesia/other interested parties**

43. The GOI issued the Govt. Regulation No. 1 of 2017 as the fourth amendments of Govt. regulation No. 23 of 2010 which requires the mining license holders to conduct in-country- process so as to increase the value of the minerals and coals products and accelerate the investment in mining sectors. GOI also retains the right of export of Minerals and Coal products. Mineral products are allowed to be exported only on satisfying minimum level of processing requirement as regulated under the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 25 of 2018. There is no minimum level of processing requirement for export of Coal products. No assistance/benefit in this program was received by the responding companies.
44. There is no basis to suggest that generally or in this particular case, imposition of such restrictions will invariably lead to fall in prices in the market place. It is also important to note that the imposition of export tax cannot be said to be a state interference resulting in distortion of the market. Imposition of export tax is absolutely legitimate and within the provisions of Article XX (g) & (i) of GATT.

**(iii) Program No. 4: Domestic Market Obligation (DMO) Scheme****a. Submission by Domestic Industry**

45. Indonesian Government policy is intended to guarantee the supply of minerals/coal for meeting the increasing domestic demand. The Central Government controls the production and the exports of each mining product. The regional government is also obliged to comply with the production and export controls that are imposed by the Central Government. The DMO applies to all types of coal and minerals. Mining companies must comply with the DMO requirements by selling their mineral/coal production to domestic consumers. Through imposition of such obligations government is artificially suppressing prices of minerals/coal in the domestic market which allows the downstream industries using it as inputs to procure them at low prices.

**b. Submission by Government of Indonesia/other interested parties**

46. Law Number 4 of 2009, the GOI requires minimum sale to domestic market for Mineral and Coal products through Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 39 of 2009 as amended by the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 25 of 2008.
47. In each year the GOI determines minimum percentage sales of coal for public interest. In 2018 and 2019 respectively, The GOI determines that 25% rate of domestic production is sufficient to meet domestic needs. In 2017 under Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 5 of 2017, the GOI determined that Nickel smelting company should use Nickel with Ni

less than 1.7% for at least 30% of its installed capacity. However, the Regulation was revoked in 2018 by Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 25 of 2018, and in the latter, the requirement no longer existed. Thus, there is no minimum sale to domestic market requirement for Mineral products.

**a. Examination by the Authority for programs 1, 2 and 4**

48. The Authority notes that program nos. 1, 2 & 4 relate to series of measures taken by the Government of Indonesia to regulate, monitor and control sales of coal and other minerals.
49. Ministry of Energy and Mineral Resources Regulation has regulated production/processing and sale of minerals, wherein minerals and ores are required to be domestically processed before being exported. It is noted that there is restriction on exports of mineral and ore.
50. The Government of Indonesia also retains the right of exports of Mineral and Coal products. However, Mineral products are allowed to be exported only if they have satisfied minimum level of processing requirements as regulated under the Minister of Energy and Mineral Resources regulation Number 25 of 2018. Moreover, the GOI allows export of nickel ore with Ni content less than 1.7 percent but such exports are subjected to 10% export tax. Additionally, the domestic market obligations are required to be met for Coal. The domestic market obligation was set at 25% of the production in 2019.
51. Thus, the coal producers/miners are forced to first provide coal to meet the domestic demand. The Authority notes that the Government of Indonesia by means of export tax, export restrictions and by allowing existence of the legal acts requiring Coal producers to sell domestically in Indonesia is directing private entities to provide financial contribution to steel producers in the form of sale of Nickel ore and Coal at less than adequate remuneration. Thus, Coal and Nickel is available to the producers of the product under consideration at less than adequate remuneration. Amount of benefit is equal to the difference between the price paid by stainless steel producers in Indonesia and the price that would have been payable in absence of these measures. The subsidy program is also specific because it is limited to certain specific enterprises or sectors that use Nickel, Coal and other minerals in their production of finished goods.
52. With regard to coal, the benchmark price settings for coal was also enacted in 2011 through Minister of Energy and Mineral Resources No. 0617 K/32/MEM/2011 on Coal Price which applied for coal purchased by for National Electric Company (PLN) PLN. However, the benchmark price does not apply for coal sales to private-owned power plant for self-consumption including for operation of production facility. The Authority considers that the power sold by the power generating company may have an element of subsidies. However, in the absence of specific evidence on record with regard to sale of power by power generating companies to steel producers, the Authority has not considered this for further analysis at this stage, pending further investigation. However, the series of steps by Government of Indonesia are directing private entities to provide Nickel ore and Coal at less than adequate remuneration by means of export tax, export restrictions and by allowing existence of the legal acts requiring Coal producers to sell domestically in Indonesia. Thus, Coal and Nickel is available to the producers of the product under consideration at less than adequate remuneration.
53. None of the producers/exporter have provided complete information regarding the benefit received pursuant to these programs based on their purchase of Coal and Nickel ore. The Authority provisionally determines that these programs are countervailable and benefit is conferred to the exporters within the meaning of Rules and ASCM agreement and hence countervailing duty should be imposed provisionally against these programs based on facts available.

**(iv) Program No. 3: Benchmarking pricing for Minerals, Metals and Coal****b. Submission by Domestic Industry**

54. The Petitioners submitted that the MoEMR (Minister of Energy and Mineral Resources), through the DGoMC (Director General of Minerals and Coal), is responsible for setting the benchmark prices for coal and metal minerals. If the Standard price (benchmark) for the relevant metal or coal, determined by MoEMR is set below appropriate market rate, the royalty fees calculated as payable to the Government of Indonesia will be less than the royalty fee calculated using market rate. Accordingly, the benefit conferred is the difference between the royalty fee calculated using the appropriate market rate for metals and coal and the royalty fee calculated using benchmark. Additionally, the royalty fee collected can also be influenced by the percentage of royalty determined on various kinds of metals or coal.

**c. Submission by Government of Indonesia/other interested parties**

55. As per Article 85 of the Regulation, the Ministry of Energy and Mineral Resources is responsible for setting the benchmark price. The Govt. of Indonesia sets the benchmark price on mineral, metal and coal products to optimize govt. revenue by the provision initiated in 2010 under Govt. Regulation No. 20 of 2010 as amended by Govt. Regulation No. 8 of 2018.

56. The benchmark price respectively for Mineral Metal and Coal products should reflect market mechanism and/or international market as per Regulation No.7 of 2017 of Minister of Energy and Mineral Resources. The mining concession holder must use the related formula and variables in calculating its benchmark price in every of its Mineral and Coal products domestic and export transaction. GOI will charge royalty on either benchmark rate or actual transaction price subject to the condition of whichever is higher.

57. The scheme is not countervailable because it does not provide any benefit whatsoever to the exporter. On the contrary, the scheme is designed in a manner that it may collect duty more than what is due but never less than the actual transactional value.

**c. Examination by the Authority**

58. Ministry of Energy and Mineral Resources is responsible for setting the benchmark of Indonesia as per Article 85 of the Regulation. It sets benchmark/minimum selling price of minerals and ore for the purpose of royalty collection. Authority notes that the benchmarking of mineral and ore is done only with the purpose of collecting royalties and optimize revenue.

59. The mining concession holders must use the related formula and variables in calculating its benchmark price in every of its Mineral and Coal products domestic and export transaction. If benchmark price is higher than the actual transactional value, the royalty amount will be based on benchmark price. If transaction value is higher than the benchmark price, royalty amount will be based on the transaction value.

60. The Authority has already provisionally concluded that nickel ore is available to Indonesian producers at less than adequate remuneration. There is no further benefit under this program. The Authority thus provisionally holds that no countervailing duty should be imposed against this program.

**(v) Program No. 5: Export Credit Insurance and reimbursement from losses****a. Submission by Domestic Industry**

61. State-owned firm Asuransi Ekspor Indonesia ('ASEI') provides comprehensive export credit insurance and reimbursements for the losses of export. ASEI reimburses exporters for up to 85 percent of their losses. It has specialized products to cover the risks borne by exporters and banks. It is mainly provided to enterprises engaged in exports except for enterprise engaged in exports of oil and gases. It confers a benefit equal to the difference between the amount the recipient pays on the premium for insurance and the amount the recipient would pay on a comparable insurance cover that the recipient could actually obtain on the market.

**b. Submission by Government of Indonesia/other interested parties**

62. Government Regulation No. 1/1982 enacted the export credit insurance and export credit guarantee programs. Export credit insurance is provided to insure/protect Indonesian exporters against the non-payment risk from their importers, whilst export credit guarantees are provided to insure Indonesian banks against the default risk of the borrower's export loan. In addition, Government Regulation No.20/1983 stipulated the establishment of a State-Owned Enterprise to carry out the provision of export credit insurance and export credit guarantees. None of the companies under investigation used this program.
63. Asuransi Asei is a subsidiary of a state-owned enterprise, 99.998% is owned by Indonesia-Re and 0.002% is owned by its employee cooperative. Asuransi Asei is a profit oriented/ commercial entity and continues to provide general insurance products and services (including credit insurance) to its corporate clients. Asuransi Asei has not offered export guarantees since 1995.

**c. Examination by the Authority**

64. Government Regulation No.20/1983 stipulated the establishment of a State-Owned Enterprise ("SOE") to carry out the provision of export credit insurance and export credit guarantees.
65. PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) was established to carry out the business for export credit guarantee and insurance. Persero established a subsidiary named PT. Asuransi Asei Indonesia (Asuransi Asei) and subsequently spun-off its insurance business in December 2014. It has been claimed that Asuransi Asei has not offered export guarantees since 1995.
66. Interested parties have also claimed that they have not received any benefit under this program. Authority provisionally determines that subject to further investigation no countervailing duty is required to be imposed against this program.

**(vi) Program No. 6: Export Credit Guarantees****a. Submission by Domestic Industry**

67. The Petitioners submitted that the State-owned Indonesia Eximbank provides export credit guarantees that permit banks to charge low rates for export financing as a result of which low rate of financing is available to export oriented enterprises.

**b. Submission by Government of Indonesia/other interested parties**

68. Both Indonesia Eximbank provide export credit guarantee to bank or financial institution against risk of debtor's default.
69. The program is eligible for both business entities and individuals domiciled in the territory of the Republic of Indonesia. There is no such law and regulations governing the eligibility criteria. Internal procedural of Indonesia Eximbank will be applicable for determining eligibility. None of the participating companies applied for, accrued, or received benefits from this program during the POI.

**c. Examination by the Authority**

70. The Authority notes that Indonesia Eximbank is a statutory body established under the Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Act and is 100% owned by GOI. Operation of Indonesia Exim Bank is subject to the Indonesia Central regulation (Bank Indonesia/BI) and Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) regulation. Therefore, export credit guarantee provided by Indonesia Eximbank amounts to financial contribution in the form of provision of service by Public Body at less than adequate remuneration.
71. Benefit is granted to enterprise in terms of the difference between the fee charged by Indonesia Eximbank and the fee charged by other commercial banks for providing the guarantee. However, none of the participating companies applied for, accrued, or received benefits from this program during the POI. Authority provisionally determines that pending further investigation no countervailing duty is required to be imposed against this program.

**(vii) Program No. 7: Reduction of Income Tax**

**a. Submission by Domestic Industry**

72. Indonesian Government provides for reduction of net income to a specified extent of the total investments made within a definite period. Article 18 of the Law of the Republic of Indonesia specifies the eligibility –
- (i) Makes an investment (expands its business; or makes a new investment)
  - (ii) Clears any one eligibility –
    - absorbs many workers
    - falls under a high priority scale
    - is engaged in infrastructure constructions
    - transfers technology
    - is engaged in a pioneer industry
    - is located in a remote area, a less-developed area, a contiguous area, or another area deemed needy
    - keeps the environment sustainable
    - conducts research, development, and innovation activities
    - is in partnership with micro, small and medium enterprises or cooperatives
73. Reduction of income results in lower income tax liability. Additionally, 5% reduction is applicable to companies listed on Indonesia Stock Exchange.

**b. Submission by Government of Indonesia/other interested parties**

74. The reduction of income tax for listed companies in Indonesia Stock Exchange (IDX) is firstly regulated under the Government Regulation Number 81 of 2007 as amended by the Government Regulation Number 77 of 2013. As stipulated in the former regulation, the reduction is to promote the role of capital market in financing business sectors, encourage the proliferation of public companies, as well as to increase public ownership in business entities. The reduction is provided at 5% rate of Corporate Income to listed companies in IDX which meet certain requirements. None of the participating companies is public company and listed to the IDX. Thus, none of them applied for, accrued, or received benefits from this program during the POI.

**c. Examination by the Authority**

75. Authority notes that two types of benefits are provided under this program in the form of reduction from income tax (i) Companies making investments during a prescribed period and fulfilling certain conditions will be allowed reduction of specified percentage from total income and (ii) 5% reduction is provided to companies listed on stock exchange in Indonesia.
76. All participating companies have submitted that they have not received any benefit under this program. Regarding the reduction of 5% rate of income tax, Authority notes that none of the participating companies are listed companies. However, interested parties and Government of Indonesia have not provided complete information and explanation regarding absence of benefit to participating companies based on investment criteria. The Authority does not have sufficient information and evidence at this stage to conclude that exemption from income tax was granted to enterprise based on investment criteria.
77. The Authority thus, pending further investigation, provisionally determines that no countervailing duty is required to be imposed against this program.

**(viii) Program No. 8: Tax Holiday**

**a. Submission by Domestic Industry**

78. Tax holiday is applicable in the form of reduction from Corporate Income Tax to relevant pioneer industry taxpayers that have made new capital investment plans of at least Rp 500 billion.

**b. Submission by Government of Indonesia/other interested parties**

79. Corporate Income Tax Reduction Facility in Tax Holiday shall be granted to income received or accrued from main business activity which constitutes a Pioneer Industry. In the April 2018, Tax Holiday was amended to provide a 100 percent income tax reduction for five to twenty years. As it currently stands, the Tax Holiday offers income tax reduction for 50 percent and 100 percent depending on the total investment value.
80. The corporation receiving the tax reduction has to be working in a “pioneer industry,” defined as an industry *“with extensive interconnection that provides added value and high externality, introduces new technology, and has strategic value for the national economy.”*
81. None of the companies under investigation applied for, accrued, or received benefits under this program during the POI.

**c. Examination by the Authority**

82. Authority notes that the program provides for reduction of income tax to certain enterprises incurring investment and meeting the prescribed eligibility criteria. Program provides for a financial contribution in the form of revenue foregone which is otherwise due and a benefit is thereby conferred.
83. None of the participating companies claims to have applied for, accrued, or received benefits under this program during the POI. Pending further verification, the Authority provisionally determines that no countervailing duty is required to be imposed against this program.

**(ix) Program No. 9: Export Financing from Indonesia EXIM**

**a. Submission by Domestic Industry**

84. Indonesian Exim bank -Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (‘LPEI’) provides export financing at preferential rates to support the improvement of the nation’s leading export products as well as to the high-competitive products by providing financing. Main function of LPEI is to



support the advancement of Indonesian exports and it serves to provide funding to regions that commercial banks or commercial financial institutions are reluctant to enter.

85. In addition to financing for exporters, Indonesia Exim bank may also provide financing to overseas buyer in order to import goods and services from Indonesia. Indonesian Exim bank's sources of funds according to Article 22 Act of LPEI are (i) issuance of marketable securities; (ii) loans from foreign governments, multilateral agencies, banks, financial institutions, and the GOI; (iii) grants; and (iv) fund placement by Bank Indonesia.

**b. Submission by Government of Indonesia/other interested parties**

86. Indonesia Eximbank is a special financial institution owned by Government of Indonesia and was established as part of mandate of the Act No. 2/2009 regarding Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). However, the operation of Indonesia Eximbank is subject to the Indonesia Central regulation (Bank Indonesia/BI) and Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) regulation.
87. Furthermore, the key activities of Indonesia Eximbank are financing (both conventional and Sharia compliant); guarantees; insurance; coaching and advisory services to banks, financial institutions, exporters manufacturers of export goods, especially small-and medium-sized enterprises and cooperatives; and special assignment by the Government to support the national export program. Govt. of Indonesia submitted that none of the companies under investigation applied for, accrued, or received benefits from this program during the POI.

**c. Examination by the Authority**

88. Authority notes that Indonesia Eximbank provides financing to enterprises including enterprises involved in export of goods. All participating entities are eligible to receive benefit under this program in form of preferential financing.
89. Authority notes that Indonesia Eximbank is a statutory body established under the Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Act and is 100% owned by Government of Indonesia. Operation of Indonesia Eximbank is subject to the Indonesia Central regulation (Bank Indonesia/BI) and Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) regulation. Therefore, export financing provided by Indonesia Exim Bank amounts to financial contribution in the form of direct transfer of funds by Public Body.
90. Amount of benefit is equal to the difference between the interest charged by Indonesia Eximbank/any other state owned bank and the interest charged by any other commercial banks on a comparable commercial loan. None of the participating companies have provided information regarding the loans obtained from Eximbank and/or any other state owned banks during the POI or AUL period. Authority notes that none of the participating companies provided information regarding loans requested under the loan appendices.
91. None of the participating companies provided supporting information or documentation to substantiate its claim that no benefit was received under this program. Thus, denial by the participating exporters of benefit received in terms of direct transfer of funds through loans from Indonesian Eximbank or any other state-owned bank cannot be accepted without supporting information regarding all loans obtained from banks in response to information requested in loan appendices. Authority provisionally determines that countervailing duty is required to be imposed against this program on all participating producers/exporters based on facts available.

**(x) Program No. 10: Exemption on Import Duty****a. Submission by Domestic Industry**

92. Indonesian Government exempts imports of material goods from import duties when they are used in manufacturing goods for export purposes. The exemption is operated with requirements and under strict surveillance. If there's deficiency between imported materials given for exemption and used in production, the exemption will not apply for the deficiency and will be penalized according to customs regulation.
93. Exemption is mainly provided to enterprises in Bonded Zones, Free Trade Zones or similar zone. The actual amount of the exemption is determined through the amount of imported materials used in manufacturing final goods for export.

**b. Submission by Government of Indonesia/other interested parties**

94. This program is set under import facility for export purposes (KITE) scheme which established on December 2003, pursuant to Minister Finance Decision No. 580/KMK.04/2003, as mandated by Act No. 10/1995 as partly amended by Act No. 17/2006 on Customs.
95. Goods processed, assembled or installed in manufacturing goods for export purposes may be exempted from import duties. Imports of fixed assets are not exempted from import duties under this program.
96. The exemption is operated with requirements and under strict surveillance. All of the end-goods resulted from the imported material should be exported, and if according to the conversion test, there's deficiency between imported materials given for exemption and used in production, the exemption will not apply for the deficiency and will be penalized according to customs regulation.
97. Regional Customs Office operated under Directorate General of Customs and Excise – Ministry of Finance administers this scheme and conducts strict surveillance. If the realization export report is agreed by the Regional Customs Office, the exemption is applied. According to Director General of Customs and Excise Regulation No. 16/BC/2012 as partly amended by Director General of Customs and Excise Regulation No. 04/BC/2014, the applicant must possess Identification Number (NIPER) for exemption purpose. In the process to obtain the NIPER, the applicant must submit letter of application to the Regional Customs Office and satisfy several requirements. All NIPER holder companies may benefit from the exemption. However, none of the companies under investigation applied for, accrued, or received benefits from this program during the POI.

**c. Examination by the Authority**

98. The government of Indonesia submitted that the above-mentioned program is set under import facility for export purposes (KITE) scheme which established on December 2003, pursuant to Minister Finance Decision No. 580/KMK.04/2003, and lastly amended by Minister Finance Regulation No. 253/PMK.04/2011 and Minister Finance Regulation No. 177/PMK.04/2013.
99. The program is not a permissible duty remission program under footnote 1 of SCM Agreement and Section 9B(1) (b) of the Customs Tariff Act. The program provides exemption to raw material used in the production of exported product. There is no sufficient evidence of verification mechanism which ensures that there is no excess benefit to enterprise. There is no evidence to show that penalty or recovery of duty was actually made from enterprises who were unable to utilize the raw material in the production of exported goods.

100. The program provides for financial contribution in the form of revenue foregone and benefit is thereby conferred. The program is also specific because it is contingent on export. However, the Authority has determined that countervailing duty should be imposed for bonded zone program and other two import duty exemption programs (other programs) granting exemption from import duties to participating companies. The Authority provisionally holds that no additional countervailing duty is required to be imposed against this program.

**(xi) Program No. 11: Import Duty Drawback**

**a. Submission by Domestic Industry**

101. Indonesian Government permits exemption from import duty payable by enterprises for goods processed, assembled or installed in manufacturing goods for export purposes. The Designated Regional Customs Office assess the amount of duty drawback proposed with the application of capital goods reports.

**b. Submission by Government of Indonesia/other interested parties**

102. This program is set under import facility for export purposes (KITE) scheme which established on December 2003, pursuant to Minister Finance Decision No. 580/KMK.04/2003, as mandated by Act No. 10/1995 as partly amended by Act No. 17/2006 on Customs. According to both Minister Finance regulations, import duty drawback scheme provides exemption from import duties payable for imports of goods processed, assembled or installed in manufacturing goods for export purposes. The applicant will receive the duty drawback after the end-goods is exported.
103. This scheme is administered by each Regional Customs Office operated under Directorate General of Customs and Excise – Ministry of Finance. The administration of this scheme was regulated on Director General of Customs and Excise Regulation No. 15/BC/2012 as partly amended by Director General of Customs and Excise Regulation No. 05/BC/2014. The designated Regional Customs Office has the authority to administer the application and issue the decision of the application. The eligibility criterion is Company Identification Number (NIPER) holder.
104. None of the companies under investigation applied for, accrued, or received benefits from this program during the POI.

**c. Examination by the Authority**

105. The Government of Indonesia submitted that the above-mentioned program is set under import facility for export purposes (KITE) scheme which was established on December 2003, pursuant to Minister Finance Decision No. 580/KMK.04/2003, and lastly amended by Minister Finance Regulation No. 253/PMK.04/2011 and Minister Finance Regulation No. 177/PMK.04/2013.
106. As per the Ministry of Finance regulation, the drawback scheme provides import duties payable for imports of goods when processed, assembled or installed in manufacturing goods for export purposes, may be partially or wholly returned, receivable at the time of export of end-goods. The present scheme is also under the supervision of the Regional Customs Officer operated under Directorate General of Customs and Excise – Ministry of Finance.
107. The eligibility criterion is Company Identification Number (NIPER) as explained in the Minister Finance Regulation No. 177/PMK.04/2013. The amount of the duty drawback is contingent to the amount of the duty paid on goods contained in the end-goods for exports. The Authority has already determined that the KITE program provides for financial contribution in the form of revenue foregone and benefit is thereby conferred. The program is also specific because it is contingent on export. The Authority has determined that countervailing duty should be imposed for bonded zone program and other two import duty exemption programs (other

programs) granting exemption from import duties to participating companies. Authority provisionally determines that no additional countervailing duty is required to be imposed against this program.

**(xii) Program No. 13: Reduction of Net Taxable Income**

**a. Submission by Domestic Industry**

108. The Petitioners submitted that Indonesian Government provides a reduction to enterprise in net taxable income of up to 30% of the amount invested in the form of fixed assets (including land), pro-rated at 5% for six years of commercial production provided that the assets invested are not misused or transferred within a certain period. It is mainly provided to enterprises located in SEZ zones.

**b. Submission by Government of Indonesia/other interested parties**

109. KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), as it is established through Act No. 39/2009 on Special Economic Zone, allows company located and operating main business in KEK to obtain wide range of facilities and incentives from taxation to employment. Currently there are 13 designated KEK across Indonesia. In its implementation, KEK is established by KEK National Council. One of main duties of KEK National Council is to determine which business sector to be main business in KEK. These areas have potentials to be developed, ranging from plantations, logistics, to tourism. As it currently stands, the SEZ is not fully operated yet.

110. The provision relating to reduction of net taxable income in KEK as stipulated in Government Regulation No. 96/2015 reduces net taxable income up to 30% of the amount invested in the form of fixed assets (including land), pro-rated at 5% for six years of commercial production. The application for the facility should be submitted to the Ministry of Finance via the Administrator of the respective KEK.

111. Apart from the KEK, Income Tax Allowance facilities, regulated under Government Regulation No. 18/2015, provide similar reduction of net taxable income. However, it is impossible for a company to obtain double-income tax facility. None of the companies under investigation applied for, accrued, or received benefits from this program, or located in KEK during the POI.

**c. Examination by the Authority**

112. Authority notes that the program is available to industries located in Special Economic Zones and provides for reduction of taxable income by 30%. The program is governed by Government Regulation No. 18/2015. The income tax exemption can be availed by the industry located in Special Economic Zone under this program only and not under any other program.

113. The subsidy program provides for financial contribution the form of revenue foregone which is otherwise due. The program is also specific because it is region specific. However, none of the participating companies applied for, accrued, or received benefits from this program during the POI. The Authority pending verification of records provisionally holds that no countervailing duty is required to be imposed against this program.

**(xiii) Program No. 14: Carry Forward of Losses**

**a. Submission by Domestic Industry**

114. Indonesian Government provides the investors with an option to carry forward their losses up to a span of 5 years which can be further extended to 5 years.

- Extension of 1 year if the capital investment is more than Rp. 200 billion;

- Extension of 1 year or 2 years if:
  - Employ not less than 500 Indonesian workers for 5 years;
  - Employ not less than 1000 Indonesian workers for 5 years;
- Extension of 1 year if the new capital investment needs investment or expense for economic and social infrastructure at SEZ at least is Rp. 10 billion;
- Extension of 2 years if spend on research and development in domestic for product development or product efficiency is at least 5% from investment for 5 years;
- Extension of 1 year if domestic raw materials were used for manufacturing end products
- Extension of 2 years if capital investment in expansion of business operation in SEZ
- Extension of 2 years if export sales comprises of at least 30% of total sales

115. It is mainly provided to business entities and business players operating in SEZ zones.

**b. Submission by Government of Indonesia/other interested parties**

116. According to the Minister of Finance Regulation No. 104/2016 on Taxation, Customs, and Excises Treatment on Special Economic Zone, the application for the facility should be submitted to the Indonesian Investment Coordination Board (BKPM) via the Administrator of the respective KEK.
117. Apart from the KEK, Income Tax Allowance facilities, regulated under Government Regulation No. 18/2015, provide similar reduction of net taxable income. However, as stipulated in the article 11 of Government Regulation No. 96/2015, the taxpayer in KEK may only apply the reduction of net taxable income facility, and any other income tax facilities, through the requirement under Government Regulation No. 96/2015. Thus, it is impossible for a company to obtain double-income tax facility. The eligibility is limited to business entities/business players operate within KEK region. None of the companies under investigation applied for, accrued, or received benefits from this program, or located in KEK during the POI.

**c. Examination by the Authority**

118. Program provides for carry forward of losses to business enterprise. The subsidy program provides for financial contribution in the form of revenue foregone which is otherwise due. The program is also specific because it is specific to enterprise located in KEK. However, none of the participating companies are claimed to have applied for, accrued, or received benefits from this program during the POI. The Authority pending verification provisionally holds that no countervailing duty is required to be imposed against this program.

**(xiv) Program No. 15: Postponement of Import Duty**

**a. Submission by Domestic Industry**

119. The Petitioners submitted that Indonesian Government postpones the import duty payment on capital goods and equipment, goods and materials for processing. It is mainly provided to business entities and business players operating in SEZ zones.

**b. Submission by Government of Indonesia/other interested parties**

120. KEK is established by KEK National Council. One of main duties of KEK National Council is to determine which business sectors are to be the main business in KEK. These areas have potentials to be developed, ranging from plantations, logistics, to tourism.
121. KEK National Council forms Region Council to perform implementation including establishment of administrator in each KEK. Region Council also reports to the KEK National Council of its management performance in each KEK.
122. The postponement of payment of import duty in KEK as stipulated in Government Regulation No. 96/2015 is operated through withholding system. The application for the facility should be submitted to the Ministry of Finance via the Administrator of the respective KEK. The application process of the program is in line with the general regulation on importation. The company notifies the Customs of its importation and submits standard customs form. None of the companies under investigation applied for, accrued, or received benefits from this program, or located in KEK during the POI.

**c. Examination by the Authority**

123. Authority notes that the program provides for postponement of import duty for enterprise. Thus, the program provides for deferral of taxes owed. Benefit conferred on the enterprise is in the form of interest free short term or long-term loan. Amount of benefit is equivalent to the amount of interest charged by bank on commercial loan.
124. The program provides for financial contribution in the form of revenue foregone. Program is also specific because it provides benefit to certain enterprise located in Special Economic Zone. However, the Authority has determined that countervailing duty should be imposed for bonded zone program and other two import duty exemption programs (other programs) granting exemption from import duties to participating companies. The Authority, therefore, provisionally determines that no additional countervailing duty is required to be imposed against this program.

**(xv) Program No. 16: Exemption of Duty on Raw Material and Supporting Goods for Production Purpose****a. Submission by Domestic Industry**

125. Indonesian Government exempts the duty on raw material and supporting goods for investors who are expanding their production in SEZ.
126. This tax benefit is available to two set of categories:
  - Taxpayers organizing a SEZ's business activity-
    - Registered by relevant government agency to be a business entity that develops or manages a SEZ.
    - Have agreements on the SEZ with the government agency
    - Create relevant boundaries of SEZ's activities
  - Taxpayers carrying out business in SEZ:
    - Have a legalized new capital investment plan for the administrator of SEZ
    - Have an information system connected to Director General of Customs and Excise

**b. Submission by Government of Indonesia/other interested parties**

127. The exemption of duty on raw material and supporting goods for production in KEK as stipulated in article 19 Government Regulation No. 96/2015 is given to the Business entities and Business Players for the development and expansion of industry for certain period.
128. As stipulated in Article 40 and 41 of Minister of Finance Regulation No. 104/2016, import of capital goods by Business Entities is exempted from import duty for 3 years, while Business Players may get import duty exemption for capital goods and/or materials for 2 years. As further stated, the type and amount of goods subject to exemption is determined by the KEK administrator, and the imported goods may only be used within the KEK region.
129. The program is administered by Directorate General of Customs and Excise via the Administrator of the respective KEK. None of the companies under investigation applied for, accrued, or received benefits from this program, or located in KEK during the POI.

**a. Examination by the Authority**

130. The program provides for financial contribution in the form of revenue foregone. Program is also specific because it provides benefit to certain enterprise located in KEK region. However, the Authority has determined that countervailing duty should be imposed for bonded zone program and other two import duty exemption programs (other programs) granting exemption from import duties to participating companies. The Authority, therefore, provisionally determines that no additional countervailing duty is required to be imposed against this program.

**(xvi) Program No. 17: Exemption from Income Tax on imports**

**a. Submission by Domestic Industry**

131. Indonesian Government grants exemption of Income Tax on importation of certain goods if the company is located in SEZ.
132. This tax benefit is available to two set of categories:
  - Taxpayers organizing a SEZ's business activity
    - Registered by relevant government agency to be a business entity that develops or manages a SEZ.
    - Have an agreement on the SEZ with the government agency
    - Create relevant boundaries of SEZ's activities.
  - Taxpayers carrying out business in SEZ:
    - Have a legalised new capital investment plan for the administrator of SEZ
    - Have an information system connected to Director General of Customs and Excise.

**b. Submission by Government of Indonesia/other interested parties**

133. Exemption of income tax on imports in KEK as stipulated in Government Regulation No. 96/2015 is applied for goods designated to business players in the KEK from Outside of Customs Area; Other Business Players within the KEK; Other Business Players in other KEK; Bonded Zones outside of the KEK; Free Trade Zone and Free Port; and/or Other Region TLDPP. The application for the facility should be submitted to the Ministry of Finance via the Administrator of the respective KEK. None of the companies under investigation applied for, accrued, or received benefits from this program, or located in KEK during the POI.

**c. Examination by the Authority**

134. Authority notes that the exemption of duty on raw material and supporting goods for production in KEK as stipulated in article 19 Government Regulation No. 96/2015 is given to the Business entities and Business Players for the development and expansion of industry for certain period.
135. The exemption under this program results in deferment of income tax payment as income tax paid on import is an instalment of annual income tax payment. The program provides for financial contribution in the form of direct transfer of funds. Benefit is equal to the interest paid on the loan obtained for such deferred amount from commercial bank. Program is also specific because it provides benefit to certain enterprise located in KEK region. However, none of the participating companies are claimed to have applied for, accrued, or received benefits from this program during the POI. The Authority, therefore, pending further investigation holds provisionally that no additional countervailing duty is required to be imposed against this program.

**(xvii) Program No. 18: Reduction for Investors investing in SEZ**

**a. Submission by Domestic Industry**

136. The Petitioners submitted that Indonesian Government provides reduction in income tax for investors investing in SEZ- Up to 20-100 % for at least 10 years to a maximum of 25 years and Up to 20-100% for at least 5 years to a maximum of 15 years. Customs, and Excise Treatment on Special Economic Zone provides that taxpayer should be:
- New Taxpayer;
  - Operating new capital investment or expansion of new capital investment;
  - Its business field is in line with the main business in SEZ;
  - Fulfilled DER requirement;
  - It has submitted letter of intent to deposit fund in Banking institutions in Indonesia with minimum deposit 10% from investment value;
  - Holds Legal entities status since 15 August 2011

**b. Submission by Government of Indonesia/other interested parties**

137. Reduction in Income Tax for Investors investing or Tax Holiday in KEK as stipulated in Government Regulation No. 96/2015 is categorized as follows:
- a) Investment >Rp. 1 trillion, reduction in income tax ranging from 20 – 100% for 10 – 25 years;
  - b) Investment Rp. 500 billion - Rp.1 trillion, reduction in income tax ranging from 20 – 100% for 5 – 15 years;
  - c) Investment <Rp. 500 billion, reduction in income tax ranging from 20 – 100% for 5 – 15 years;
138. The amount of Income Tax reduction for each year of the period given remains the same. The facility itself is given upon income specifically received from main business operation in KEK. However, income received from business activities other than its main operation is still subject for taxation. The application for the facility should be submitted to the Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM) via the Administrator of the respective KEK.
139. According to article 7 of Government Regulation No. 96/2015, Ministry of Finance determines the period and the amount of income tax reduction based on the proposal from taxpayer. For



determining the amount of the reduction, the Ministry of Finance forms verification committee.

140. The eligibility is limited to business entities/business players operating within KEK region. None of the companies under investigation applied for, accrued, or received benefits from this program, or located in KEK during the POI.

**c. Examination by the Authority**

141. Authority notes that the program provides exemption from income tax. The Authority has already determined that the subsidy program granting reduction or exemption from income tax provides for financial contribution the form of revenue foregone which is otherwise due. The subsidy program is also specific because it applies to certain enterprises incurring investment as per Government Regulation.
142. However, none of the participating companies are claimed to have applied for, accrued, or received benefits from this program during the POI. Pending verification, the Authority provisionally holds that no countervailing duty is required to be imposed against this program.

**(xviii) Program No. 19: Pioneer Industry Status**

**a. Submission by Domestic Industry**

143. Indonesian Government launched Pioneer Industry Tax Benefits Program. The program, as it stood in the POI and as it currently stands, provides an income tax reduction in the range of 10 percent to 100 percent over five to fifteen years for certain corporate taxpayers. The tax reduction starts from the first year of the corporation's commercial production time. The corporation receiving the tax reduction has to be a "pioneer industry" defined as an industry "with extensive interconnection that provides added value and high externality, introduces new technology, and has strategic value for the national economy." In addition, considering the total investment value, the corporation has to invest at least IDR 1,000,000,000,000.00 (one trillion rupiah) for all sectors of pioneer industries excluding the information, communication and technology (ICT) sector that introduces high technology. The corporations in the ICT sector could invest minimum IDR 500,000,000,000.00 (five hundred billion rupiah) to be eligible for the benefit. In addition, the corporation must fulfil other requirements for the tax reduction, namely depositing a minimum of 10 percent of the investment plan in Indonesian banks, maintaining a debt to equity ratio at least 4:1, and having the status of Indonesian legal entity since August 15, 2011.
144. Under this program, benefits available to enterprises include simplified environmental reporting requirements and licensing requirements, fiscal incentives such as tax holidays and tax allowances at both the national and regional levels, reductions, allowances or exemptions of regional taxes or levies.

**b. Submission by Government of Indonesia/other interested parties**

145. Pioneer Industry status is defined as industry "*with extensive interconnection that provides added value and high externality, introduces new technology, and has strategic value for the national economy*". The status however is only eligible for the Tax Holiday program and not for the Tax Allowance facility as alleged by the petitioner instead.
146. Pioneer industry covers 18 sectors. However, the list is not exhaustive. The program opens the opportunity for other sectors other than currently stipulated in the program upon the approval of the Minister of Finance. Thus, the program is not limited to certain sectors or region in nature. Nonetheless, none of the alleged exporters applied or benefitted from this program.

**c. Examination by the Authority**

147. Authority notes that the program provides exemption from income tax. The Authority has already determined that the subsidy program granting reduction or exemption from income tax provides for financial contribution the form of revenue foregone which is otherwise due. The subsidy program is also specific because it applies to certain enterprises having pioneer industry status.
148. However, none of the participating companies are claimed to have applied for, accrued, or received benefits from this program during the POI. Pending verification, the Authority provisionally holds that no countervailing duty is required to be imposed against this program.

**(xix) Program No. 21: Deduction in Land Tax**

**a. Submission by Domestic Industry**

149. The Petitioners submitted that Indonesian Government provides benefit of land tax to the enterprises located in SEZ region.
150. This tax benefit is available to two set of categories:
- Enterprises which are located in SEZ:
    - Registered by relevant government agency to be a business entity that develops or manages a SEZ
    - Have an agreement on the SEZ with the government agency
    - Create relevant boundaries of SEZ's activities
  - Taxpayers carrying out business in SEZ:
    - Have a legalized new capital investment plan for the administrator of SEZ
    - Have an information system connected to Director General of Customs and Excise

**b. Submission by Government of Indonesia/other interested parties**

151. Land and Building Tax (PBB) in Indonesia tax system is part of the regional/city tax or retribution, and it is determined by the regional government through head of regional/mayor regulation. In Act No. 39/2009, reduction of PBB is provided in line with regulation. However, in Government Regulation No. 96/2015, PBB is provided under facilities in KEK for Tourism which provides that regional government may determine reduction or exemption of regional tax ranging from 50% and 100%.
152. As it stands, only KEK with main business in Tourism such as KEK Tanjung Kelayang, KEK Mandalika, KEK Tanjung Lesung, KEK Morotai, KEK Sorong applied reduction in regional/city tax. PBB is provided under facilities in KEK for Tourism which provides that regional government may determine reduction or exemption of regional tax ranging from 50% and 100%. None of the companies under this investigation used this program.

**c. Examination by the Authority**

153. The program provides reduction in land tax application to enterprise if the enterprise is located in Special Economic Zone. However, the benefit of reduction is available to enterprise carrying out tourism related business activity. Therefore, Authority holds that no countervailing duty is required to be imposed under this program.

**(xx) Program No. 23: Refund of VAT****a. Submission by Domestic Industry**

154. Indonesian Government provides refund of VAT in certain cases. The delivery of goods and services in Indonesia is generally subject to VAT, except for the delivery of certain pre-determined types of goods and services. The current VAT rate is 10%. The prevailing VAT Law stipulates that supplies of gold bars, coal, and natural resources that have been taken directly from their source are not subject to VAT. This VAT position may change, according to the level of processing of the mining product in question. During pre-production, only Input VAT that has been incurred on purchases of capital goods is creditable. Furthermore, since the company will not have any Output VAT during the pre- production period, a VAT overpayment is likely. For most companies, a VAT refund is only available at the end of the year. However, companies that incur VAT during pre-production may apply for refunds in respect of VAT on capital goods on a monthly basis. But, if they fail to commence production (defined as the delivery of VAT-able goods/services) within three years (potentially extended to five years in some circumstances) from the date on which they credit the Input VAT, they must repay the VAT refund by the end of the month following the failure to enter into production. The prevailing VAT Law stipulates that supplies of gold bars, coal, and natural resources that have been taken directly from their source are not subject to VAT.

**b. Submission by Government of Indonesia/other interested parties**

155. Value Added Tax (VAT) is a tax imposed on any value added of goods or services in circulation from producer to consumer.
156. Indonesia has a single tariff system for VAT, which is 10%. The main legal basis used for the application of VAT in Indonesia is Law No. 8 of 1983 lastly amended with Law No. 42 of 2009.
157. VAT rate of 0 percent is applied on export of tangible goods, export of intangible goods and export of services. VAT is an indirect tax. In the application of VAT levies, tax payers will credit input tax and output tax within the same fiscal period. If in the fiscal period the output tax is greater, then the excess tax output must be deposited in the state treasury.
158. Conversely, if in the tax period, the input tax period is greater than the output tax, the excess input tax can be compensated to the next tax period. In this procedure, the amount to be paid by the tax payers may change according to the input tax paid. Basically, all goods and services are taxable goods and taxable services, so they are subject to Value Added Tax (VAT), except for the types of goods and types of services as stipulated in Article 4A of Law No. 42 of 2009 concerning the Third Amendment of Law Number 8 of 1983 on the Value Added Tax of Goods and Services.
159. Article 4A of the Law No. 42 of 2009 stipulates that type of goods that are not subject to the Value Added Tax shall be certain goods within the group of goods are: 1) mining and drilling products of which are taken directly from their sources; 2) staple goods of which are mostly required by the people; 3) food and beverage of which are served in the hotel, restaurant, food shop, shop, or the similar is desired, including dine in and take out food, including food and beverage of which are presented by catering company; and 4) money, gold bullion, and securities.

160. The VAT refund is not contingent upon export performance or on the use of domestic goods. The provision is applied to all taxpayers. The legal basis of VAT return is in Article 6 of Minister of Finance Regulation Number 72 of 2010. None of the companies under investigation applied for, accrued, or received benefits from this program.

**c. Examination by the Authority**

161. Authority notes that all products are subject to VAT in Indonesia. However, mining and drilling products, which are taken directly from their sources are not subject of VAT.
162. Additionally, VAT refund is granted under this program. If in the fiscal period, the output tax is greater than input tax, excess tax output must be deposited in the state treasury. If in the tax period, the input tax period is greater than the output tax, the excess input tax can be compensated to the next tax period.
163. Authority notes that fixing differential VAT rate does not amount to financial contribution to enterprises procuring such product. Moreover, refund of excess VAT paid also does not amount to financial contribution as it does not result in foregoing of revenue that is otherwise due.

**(xxi) Other Program 1: Bonded Zone**

**a. Submission by Domestic Industry**

164. The domestic industry has not alleged existence of this program in the petition.

**b. Submission by Government of Indonesia/Other interested parties**

165. A “Bonded Zone” is defined as a bonded storage location which is utilized to store imported goods and/ or goods from other location in customs territory in order to be processed or assembled. However, as stipulated in Minister of Finance Regulation No. 147/PMK.04/2013 Bonded Zone is categorized as part of the Customs territory and operated under full surveillance of Directorate General of Customs and Excise. As it is part of Indonesia Customs territory which is neutral, goods entering Bonded Zone are not yet considered as a fully imported goods. By this understanding, Customs cannot collect import duty, income tax, value added tax (VAT), luxury tax, and excise.
166. VAT import exemption on raw materials or capital goods is SCM consistent. The exemption of income tax for import materials and capital goods does not also confer benefit as income tax for import is instalment for annual payable income tax. The suspension of import duty for capital goods and import of material does not also have material benefit since material imported is subject to preferential import tariff from 0% with maximum 5% rate.

**c. Examination by the Authority**

167. Authority notes that import duty exemption is granted to imports into bonded zone. Participating companies PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel, PT Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry, PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy, PT Tsingshan Steel Indonesia (TSI), PT Sulawesi Mining Investment are located in the Bonded Zone and provided information regarding the exemption of duty on capital goods imported into bonded zone.
168. Authority notes that exemption from import duty for goods imported into bonded zone amounts to financial contribution in the form of revenue foregone that is otherwise due. Amount of benefit

is equal to the difference between the import duty on import and the income tax and import duty paid on imports. The Authority provisionally determines that countervailing duty should be imposed against this program.

**(xxii) Other program 2: Exemption of Import Income Tax under Article 22**

**a. Submission by Domestic Industry**

169. The domestic industry has not alleged existence of this program in the petition.

**b. Submission by Government of Indonesia/Other interested parties**

170. Under the Director General of Tax Regulation No. 1/PJ/2011, the GOI provides an exemption on final income tax and import income tax to tax payers who (1) face fiscal loss due to certain causes such as a) new tax payer is in investment phase; b) the tax payer is not in the commercial operation; or c) Force Majeure; (2) eligible for fiscal loss compensation and 3) the amount of paid income tax is greater than the payable income tax

171. The tax payers who meet the above criteria may request for the exemption through written application to local tax office along with supporting documents such as the previous year tax notification letter. If granted, the exemption would apply for the final income tax at 10% or income import tax at 2.5% rate and for the given tax year. The exemption of import income tax at 2.5% rate does not confer benefit as it is instalment for annual payable income tax.

**Examination by Authority**

172. Authority notes that under this program, enterprise which is (1) facing fiscal loss due to certain causes such as new tax payer in investment phase, not in the commercial operation, Force Majeure or (2) is eligible for fiscal loss compensation or 3) Wherein the amount of paid income tax by enterprise is greater than the payable income tax, may apply for the facility. If granted, the exemption would apply for the final income tax at 10% or income import tax at 2.5% rate and for the given tax year.

173. PT IMR ARC received exemption at \*\*\*% rate. The exemption under this program results in deferment of income tax payment as income tax paid on import is an instalment of annual income tax payment. The program provides for financial contribution in the form of direct transfer of funds. Benefit is equal to the interest paid on the loan obtained for such deferred amount from commercial bank. . The Authority preliminary determines that countervailing duty should be imposed against this program.

**(xxiii) Other Program 3: Investment Facility for Imports of Machinery and Capital Goods**

**a. Submission by Domestic Industry**

174. The domestic industry has not alleged existence of this program in the petition.

**b. Submission by Government of Indonesia/Other interested parties**

175. Government Regulation No. 81 of 2015 (GR 81/2015) provides for imports of strategic goods, which among others include machineries and factory equipment to be installed and used for production by newly established industry and/or expansion of industry, which may obtain import facility in form of exemption of import duty and VAT exemption.

176. For the import duty exemption, the proposed items and value of the imported goods shall first be proposed to and approved by the supervising agencies, namely the BKPM, whereas for the VAT exemption importing companies may propose and seek approval from the local tax office under the Directorate General of Taxation.

177. Machineries and equipment imported shall only be used by the importing industries (non-transferrable) and for the intended purpose as stated in the application only.

**c. Examination by Authority**

178. Authority notes that under this program import of goods are exempted from customs duty and VAT for new units and for units creating expansion. Normal VAT rate in Indonesia is 10%. PT IMR ARC has received VAT exemption under this program. If VAT is payable, tax payers will credit input tax against output tax payment.
179. PT IMR ARC received exemption on its import of capital goods under this program. The exemption of customs duty on import of capital goods results in financial contribution in the form of foregoing of revenue that is otherwise due. The amount of benefit is equal to the amount of customs duty paid on import of capital goods and the amount of customs duty payable in absence of exemption under this program. Exemption from VAT on import of capital goods does not provide financial contribution as it does not result in revenue foregone that is otherwise due. The Authority provisionally determines that countervailing duty should be imposed against this program for customs duty exemption on import of capital goods.

**Producers/exporters from Indonesia**

**PT Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry (GCNS)**

180. PT Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry (GCNS) is the producer/exporter of subject product in Indonesia. PT GCNS has filed questionnaire response and has provided information regarding the subsidy received by it. Related raw material suppliers in Indonesia \*\*\* and \*\*\* have also filed questionnaire response. PT GCNS has exported the subject product to India through related traders namely \*\*\*, \*\*\* and through \*\*\*. All the three related exporters have filed questionnaire responses.
181. PT GCNS is related to other producer/exporters \*\*\*, and \*\*\* in Indonesia, who have also filed separate questionnaire responses.
182. Authority has examined the response filed by, PT GCNS, its related raw material suppliers and its related exporters. Upon examination of these response, the Authority notes that the related exporters are also purchasing subject goods from other suppliers in Indonesia for exporting to India. However, the information provided by the related exporters regarding transaction by transaction exports to India does not disclose the name of the producer in Indonesia. Based on the examination of the questionnaire responses, the Authority also notes that in a given export transaction to India, more than one related trader is involved before goods are finally exported to customer in India but no clear export value chain is prescribed or identifiable based on the information provided in the questionnaire response. The Authority is unable to determine specific export price for PT GCNS based on the information provided in its questionnaire response. The questionnaire response by related exporters have also not provided information in accordance with the PCN proposed by the Authority in this investigation. Thus, the Authority notes that the information provided by PT GCNS and its related exporters is not complete and is deficient on many aspects. However, upon examination of transaction by transaction exports to India provided by PT GCNS, the Authority notes that PT GCNS has exported only one type of grade to India. Authority has accordingly determined export price and landed value for exports to India based on final export price to India by related exporters and has not rejected the information provided in the questionnaire response of PT GCNS and its related exporters entirely .
183. Authority has determined subsidy margin for programs, for which information was provided in the questionnaire response of GCNS and its related raw material suppliers in Indonesia, equal to the benefit received or accrued during the POI. It is noted that PT GCNS and its related raw

material suppliers availed benefit under other program concerning exemption from import duty in Bonded Zone. Authority determines that the subsidy programs resulted in the provision of financial contribution in the form of revenue foregone which was otherwise due. As a result, benefit was conferred to PT GCNS as a recipient of this benefit. Subsidy program was also specific because they were limited to certain enterprise including PT GCNS located in Bonded Zone.

184. Authority has also relied on facts available to determine the subsidy margin for provision of raw materials Coal and Nickel ore for less than adequate remuneration by relying on information available publicly. Authority has also relied on facts available to determine subsidy margin for program concerning export financing by Indonesia Eximbank.

185. The table below provides name of the subsidy programs and the corresponding subsidy margin.

Program Nos.	Name of the Program	Brief Description	Subsidy Margin %	Subsidy Margin Range
Other Program	Bonded Zone	Exemption from customs duty and income tax on import of capital goods	***	0-5%
Program Nos. 1, 2 & 4	Minimum value addition for export and domestic market obligation requirement	Provision of minerals at less than adequate remuneration	***	15-20%
Program No. 9	Export Financing from Indonesia Exim Bank	Direct transfer of funds in form of loans from state owned banks/public bodies	***	5-10%
<b>Total</b>			***	<b>20-30%</b>

### **PT. Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS)**

186. PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel is the producer/exporter of subject product in Indonesia. PT ITSS has filed questionnaire response and has provided information regarding the subsidy received by it. Related raw material suppliers in Indonesia \*\*\* and \*\*\* have also filed questionnaire response. PT ITSS has exported the subject product to India through related traders namely \*\*\*, \*\*\*, \*\*\* and through \*\*\*. All the four related exporters have filed questionnaire responses.

187. PT ITSS is related to other producer/exporters \*\*\* and \*\*\* in Indonesia, who have also filed separate questionnaire responses.

188. Authority examines the response filed by, PT ITSS, its related raw material suppliers and its related exporters. Upon examination of these response, the Authority notes that the related exporters are also purchasing subject goods from other suppliers in Indonesia for exporting to India. However, the information provided by the related exporters regarding transaction by transaction exports to India does not disclose the name of the producer in Indonesia. Based on the

examination of the questionnaire responses, the Authority also notes that in a given export transaction to India, more than one related trader is involved before goods are finally exported to customer in India but no clear export value chain is prescribed or is identifiable based on the information provided in the questionnaire response. The Authority is unable to determine specific export price for PT ITSS based on information provided in the questionnaire response. The questionnaire response by PT ITSS and its related exporters have also not provided information in accordance with the PCN proposed by the Authority in this investigation. However, upon examination of transaction by transaction exports to India provided by PT ITSS, the Authority notes that PT ITSS has exported only two types of grade to India. Authority has accordingly determined export price and landed value for exports to India based on final export price to India by related exporters and has not rejected the information provided in the questionnaire response of PT ITSS and its related exporters entirely.

189. Authority has determined subsidy margin for programs, for which information was provided in the questionnaire response of PT ITSS and its related raw material suppliers in Indonesia, equal to the benefit received or accrued during the POI. It is noted that PT ITSS and its related raw material suppliers availed benefit under other program concerning exemption from import duty in Bonded Zone. Authority determines that the subsidy programs resulted in the provision of financial contribution in the form of revenue foregone which was otherwise due. As a result, benefit was conferred to PT ITSS as a recipient of this benefit. Subsidy program was also specific because they were limited to certain enterprise including PT ITSS located in Bonded Zone.
190. Authority has also relied on facts available to determine the subsidy margin for provision of raw materials Coal and Nickel ore for less than adequate remuneration by relying on information available publicly. Authority has also relied on facts available to determine subsidy margin for program concerning export financing by Indonesia Eximbank.
191. The table below provides name of the subsidy programs and the corresponding subsidy margin.

Program No.	Name of the Program	Brief Description	Subsidy Margin %	Subsidy Margin Range
Other Program	Bonded Zone	Exemption from customs duty and income tax on import of capital goods	***	0-2%
Program Nos. 1, 2 & 4	Minimum value addition for export and domestic market obligation requirement	Provision of minerals at less than adequate remuneration	***	15-25%
Program No. 9	Export Financing from Indonesia Exim Bank	Direct transfer of funds in form of loans from state owned banks/public bodies	***	5-10%
<b>Total</b>			***	<b>20-30%</b>



**PT. Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy (IRNC)**

192. PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy (IRNC) is the producer/exporter of subject product in Indonesia. PT IRNC has filed questionnaire response and has provided information regarding the subsidy received by it. Related raw material suppliers in Indonesia \*\*\* and \*\*\* have also filed questionnaire response. PT IRNC has exported the subject product to India through related traders namely \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, \*\*\* and through \*\*\*. All the related exporters have filed questionnaire responses.
193. PT. IRNC is related to other producer/exporters \*\*\*, \*\*\* in Indonesia, who have also filed separate questionnaire responses.
194. Authority examines the response filed by, PT IRNC, its related raw material suppliers and its related exporters. Upon examination of these response, the Authority notes that the related exporters are also purchasing subject goods from other suppliers in Indonesia for exporting to India. However, the information provided by the related exporters regarding transaction by transaction exports to India does not disclose the name of the producer in Indonesia. Based on the examination of the questionnaire responses, the Authority also notes that in a given export transaction to India, more than one related trader is involved before goods are finally exported to customer in India but no clear export value chain is prescribed or is identifiable based on the information provided in the questionnaire response. The Authority is unable to determine specific export price for PT IRNC based on information provided in the questionnaire response. The questionnaire response by PT IRNC and its related exporters have also not provided information in accordance with the PCN proposed by the Authority in this investigation. However, upon examination of transaction by transaction exports to India provided by PT IRNC, the Authority notes that PT IRNC has exported only one type of grade to India. Authority has accordingly determined export price and landed value for exports to India based on final export price to India by related exporters and has not rejected the information provided in the questionnaire response of PT IRNC and its related exporters entirely.
195. Authority has determined subsidy margin for programs, for which information was provided in the questionnaire response of PT IRNC and its related raw material suppliers in Indonesia, equal to the benefit received or accrued during the POI. It is noted that PT IRNC and its related raw material suppliers availed benefit under other program concerning exemption from import duty in Bonded Zone. Authority determines that the subsidy programs resulted in the provision of financial contribution in the form of revenue foregone which was otherwise due. As a result, benefit was conferred to PT IRNC as a recipient of this benefit. Subsidy program was also specific because they were limited to certain enterprise including PT IRNC located in Bonded Zone.
196. Authority has also relied on facts available to determine the subsidy margin for provision of raw materials Coal and Nickel ore for less than adequate remuneration by relying on information available publicly. Authority has also relied on facts available to determine subsidy margin for program concerning export financing by Indonesia Eximbank.
197. The table below provides name of the subsidy programs and the corresponding subsidy margin.

Program No.	Name of the Program	Brief Description	Subsidy Margin %	Subsidy Margin Range
Other Program	Bonded Zone	Exemption from customs duty and income tax on import of	***	0-5%

		capital goods		
Program Nos. 1, 2 & 4	Minimum value addition for export and domestic market obligation requirement	Provision of minerals at less than adequate remuneration	***	15-25%
Program No. 9	Export Financing from Indonesia Exim Bank	Direct transfer of funds in form of loans from state owned banks/public bodies	***	5-10%
<b>Total</b>			***	<b>20-30%</b>

### **PT IMR ARC Steel, Indonesia**

198. PT IMR ARC Steel, Indonesia is the producer/exporter of subject goods in Indonesia. PT IMR ARC has filed questionnaire response and has provided information regarding the subsidies received by it. \*\*\* is the related importer of PT IMR ARC in India. PT IMR ARC has exported subject goods to India directly and through related exporter \*\*\* to related and unrelated importer in India.
199. Authority has determined subsidy margin for programs, for which information was provided in the questionnaire response of PT IMR ARC equal to the benefit received or accrued during the POI. It is noted that PT IMR ARC and its related raw material suppliers availed benefit under other program concerning exemption from import duties. Authority determines that the subsidy programs resulted in the provision of financial contribution in the form of revenue foregone which was otherwise due. As a result, benefit was conferred to PT IMR ARC as a recipient of this benefit. Subsidy program was also specific because they were limited to certain enterprise including PT IMR ARC who fulfilled the eligibility criteria under the program.
200. Authority has also relied on facts available to determine the subsidy margin for provision of raw materials Coal and Nickel ore for less than adequate remuneration by relying on information available publicly. Authority has also relied on facts available to determine subsidy margin for program concerning export financing by Indonesia Eximbank.
201. The table below provides name of the subsidy programs and the corresponding subsidy margin.

<b>Program No.</b>	<b>Name of the Program</b>	<b>Brief Description</b>	<b>Subsidy Margin %</b>	<b>Subsidy Margin Range</b>
Other Program	Facility Service Capital Investment (Master List Scheme)	Exemption from customs duty on machines	***	0-5%
Other Program	Exemption from Income Tax on Machines	Exemption from Income Tax on import of	***	0-5%

		capital goods		
Other Program	Exemption from Income Tax on Raw Materials	Exemption from income tax on import of raw materials	***	0-5%
Program Nos. 1, 2 & 4	Minimum value addition for export and domestic market obligation requirement	Provision of minerals at less than adequate remuneration	***	15-25%
Program No. 9	Export Financing from Indonesia Exim Bank	Direct transfer of funds in form of loans from state owned banks/public bodies	***	5-10%
Total			***	20-30%

### **PT Bintang Asia Usaha (BAU), Indonesia**

202. PT Bintang Asia Usaha (BAU) is the producer/exporter of subject product in Indonesia. PT BAU has filed exporter questionnaire response. PT BAU has claimed that product exported by PT BAU is not covered within the scope of PUC. Authority has examined the response of PT BAU. Authority notes that product exported by PT BAU to India is “Stainless Steel Circles” and is covered within the scope of product under consideration. Authority further notes that PT BAU has not provided complete transaction by transaction information regarding exports made to India during the POI. Thus, the Authority has relied on facts available to determine the export price of PT BAU in this preliminary determination.
203. Authority has examined the questionnaire response filed by PT BAU. PT BAU has not provided complete information regarding the programs identified in the notice of initiation and regarding the programs under which benefit is received by PT BAU. Thus, Authority rejects the questionnaire response filed by PT BAU and determines PT BAU as non-cooperating producer/exporter from Indonesia in this preliminary determination. Accordingly, the Authority has relied on facts available to determine the subsidy margin for PT BAU.

### **Summary of Subsidy Programs for Indonesia**

204. There are three groups of participating producers/exporters from Indonesia. The first group comprises of three related producers in Indonesia namely \*\*\*, \*\*\* and \*\*\* and their related raw material suppliers and related traders/exporters. The second group comprises of producer PT IMR ARC, its related exporter \*\*\* and its related importer in India \*\*\*. The third group comprises of producer/exporter PT BAU, Indonesia. Authority has determined subsidy margin for first two groups based on information provided in their questionnaire responses.
205. Countervailing duty for all other producers/exporters from Indonesia has been determined based on the highest of the subsidy margins for the cooperating parties.

Program No.	Name of the Program	Brief Description	Subsidy Margin %	Subsidy Margin Range
Other Program	Bonded Zone	Exemption from customs duty and income tax on import of capital goods	***	0-5
Other Program	Exemption from Income Tax on Raw Materials	<b>Exemption from income tax on import of raw materials</b>	***	0-5
Program Nos. 1, 2 & 4	Minimum value addition for export and domestic market obligation requirement	Provision of minerals at less than adequate remuneration	***	15-25%
Program No. 9	Export Financing from Indonesia Exim Bank	Direct transfer of funds in form of loans from state owned banks/public bodies	***	5-10%
<b>Total</b>			***	<b>20-30%</b>

## **G. INJURY ASSESSMENT AND CAUSAL LINK**

### **G.1. Submissions by Domestic Industry**

206. The following submissions have been made by the Domestic Industry with regard to injury issues:

- a) Demand or apparent consumption of the product concerned in India is defined as the sum of domestic sales of Indian producers and imports from all other countries. Production/sales of those producers whose input and output both are within the scope of product under consideration in the present petition is required to be ignored. There has been increase in demand throughout the injury period
- c) There is significant increase in imports from the subject country throughout the injury period. Imports were only 93 MT in the base year and the same have increased to 76,102 MT in the POI. Thus, imports have increased by more than 700 times over the injury period
- d) Market share in imports from subject country was almost NIL in the base year and the same increased to 17% of total imports in the POI. Imports have not only increased in absolute terms but have also increased in relation to production, consumption, sale and total imports in the same proportion.
- e) Subject imports constituted only \*\*\* % of production in the base year which has increased to \*\*\* % in the POI.

- f) Similarly, subject imports did not constitute any percentage of consumption of the domestic industry and it was merely \*\*\* % in 2016-17 which increased to \*\*\* % in the POI. Subject imports were only \*\*\* % of sales of domestic industry in the base year, which has now increased to \*\*\*%.
- g) Price undercutting should be determined considering only those import transactions whose landed price of imports is below selling price of the domestic industry. Petitioner's concern is against injurious imports.
- h) Authority should consider only those transactions that are below non-injurious price for calculation of injury margin
- i) The cost of production has increased over the current injury period in view of significant increase in input prices. Prices of these major inputs such as scrap, nickel, Ferro alloys have increased over the injury period thus resulting in increase in direct costs over the injury period. In particular, between POI and preceding year, there have been significant increase in prices of inputs and resultantly in the material costs. However, the selling prices have not increased in proportion to the increase in raw material cost
- j) The capacity with the domestic industry has remained the same over the injury period. The domestic industry along with the other producers in India have sufficient capacity to cater to the domestic demand. Thus, imports to this extent are not necessary.
- k) The production and sales of the domestic industry has increased throughout the injury period. Subsidized imports from Indonesia has prevented the domestic industry from increasing its domestic sales to the extent of production, thereby forcing the domestic industry to continue to resort to exports.
- l) Domestic industry is not able to utilise its capacity to the fullest. The domestic industry is exporting the product at significant financial losses in spite of adequate demand in the domestic market. The only reason for the domestic industry to export the product is subsidised imports accounting for significant share of the market demand and resultantly taking away market share from the domestic industry
- m) The domestic industry was forced to reduce prices in view of the significant price undercutting being faced.
- n) The profits of the domestic industry increased in 2017-18. However, it declined significantly in the POI. The cash profits and return on investments have followed the same trend as that of profits. Cash profits and return on investments have declined significantly in the POI.
- o) The market for the product was predominantly dictated by the Chinese prices up to the imposition of CVD. The domestic industry suffered significant price injury as a result of subsidized Chinese imports. The industry had hoped to improve its prices and profitability with the imposition of CVD. This did happen to some extent in 2017-18. However, this remained short lived in view of imports of subsidized goods from Indonesia.
- p) Petitioners have lost revenue and consequently profits by undertaking exports instead of selling in the domestic market.
- q) Employment level have remained in the similar region, while wages paid have increased. Petitioners have not claimed any injury on this account.
- r) The growth of the domestic industry in respect of volume parameters has remained adverse. The domestic industry expected to gain the market share vacated by China pursuant to imposition of CVD duties. However, subsidized imports from the subject country has led to

the adverse impact on the production, sales and utilization of the domestic industry. Further, growth in terms of the price parameters has been negative in the POI.

- s) Imports from countries other than the subject country are either negligible or are already attracting Anti-dumping duty/ countervailing duty or are being examined under antidumping investigation.
- t) There is no decline in demand of the product over the injury period. Decline in demand is not a possible cause of injury to the domestic industry.
- u) Performance of other products being produced and sold by the Domestic Industry has no impact over reported performance of the product. Availability of subsidized imports in the market is the sole reason for the present injury being suffered by the domestic industry.
- v) There is significant difference between the prices offered by the domestic industry and foreign producers. Resultantly, imports have increased significantly over the injury period.
- w) The price undercutting has prevented the domestic industry from raising prices to the extent of cost increases. Price suppression has led to decline in profits of the domestic industry
- x) Growth of the domestic industry has become negative in respect of a number of price parameters in the proposed POI, which is due to subsidized imports in the country.
- y) Chinese company Tsingshan has invested heavily in a plant with mammoth capacity (much more than the demand in Indonesia).
- z) The market share of imports from subject country has increased
- aa) The rate of increase in imports is also high. Imports from subject country have increased by around 700 times since the base year. It is likely that the imports will increase further in the future.
- bb) The Tsingshan group alone has set up a plant with 3 million tons capacity. Tsingshan group has made this massive investment, having regard to global market. The huge capacities coming up in Indonesia are primarily targeted at other markets as the consumption of stainless steel in Indonesia is extremely low and is likely to further disturb the global trade balance
- cc) The major centres of stainless-steel consumption are China, EU, Japan, Korea and USA and these countries are already riddled with stagnant demand & excess production and surplus capacity which leaves very little space for absorbing additional volumes.
- dd) Comparison of selling price with landed price of import shows that the imports are undercutting the prices of the domestic industry. These low-priced imports are leading to price suppression in the market. Thus, imports are likely to increase further in case anti subsidy measures are not imposed.
- ee) Landed value of imports are at a price much lower than the selling price and cost of sales of the Domestic Industry. The producers from subject country are finding the Indian market quite attractive in terms of prices. Imports are entering at prices that are having a significant suppressing effect on domestic prices and would likely increase demand for further imports. India is not only the second largest producer & consumer of stainless steel but is also the only market where stainless-steel consumption is growing at a CAGR of 9-10% per annum. As against a global per capita stainless-steel consumption of 6 kgs, the figure of per capita consumption in India is only 2kgs, which clearly indicates that growth is expected to continue in the same trajectory. This makes India a very obvious target for the stainless-steel capacities set up in Indonesia

## G.2. Examination by the Authority

207. The submissions made by the interested parties have been analysed by the Authority to examine the injury to the domestic industry on account of subsidized imports from the subject country.

208. Rule 13 of the Rules deals with the principles governing the determination of injury which is as follows:

*“13. Determination of injury.-*

*(1) In the case of imports from specified countries, the designated authority shall give a further finding that the import of such article into India causes or threatens material injury to any industry established in India, or materially retards the establishment of an industry in India.*

*(2) Except when a finding of injury is made under sub-rule (3), the designated authority shall determine the injury, threat of injury, material retardation to the establishment of an industry and the casual link between the subsidized import and the injury, taking into account inter alia, the principle laid down in Annexure I to the rule.*

*(3) The designated authority may, in exceptional cases, give a finding as to the existence of injury even where a substantial portion of the domestic industry is not injured if –*

*(i) there is a concentration of subsidized imports into an isolated market, and*

*(ii) the subsidized imports are causing injury to the producers of almost all of the production within such market.”*

## H. Volume Effect of subsidized imports and Impact on domestic Industry

### (i) Assessment of Demand

209. Demand or apparent consumption of the product concerned in India is defined as the sum of domestic sales of Indian producers and imports from all other countries. It is noted that the product under consideration is being imported into India in cold and hot rolled conditions. Some producers of cold rolled products procure hot rolled either from the domestic market or from imports. Therefore, sales of these producers have not been counted to determine consumption of the product under consideration in India in order to avoid double accounting of production. It is seen that demand has increased over the injury period and POI. The demand so assessed is as follows:

Particulars	UOM	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Subject Country Imports	MT	93	4,024	8,601	76,102
Trend	Index	100	4,327	9,248	81,830
Country attracting CVD (China)	MT	235,949	241,703	152,821	62,705
Trend	Index	100	100	102	65
Countries attracting ADD	MT	39,435	30,839	34,829	59,232
Trend	Index	100	78	88	150
Countries under ongoing ADD Investigation (except Indonesia and China)	MT	209,705	185,680	243,335	243,216
Trend	Index	100	89	116	116

Particulars	UOM	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Other Countries	MT	9,637	6,184	9,651	158
Trend	Index	100	64	100	2
Domestic sales by DI	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	107	131	133
Domestic sales by other Indian Producers	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	101	110	110
Total Demand	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	102	114	115

It is noted that the demand of the subject goods follows increasing trend throughout the injury period.

**(ii) Imports**

210. With regard to volume of the subject imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in subsidized imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India.

211. The Authority notes that the volume of subject imports from the subject country has increased very significantly in POI as compared to previous years, as is obvious from the table below:

Particulars	UOM	2015-16	2016-17	2017-18	POI
<b>Import Volume</b>					
Subject Country-Indonesia	MT	93	4,024	8,601	76,102
Country attracting CVD(China)	MT	235,949	241,703	152,821	62,705
Countries attracting ADD	MT	39,435	30,839	34,829	59,232
Countries under ongoing ADD Investigation (except Indonesia and China)	MT	209,705	185,680	243,335	243,216
Other Countries	MT	9,637	6,184	9,651	158
Total	MT	494,819	468,429	449,237	441,412
<b>Share in Imports</b>					
Subject Country-Indonesia	%	0%	1%	2%	17%
	Range	0%	0-10%	0-10%	15-25%
Country attracting CVD(China)	%	48%	52%	34%	14%
	Range	45-55%	50-60%	30-40%	10-20%
Countries attracting ADD	%	8%	7%	8%	13%
	Range	5-15%	5-15%	5-15%	10-20%



Countries under ongoing ADD investigation (except Indonesia and China)	%	42%	40%	54%	55%
	Range	40-50%	35-45%	50-60%	50-60%
Other Countries	%	2%	1%	2%	0%
	Range	0-10%	0-10%	0-10%	0-10%
<b>Total</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

212. Imports from Indonesia increased from 93 MT in the year 2015-16 to 76,102 MT in the POI. The Authority observed that the trend of import in relation to production and consumption in India follows the same trend as imports in absolute terms. The imports in relation to production and consumption in India has increased significantly in POI as compared to previous years.

Particulars	UOM	2015-16	2016-17	2017-18	POI
<b>Subject Country Imports in relation to</b>					
Indian Production	%	***	***	***	***
	Range	0%	0-10%	0-10%	0-10%
Consumption	%	***	***	***	***
	Range	0%	0-10%	0-10%	0-10%
Total imports	%	***	***	***	***
	Range	0%	0-10%	0-10%	15-20%

213. Share of subject imports in total domestic production increased from 0% to 0-10% and share of imports in total consumption increased from 0% to 0-10%.

**(iii) Market Share**

Particulars	UOM	2015-16	2016-17	2017-18	POI
<b>Share in Demand</b>					
Subject Country-Indonesia	%	0%	0%	0%	3%
Country attracting CVD(China)	%	10%	10%	6%	2%
Countries attracting ADD	%	2%	1%	1%	2%
Countries under ongoing ADD investigation (except Indonesia and China)	%	9%	8%	9%	9%
Other Countries	%	0%	0%	0%	0%
DI domestic Sales	%	***	***	***	***
	Index	35-45%	40-50%	45-55%	45-55%
Other Indian Producers	%	***	***	***	***
	Index	35-45%	35-45%	35-45%	35-45%
Total Demand	%	100%	100%	100%	100%

214. It is seen that the market share of imports from the subject country was almost NIL in the base year and the same has increased to 0-10% during POI. The market share of domestic industry has also increased during POI.

### **I. Price effect of subject imports and impact on domestic industry**

215. With regard to the effect of subsidized imports on prices, it is required to be examined whether there has been a significant price undercutting by the subsidized imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such subsidized imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the purpose of this analysis, the weighted average cost of production (COP), weighted average Net Sales Realization (NSR) of the domestic industry have been compared with the landed price of imports from the subject country.

#### **(i) Price Undercutting**

216. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, the price undercutting has been worked out by comparing the landed price of imports with the selling price of the domestic industry during the injury period. The price undercutting has been determined for the POI separately for each PCN produced by the domestic industry and thereafter for the product under consideration as a whole.

Particulars	UOM	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Import Volume from subject country	MT	93	4,024	8,601	76,102
Trend	Index	100	4326	9254	81,830
Landed price of imports	Rs/MT	20,635	100,572	103,938	137,996
Trend	Index	100	487	503	668
Net Sales Realization	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	109	118	149
Price undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	10	16	12
Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting Range	%	380-390%	5-15%	10-20%	5 -15%

217. The Authority notes that the landed prices of the subject goods were below the selling price of the domestic industry showing price undercutting being caused by the subsidized products from the subject country during the injury investigation period including the POI.

#### **(ii) Price Underselling/ Injury Margin**

218. The Authority has worked out the non-injurious prices of the subject goods and compared the same with the landed value of the imported goods to arrive at the extent of price underselling. The price underselling/ injury margin has been determined separately for each PCN and thereafter for the product under consideration as a whole.

219. It is noted from the table below that the price underselling/ injury margin is positive, indicating that the imports have entered the market at injurious prices.

220. The injury margin for cooperative producers/exporters and others are evaluated as under:-

Producer	Non-Injurious Price (USD/MT)	Landed Price (USD/MT)	Injury Margin (USD/MT)	Injury Margin %	Injury Margin Range
PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry	***	***	***	***	10-30%
PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel	***	***	***	***	10-30%
PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy	***	***	***	***	10-30%
PT IMR ARC Steel	***	***	***	***	10-30%
Others	***	***	***	***	10-30%

### **(iii) Price Suppression and Depression**

221. In order to determine whether the subsidized imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority considered the changes in the costs and prices over the injury period. The position is shown in the table below:

Particulars	UOM	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	99	104	116
Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	118	149
Landed Price	Rs/MT	20,635	100,572	103,938	137,996
Trend	Indexed	100	487	504	669

222. From the above table, it is clear that the landed value of imports from the subject country have shown an upward trend in injury period as compared to the previous years. The Authority further

notes that cost of sales and the selling price of the domestic industry has increased during the POI as compared to the base year.

## **II. Economic Parameters relating to the Domestic Industry**

223. The Rules require that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the subsidized imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Accordingly, performance of the domestic industry has been examined over the injury period.

### **(i) Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales**

224. Position of the domestic industry over the injury period with regard to Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales was as follows:

Particulars	UOM	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Capacity	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	100	100	100
Production	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	112	127	125
Capacity Utilization	%	***	***	***	***
Trend	Index	100	111	126	125
Sales Volume Total	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	112	130	126

225. The Authority notes that-

- The capacity with the domestic industry has remained the same over the injury period.
- The production, sales of the domestic industry and capacity utilisation have increased throughout the injury period with marginal decline in POI.

### **(ii) Profitability, return on investment and cash profits**

226. Position of the domestic industry over the injury period with regard to profitability, ROI and cash profit are as follows:

Particulars	UOM	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	99	104	116

Particulars	UOM	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	118	129
Profit	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	-100	-19	9	-4
Cash Profits	Rs Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	-100	19	73	47
PBIT	Rs Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	-100	76	133	107
Return on Investment	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	-100	82	138	120

227. From the above information, the Authority notes that:

- The profits of the domestic industry increased in 2017-18, but it turned into losses in the POI.
- The cash profits, profit before interest & tax and return on investments have followed the same trend as that of profits. Cash profits, profit before interest & tax and return on investments increased in 2017-18, but declined thereafter in the POI.

(iii) Market share

228. Position of the domestic industry over the injury period with regard to market share in demand are as follows:

Particulars	UOM	2015-16	2016-17	2017-18	POI
<b>Market Share in Demand</b>					
Subject Country-Indonesia	%	0%	0%	0%	3%
Country attracting CVD(China)	%	10%	10%	6%	2%
Countries attracting ADD	%	2%	1%	1%	2%
Countries under ongoing ADD Investigation (except Indonesia and China)	%	9%	8%	9%	9%
Other Countries	%	0%	0%	0%	0%
DI domestic Sales	%	35-45%	40-50%	45-55%	45-55%
Other Indian Producers	%	35-45%	35-45%	35-45%	35-45%
Total Demand	%	100%	100%	100%	100%

229. The market share of subject imports has increased during the POI as compared to the previous years.

(iv) Employment, Wages and Productivity

Particulars	UOM	2015-16	2016-17	2017-18	POI
No of Employees	Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	102	107	107
Salaries & Wages	Rs Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	111	162	157
Salaries & Wages per Unit	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	99	128	125
Productivity Per Employee	MT/No	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	119	117
Productivity Per Day	MT/Day	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	112	127	125

230. Salaries & wages per unit and productivity per employee and productivity per day has marginally declined during POI as compared to previous year.

(v) Inventories

231. Inventories with the domestic industry have declined in the POI.

Particulars	UOM	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Inventory	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	107	97	83

(vi) Ability to raise capital investment

232. The Petitioner has submitted that ability to raise fresh investment are taken considering present and potential demand for the product under consideration. Long term viability of the product under consideration is dependent upon strong profitable business, which is impacted due to subject imports.

**III. Causal link**

233. The Authority has examined whether other known factors listed below could have caused injury to the domestic industry:

**a. Volume and prices of imports from third countries**

234. The imports from other countries are either attracting anti-dumping duty or under antidumping investigation or are at higher prices.

**b. Contraction of demand and changes in the pattern of consumption**

235. The Authority notes that there is no contraction of demand. On the contrary, overall demand for subject goods has shown improvement over the injury period. The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change. Changes in the pattern of consumption could not have contributed to the injury to the domestic industry.

**c. Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers**

236. There is no known trade restrictive practice which could have contributed to the injury to the domestic industry.

**d. Developments in technology**

237. None of the interested parties has furnished any evidence to demonstrate any change in the technology that could have caused injury to the domestic industry.

**e. Export performance of the domestic industry**

238. The injury information has been considered separately for domestic and exports, to the extent the same could be segregated.

**f. Performance of other products being produced and sold by the domestic industry**

239. The Authority has considered data only in relation to the product under consideration.

**IV. Conclusion on Causal Link**

240. The Authority notes as under:

- a) Subsidized imports from the subject country are coming into India in substantial volumes during the POI.
- b) Imports are undercutting the prices of the Domestic Industry during the injury period.
- c) Performance of the domestic industry has deteriorated during POI in terms of profits and ROI. Cash profits, profit before interest & tax and return on investments increased in 2017-18, however declined in the POI.

241. The Authority therefore provisionally holds that there is causal link between the subsidization of the subject goods and the injury suffered by the domestic industry.

**V. Threat of Material Injury**

242. The provisions relating to threat of material injury are provided in para 3 of Annexure I of Subsidy Rules which provide as follows:

*3. A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility. The change in circumstances which would create a situation in which the subsidy would cause injury must be clearly foreseen and imminent. In making a determination regarding the existence of a threat of a material injury, the designated authority shall consider, inter alia, such factors as:*

- i. nature of the subsidy or subsidies in question and the trade effects likely to arise therefrom;*
- ii. a significant rate of increase of subsidized imports into the domestic market indicating the likelihood of substantially increased importation;*
- iii. sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased subsidized exports to Indian market, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;*
- iv. whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further Imports; and*
- v. Inventories of the product being investigated.*

243. With respect to threat of material injury, the Authority notes as under:

- a) There is significant difference between the prices offered by the domestic industry and Foreign Producers. There are countervailable subsidies which are being provided to the producers of the product under consideration in Indonesia. The subsidy margins for all of the co-operating producers/exporters from Indonesia are above de-minimis.
- b) The Authority has examined the capacity details of the co-operative producers/exporters from the subject country and it is noted that no significant capacity has been added by any of the co-operative producers/exporters.
- c) Imported product is undercutting the prices of the domestic industry. Resultantly, the domestic industry has been preventing from charging fair prices.
- d) Authority has examined the inventory of the co-operative producers/exporters from the subject country and it is noted that none of them hold any significant inventory of the subject goods.

#### **H. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES**

244. The Authority notes that the purpose of imposition of countervailing duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of subsidization so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the Country. Imposition of countervailing duty would not prohibit imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.
245. It is recognized that the imposition of countervailing duty might affect the cost of the subject goods. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of the countervailing measures, particularly if the levy of the provisional countervailing duty is restricted to an amount necessary to redress the injury caused to the domestic industry by the imports of subsidized subject goods. On the contrary, imposition of countervailing measures would remove the unfair advantages gained by subsidization and create level playing field.

#### **I. CONCLUSION & RECOMMENDATIONS**

246. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein; and considering the facts available on record, the Authority provisionally concludes that:
- a) The product under consideration has been exported to India from the subject country at subsidized prices.
  - b) The domestic industry has suffered material injury due to subsidization of the product under consideration.
  - c) The material injury has been caused by the subsidized imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.
247. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties including the Government of Indonesia and adequate opportunity was given to exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of subsidization, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into subsidization, injury and causal links in terms of the Rules laid down and having established positive subsidy margin as well as material injury to the domestic industry caused by such subsidized imports, the Authority is of the view that imposition of provisional countervailing duty is required to offset subsidization and injury, pending completion of the investigation. Therefore, the Authority considers it necessary to recommend imposition of provisional countervailing duty on the imports of the subject goods from Indonesia in the form and manner described hereunder.



248. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of provisional countervailing duty equal to the lesser of margin of subsidy and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of provisional countervailing duty on the imports of subject goods, originating in or exported from the subject country, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, equal to the amount mentioned in Col. 7 of the duty table appended below. The landed value of imports for this purpose shall be assessable value as determined by the Customs under Customs Act, 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

#### **DUTY TABLE**

S. No.	Heading/ Subheading	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Duty amount as a % of CIF value
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Flat Products of Stainless Steel	7219 and 7220	Indonesia	Any country including Indonesia	PT Indonesia Guang Ching Nikel and Stainless Steel Industry	22.31%
2.	-do-	-do-	Indonesia	Any country including Indonesia	PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel	22.31%
3.	-do-	-do-	Indonesia	Any country including Indonesia	PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy	22.31%
4.	-do-	-do-	Indonesia	Any country including Indonesia	PT IMR ARC Steel	22.65%
5.	-do-	-do-	Indonesia	Any country including Indonesia	Any producer other than producers mentioned in S. Nos. 1 to 4 above	24.83%
6.	-do-	-do-	Any country other than Indonesia	Indonesia	Any	24.83%

#### **J. FURTHER PROCEDURE**

249. The procedure as below would be followed subsequent to notifying the preliminary findings:

- i. The Authority invites comments on these provisional findings from all the interested parties and the same, considered relevant by the Authority, would be considered in the final finding.
- ii. Domestic Industry, exporters, importers and other interested parties known to be concerned are being addressed separately by the Authority, who may make their views known, within forty days from the date of the publication of these preliminary findings.
- iii. Any other interested party may also make its views known within forty days from the date of publication of these findings.
- iv. The Authority would conduct oral hearing in terms of rule 7(6) to give an opportunity to all interested parties to present their views relevant to the investigation. Issues and concerns raised during oral hearing will be examined in the final findings.
- v. The date of the oral hearing would be announced on the DGTR website (dgtr.gov.in).

- vi. The Authority would conduct further verification to the extent deemed necessary.
- vii. The Authority would disclose the essential facts as per the Rules before announcing the final findings.

B.B.SWAIN, Special Secy. and Designated Authority